हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शनिवार, दिनांक 14 मार्च, 2020 को माननीय अध्यक्ष,श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

14.03.2020/1100/बी.एस./डी.सी./-1

प्रश्न संख्याः 2756

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु (नदौन) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, इसमें जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजैक्ट है जिसके लिए हमारी कांग्रेस की सरकार के समय 1100-1200 करोड़ रुपए आया था, उसकी क्या स्थिति है? और जो 'शिवा' प्रोजैक्ट है, क्या इसमें ए.डी.बी. के द्वारा वित्त पोषण की बात की गई है और उसकी स्वीकृति मिल चुकी है? आपने जो हिमाचल प्रदेश के सात जिलों की बात की है और जिन जिलों के ब्लॉक्स को आपने सिलैक्ट किया है क्या उसमें पहले क्लस्टर के लिए पंचायतों को लेंगे या सभी ब्लोक्स को एक साथ शुरू किया जाएगा?

जल शक्ति मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के अनुसार हमारी दो परियोजनाएं है जिसमें एक परियोजना विश्व बैंक से संबंधित है और दूसरी एशियन डवलपमैंट से संबंधित है। मैं पहले शिवा प्रोजैक्ट से शुरू करूंगा, फिर विश्व बैंक परियोजना की तरफ आता हूं। जो शिवा प्रोजैक्ट है इससे पहले हमारे दो प्रोजैक्ट भारत सरकार के पास थे। भारत सरकार वित्त मंत्रालय और वित्त मन्त्रालय के डिपार्टमैंट ऑफ इकोनोमिक अफेयर के पास हमने दोनों प्रोजैक्ट भेजे। एक प्रोजैक्ट, जैसे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने पूरे देशवासियों और विशेष करके किसानों की आमदन को दोगुना करने के लिए जो सभी प्रदेश सरकारों से आवाह्न किया है उसके अनुसरण में माननीय मुख्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने यहां से अपना कन्सेप्ट नोट 4751 करोड़ रुपए का बना करके वित्त मंत्रालय के डी.ए. में प्रेशित किया और प्रेशित करने के साथ-साथ यह जो हमारा प्रोजैक्ट है यह डी.ए. की 85 सक्रिनिंग की जो बैठक है वह 17 जुलाई, 2018 को थी।

श्री डी.टी.द्वारा जारी...

जल शक्ति मन्त्री क्रमागत

जिसमें इसकी अप्रूवल दे दी गई। अप्रूवल देने के बाद इस प्राजैक्ट को रिक्विजिशन के लिए एशियन विकास बैंक के पास भेज दिया गया। एशियन विकास बैंक इस परियोजना के लिए धनराशि देगा। दूसरा, सब-ट्रोपिकल प्रोजैक्ट फॉर लॉ एंड मिड हिल एरियाज प्रोजैक्ट जो हिमाचल प्रदेश के सब-ट्रोपिकल एरियाज के लिए है। माननीय अध्यक्ष जी, आज तक जो प्रोजैक्ट हमें मिलते रहे, चाहे वह छोटा था या बड़ा प्रोजैक्ट, वह केवल और केवल ट्रोपिकल एरियाज यानी ऊपर के क्षेत्रों के लिए मिला। हिमचल प्रदेश का निचला एरिया प्रदेश का लगभग 70 प्रतिशत एरिया क्वर करता है वहां पर बागवानी नाम की अभी तक कोई शुरूआत नहीं हुई है। एक अन्य प्रोजेक्ट हमने उद्यान विभाग के माध्यम से भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय को और Department of Economic Affairs को यह भेजा और 14 जून, 2018 को हुई डी0ए0 की 84वीं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में इसे स्वीकृति दे दी गई और उन्होंने कहा की इस प्रोजेक्ट को भी हम एशियन विकास बैंक को वित्त पोषण के लिए भेज रहें हैं। जब दोनो प्रोजेक्ट एशियन विकास बैंक को गये और एशियन विकास बैंक की जो टीमें यहां पर आई, मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। इनकी टीम यहां आई। The Project was approved by DA, Ministry of Finance, Government of India in its 84th Screening Committee Meeting held on 14th June, 2018. हमारा प्रोजेक्ट डी0ए0 से एशियन विकास बैंक को 6 जुलाई, 2018 को गया। After that Mr. Sanath Renawala, Mission Leader of ADB Scope Finding and Consultation Mission visited Himachal Pradesh तथा वह 18 सितम्बर से लेकर 22 सितम्बर तक हिमाचल प्रदेश में रहे। उसके बाद फिर उन्होंने MMR सबमिट किया और ए0डी0बी0 के साथ इनकी कन्शलटेशन 3 अक्तुबर, 2018 को हुई। उसके बाद उसकी concurrence 8 अक्तुबर, 2018 को by the Government of Himachal Pradesh हुई।

प्रोजेक्ट डयूरेशन के लिए - यानी यह प्रोजोक्ट कितने वर्षों में पूरा होना है - पांच से सात साल का

14.03.2020/1105/DC/DT-2

समय इसमें रखा गया है। शुरूआत में हिमाचल प्रदेश के 28 ब्लॉकस इसमें शामिल किये जायेंगे। इसके पश्चात 6 दिसम्बर, 2018 से 16 दिसम्बर, 2018 तक ए0डी0बी0 का के कन्सलटेन्ट, श्री डेविड मेख ने इस प्रोजेक्ट को फाईनान्स करने के लिए कॉन्सेप्ट नोट दिया है। 29 नवम्बर, 2018 को ए0डी0बी0 के द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए एक Project Officer Appoint की गई जिनका नाम था Ms. Sunae Kim. A notification of Governing Council and Executive Committee of the H.P. SHIVA was issued by the State Government on 26, November, 2018. और एक Notification of PMU of SHIVA by the State Government 13, अक्तुबर, 2019 को हुई। माननीय अध्यक्ष जी, इसके उपरान्त मैं फरवरी, 2019 में जो ए0डी0बी0 का मिशन था वो आई0पी0एच0 का जो प्रोजेक्ट था जो किसानों की आमदनी को दोगुना करने का था, उसके लेकर भी और जो निचले क्षेत्र में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए था उसको लेकर कर भी हिमाचल प्रदेश में विधान सभा

श्री एन0जी0द्वारा जारी

14-03-2020/1110/एच.के.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या 2756 जारी.....

जल शक्ति मंत्री जारी.....

आई.पी.एच. का और बागवानी का प्रोजैक्ट, ये दोनों प्रोजैक्ट किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए हैं। दोनों प्रोजैक्ट एशियन डिवेलपमेंट बैंक (ए.डी.बी.) को दिए गए हैं।

उन्होंने हमें कहा कि दोनों प्रोजैक्टों को अलग-अलग न चला कर दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए। बागवानी के लिए भी सिंचाई की आवश्यकता होती ही है और आई.पी.एच. विभाग सिंचाई का काम करेगा व बागवानी का काम होर्टीकल्चर विभाग करेगा इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि इन दोनों प्रोजैक्टों को एक बना दिया जाए और फिर इसे 'शिवा' नाम दिया गया। उसके बाद इस प्रोजैक्ट का अगला काम फरवरी-मार्च, 2019 के उपरान्त शुरू हुआ। अध्यक्ष महोदय, यह फोरेन फंडिंग प्रोजैक्ट्स हैं और जब भी कोई फोरेन फंडिंग प्रोजैक्ट्स आते हैं तो वह हमारे मुताबिक काम नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि प्रदेश सरकार ने कहा कि आज आप पौधे ले आओ और कल उन्हें लगा दो, उनकी अपनी एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में उनका अपना टाइम टेबल होता है और उसके मुतबिक ही वे अपना सारा काम करते हैं। मैं माननीय सदन को इस बात से अवगत करवाना चाहता हूं कि जो हमारे 28 ब्लॉक लिए गए हैं वे जिला मण्डी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सिरमौर, सोलन के हैं और एक ब्लॉक जिला ऊना का भी है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रोजैक्ट के अंतर्गत 28 ब्लॉकों का चयन करने के बाद उन्होंने कहा कि हमने एक पायलट प्रोजैक्ट के रूप में हिमाचल प्रदेश में सब्टरॉपिकल एरिया के अंदर 17 कल्सटर चिन्हित किए हैं, मैं उनका ब्यौरा भी सभा पटल पर रखना चाहता हूं। उनमें बैजनाथ का सेहल और घरथोली, भभारणा का डैहण, सुलाह का लाहट, सदर बिलासपुर का मजेहड़, स्वारघाट का दुलैहड़, घुमारवीं का लंजटा और तलवाड़ा, दबरोटा, मण्डी का बिंगा और गमधाल, सन्धोल, मटोर, गोपालपुर, कांगड़ा का रिटलाहट, सुन्दरनगर का कल्होट, हमीरपुर बमसन का कैहडरू और सुजानपुर का बहलेट शामिल है।

14-03-2020/1110/एच.के.-एन.जी./2

पायलट प्रोजैक्ट में जो 17 कल्सटर लिए गए हैं उनमें प्रति कल्सटर 10 हैक्टर भूमि का चयन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, भूमि चयन की एक प्रकिया है जिसमें सबसे पहले यह देखा जाता है कि वहां के किसान 10 हैक्टर भूमि इकट्ठी करके बागवानी करना चाहता हैं

या नहीं और इन सभी 17 कल्सटरों में वहां के किसानों ने 10-10 हैक्टर भूमि पर बागवानी करने के लिए अपनी सहमती दी है। अध्यक्ष महोदय, जो कल्सटर चुने गए हैं

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी....

14/03/2020/1115/MS/HK/1

प्रश्न संख्याः 2756 क्रमागत----जल शक्ति मंत्री जारी---

उन कलस्टर्ज में, वहां की मिट्टी किस फल के लिए अच्छी है। ...(व्यवधान) आप लोग सुन लीजिए। मेरा काम आपको बताना है। ...(व्यवधान) वहां क्या सिंचाई की सुविधा है। ...(व्यवधान)जो वहां की सिंचाई की सुविधा है और वहां जो लोग तैयार हैं, उसमें देखेंगे कि वहां की भूमि किस फल के लिए तैयार है। उसके लिए जो 17 कलस्टर्ज हैं, उनमें से 7-8 कलस्टर्ज में पायलट प्रोजैक्ट के तहत एक छोटे से हिस्से में यानी एक-एक हैक्टेयर में वहां पर पौधरोपण किया गया है। जो पौधरोपण किया गया है, उसको अब जो हमारा शिवा प्रोजैक्ट है, ...(व्यवधान) सुनिये, मैं पैसे पर ही आ रहा हूं। पैसा जेब से निकालकर थोड़े ही आपकी जेब में डालना है। ...(व्यवधान) सुखविन्द्र जी, पहले बात सुननी चाहिए फिर आगे बात करनी चाहिए। अब मार्च और अप्रैल में जो 17 कलस्टर्ज हैं उनमें 10-10 हैक्टेयर के लिए 10 मिलियन डॉलर बारे मिशन ने कहा है कि वह स्वीकृत करने जा रहा है। उसके लिए अप्रैल और मई के महीने में मिशन आ रहा है और 10 मिलियन डॉलर की स्वीकृति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जैसे ही वह पैसा मिलता है; मैं मार्च और अप्रैल, 2020 की बात कर रहा हूं। जैसे ही वह पैसा मिलता है फिर जुलाई के महीने में जो हमारे 17 कलस्टर्ज हैं, उनमें फिर पूरी प्लांटेशन की जाएगी। उसके बाद फिर 3000 हैक्टेयर पर प्लांटेशन की जाएगी और फिर 10000 हैक्टेयर पर प्लांटेशन की जाएगी। यह 100 मिलियन डॉलर उसके बाद आएगा। ...(व्यवधान) मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जो आप लोगों की चिन्ता थी कि पैसा कहां से आएगा, इसमें मैं बता दूं कि फॉरेन फण्डिंग प्रोजैक्ट्स का अपना एक तरीका होता है और उसके हिसाब से ही फण्डिंग आती है। ...(व्यवधान) सुनिए, अभी कहां हुआ है? अभी तो शुरूआत हुई है।

अध्यक्ष जी, इन्होंने विश्व बैंक परियोजना की बात कही है। ...(व्यवधान)आप हल्ला डालते हैं और फिर हम पूरा जवाब न दें तो मुश्किल कर देते हो। अभी तो मैंने विश्व बैंक के

प्रोजैक्ट पर ही कहना है। ...(व्यवधान) मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज के बाद फॉरेन प्रोजैक्ट को लेकर शोर मत कीजिएगा।

14/03/2020/1115/MS/HK/2

अध्यक्षः माननीय सदस्य, बैठ जाइए। माननीय सदस्य क्या आप मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट है? इस प्रश्न पर चर्चा करते हुए 15 मिनट का समय हो गया है। माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से उत्तर दे दिया है। माननीय सदस्य, जो मंत्री जी ने उत्तर दिया है, उससे हटकर कुछ पूछिएगा।

श्री राकेश पठानिया(नूरपुर)ः अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल हटकर ही जानकारी लूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज आप देख रहे हैं कि मार्च महीने में क्या मौसम चल रहा है। यह जो सारा क्लाइमेट चेंज आ रहा है, this is a very serious concern we are facing. It is not because of SHIVA Project, Mukesh ji, it is because of you, जो आप लोगों ने कभी कुछ किया ही नहीं और जब होने लगा तो आपको परेशानी है। यह जो हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत प्रोजैक्ट आया था, क्या मंत्री जी बताएंगे कि इसमें सभी 12 जिले कवर्ड थे? क्या हमारे कांगड़ा का सब-ट्रॉपिकल एरिया भी उसमें कवर्ड था? जो उसमें ऑलरेडी पैसा आया हुआ था वह तो हमें मिला नहीं। हमने 9 कलस्टर बनाकर दिए थे और हम पहले साल से इनके पीछे पड़े हुए हैं। इसमें 7 कलस्टर नूरपुर के हैं और दो कलस्टर ज्वाली के हैं। इनकी पूरी स्कीम बनाकर हमने आपको सबमिट की हुई है। अभी तक मैं बार-बार विभाग से पूछ रहा हूं लेकिन डेढ़ साल से हमें कोई जवाब नहीं मिला कि एक कलस्टर की भी डी0पी0आर0 बनी है या नहीं बनी है। दूसरे, इसके अंदर जो फॉर्मूला एडॉप्ट किया गया; जो सुक्खु जी ने पूछा कि इसके अंदर जो इरीगेशन कम्पोनेंट है, उसमें आप फार्मर्ज को पैसा कैसे देंगे?

जारी एस0एस0 द्वारा----

14.03.2020/1120/SS-YK/1

प्रश्न संख्याः 2756 क्रमागत

श्री राकेश पठानिया क्रमागत :

क्या वहां पर फार्मर्ज़ की सब-कमेटी बनायेंगे या डायरैक्ट उसकी फंडिंग होगी? यह एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है जो क्लीयर होना चाहिए।

तीसरा, यह जो आपने शिवा प्रोजैक्ट बनाया अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा आम, लीची, नीम्बू, किन्नू इत्यादि की बागवानी हमारे नूरपुर सब-डिवीजन में होती है। नूरपुर सब-डिवीजन में चार विधान सभा क्षेत्र आते हैं। यह जो आपने शिवा प्रोजैक्ट लिया है उसमें आपने नूरपुर सब-डिवीजन को हाथ नहीं लगाया। हमें तो आपके पास दो साल तक होर्टिकल्चर मिशन के लिए रोते हुए हो गए कि न हमें उसमें कुछ मिला और न हमें शिवा प्रोजैक्ट में कुछ मिला तो हमारी बारी कब आयेगी?

जल शक्ति मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने विश्व बैंक की परियोजना के बारे में जानना चाहा है। यह परियोजना 2016 में आई थी जब हमारे विपक्ष के भाई सत्तापक्ष में होते थे। 2016, 2017 और 2018 तक जो 1134 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट है इन माननीय सदस्यों ने इस प्रोजैक्ट के अंदर ढाई साल में 1134 करोड़ रुपये में से केवलमात्र 22.57 करोड़ रुपये खर्च किए। जब किसी प्रोजैक्ट की डी0पी0आर0 बनती है, मेजर प्रोजैक्ट बनता है जैसे मैंने शिवा प्रोजैक्ट के लिए कहा है उस प्रकार की एक्सरसाइज होनी चाहिए थी। लेकिन उस एक्सरसाइज में कुछ कमियां रही हैं। इस विश्व बैंक परियोजना में जो कमियां थीं, हमने उसमें सुधार करने की आवश्यकता समझी तथा इसे देखने हुए हमने शिवा प्रोजैक्ट में सुधार भी किया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं और इनके प्रश्न का उत्तर दूंगा। जब हमारी सरकार बनी तो सरकार बनने के उपरांत हमने इस 22.57 करोड़ रुपये को जो आने वाला 31 मार्च है उसमें हमने वैसे 150 से 160 करोड़ रुपये का टारगेट रखा है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपके (विपक्ष के) ढाई साल और हमारे दो साल में उसमें कितना अंतर आया है।

14.03.2020/1120/SS-YK/2

दूसरा जो माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी जानना चाहते हैं क्योंकि पहले 2016 में विश्व बैंक परियोजना आई थी उस वक्त सब-ट्रोपिकल एरिया भी लिया गया था। जो निचला क्षेत्र था उसको भी शामिल किया गया था। जब उसको शामिल किया गया तो उसमें ज्यादा फोकस सेब की तरफ रहा। नीचे के क्षेत्र की तरफ चाहे उसमें आम, लीची, संतरा,

मौसम्मी या किन्नू इत्यादि हैं उनकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया। इनका कहना ठीक है कि नूरपुर का जो सब-डिवीजन है या कांगड़ा का एरिया है, वह हमारे सिट्रस फ्रूट्स के लिए सबसे बैस्ट एरिया है। लेकिन जब दूसरा प्रोजैक्ट आ गया तो कहीं ओवरलैपिंग न हो, उससे बचने के लिए फिर हमने चिन्हित कर दिया कि 28 ब्लॉक शिवा प्रोजैक्ट में निचले क्षेत्र के ले जाएं और ऊपर का सारा-का-सारा एरिया वर्ल्ड बैंक प्रोजैक्ट के लिए छोड़ दिया गया। आदरणीय पठानिया जी मुझे दो-तीन बार मिले। इन्होंने इस माननीय सदन में भी इस बात को उठाया कि नूरपुर का क्षेत्र वर्ल्ड बैंक परियोजना से बाहर क्यों किया गया। इनके कहने पर हमने इनके क्षेत्र को वर्ल्ड बैंक में रखा। क्योंकि किसी भी सदस्य को विश्वास नहीं था कि शिवा प्रोजैक्ट आयेगा या नहीं आयेगा, होगा या नहीं होगा। जैसे कि बहुत शंकाएं हमारे मित्रों को अभी भी हैं वैसे ही इनको भी शंका थी कि ऐसा न हो कि वर्ल्ड बैंक आया हुआ प्रोजैक्ट है उससे हमें बाहर कर दिया जाए और दूसरे प्रोजैक्ट में अगर हम नहीं आए तो हम वैसे ही रह जायेंगे। मैं इनके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। इसलिए हमने इनके नूरपुर के क्षेत्र को विश्व बैंक में रहने दिया। **मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा, जो वर्ल्ड बैंक प्रोजैक्ट है उसमें नूरपुर का क्षेत्र रखा गया है..**

जारी श्रीमती के0एस0

14.03.2020/1125/केएस/वाईके/1

प्रश्न संख्याः 2756 जारी..

जल शक्ति मंत्री जारी---

ओर जो भी उसमें काम होना है, उसको टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी। क्योंकि थोड़ा सा एरिया हमने सब-ट्रॉपिकल रखा हुआ है, मैं इनको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्षः राकेश सिंघा जी, माननीय मंत्री जी ने विस्तार में उत्तर दे दिया है। ...(व्यवधान)

जल शक्ति मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि सवा सौ करोड़ रुपये खर्च करने पर हम क्या संतुष्ट हैं, हमने जो दो साल में किया है, हम उससे संतुष्ट हैं लेकिन मैं आपको इस बात का भी विश्वास दिलाता हूं कि यह जो विश्व बैंक परियोजना है, हम और हमारा पूरा विभाग लगातार काम कर रहे हैं। राकेश पठानिया जी ने एक बात कही थी कि सिंचाई की क्या व्यवस्था होगी, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार के समय ऐसी स्थिति थी कि ढाई साल तक सिंचाई की व्यवस्था पर कोई काम नहीं किया गया था।

अध्यक्षः मंत्री जी, आपने काफी विस्तार से उत्तर दे दिया है। मुझे लगता है इससे सभी संतुष्ट हैं। ...(व्यवधान) सिंघा साहब, एक ही प्रश्न पर आधा घंटा हो गया है। ठीक है, आप प्रश्न करिए लेकिन ज्यादा लम्बी बात न हो क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं।

श्री राकेश सिंघाः अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। यह न सेब का प्रश्न है, न नींबू का प्रश्न है, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जो import of the plants की बेसिक कंडिशन है, PQ फॉर्म की 12 कंडिशन्ज़ हमने फुलफिल की है या नहीं? दूसरे, जो इन्सपैक्टिंग अथॉरिटी है, उसने प्लांट्स आने के एक महीने बाद इन्सपैक्ट किया या नहीं? तीसरे,उसकी इन्सपैक्शन का रैगुलर इन्टरवल क्या था, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं और अगर माननीय मंत्री जी आज इसका जवाब नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं लेकिन यह उत्तर बाद में आना चाहिए।

14.03.2020/1125/केएस/वाईके/2

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, क्या आपके पास यह उत्तर हैं या इनको बाद में लिखित रूप में दे देंगे?

जल शक्ति मंत्री : अध्यक्ष महोदय , जैसा माननीय सदस्य चाहें मैं उत्तर दे दूंगा लेकिन इसका उत्तर देने में 15 मिनट का समय लगेगा।

अध्यक्ष : राकेश सिंघा जी, माननीय मंत्री जी आपको बाद में विस्तार में जानकारी दे देंगे।

4.03.2020/1125/केएस/वाईके/3

प्रश्न संख्या 2757

श्री राम लाल ठाकुर (श्री नैना देवी जी) : अनुपस्थित

14.03.2020/1125/केएस/वाईके/4

प्रश्न संख्या : 2758

श्री राजेन्द्र राणाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न का जवाब तो बहुत ही विस्तार से आया है परन्तु इसमें कुछ जानकारियां छूट भी गई हैं। जो धौलासिद्ध का प्रोजैक्ट है, जो कि 66 मैगावाट का लगाया जा रहा है, उत्तर में दिखाया गया है कि इसकी 668 करोड़ रुपये लागत आएगी और जो भूमि दिखाई गई है, जो जवाब आया है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा होमवर्क तो मैं करके आया हूं। जो इसमें जवाब आया है कि टोटल लैंड लगभग 7200 कनाल है और इफैक्ट कर रही है 338 हैक्टेयर जिसमें कि वन भूमि 52 हैक्टेयर और सरकारी भूमि 28 हैक्टेयर है। निजी भूमि 282 हैक्टेयर है और इसमें कुल 18 पंचायतें हैं जिनमें से 10 हमीरपुर की और 8 कांगड़ा की अफैक्ट कर रही हैं। इसके अलावा सुजानपुर की 9 पंचायतें, जयसिंहपुर की 7 , ज्वालामुखी की 1 और नदौन की भी 1 पंचायत है। विभागीय उत्तर में बताया गया है कि कुल 427 परिवार प्रभावित हो रहे हैं और 4 परिवार विस्थापित हो रहे हैं जबकि हमने इस सम्बन्ध में जो डिटेल इन्फोर्मेशन ली है, उसके अनुसार 713 परिवार इफैक्ट हो रहे हैं। लगभग 440 परिवार हमीरपुर के हैं और कांगड़ा के 273 हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

14.03.2020/1130/av-ag/1

प्रश्न संख्या : 2758----- क्रमागत

श्री राजेन्द्र राणा----- जारी

इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठ रहे हैं कि वहां जिन प्राइवेट लैंड लॉड्र्ज की ज़मीन खरीदी जा रही है तो उसके लिए किसान कई बार एजिटेशन भी कर चुके हैं। वे किसान प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिल चुके हैं मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। धौलासिद्ध में एस0जे0वी0एन0एल0 के माध्यम से प्रोजैक्ट लगाया जा रहा है। श्री शिव देव, रिटायर्ड एच0ए0एस0 ऑफिसर जो कि पहले एस0डी0एम0(सुजानपुर) रह चुके हैं; उनको वहां पर एडवाइजर लगाया गया है क्योंकि उनको वहां की जानकारी थी। वहां पर जो ज़मीनें खरीदी जा रही हैं उसकी रजिस्ट्रेशन का काम 5.00 बजे के बाद शुरू होता है। वहां के किसानों को डराया-धमकाया जा रहा है तथा यह कहा जा रहा है कि रैवन्यू एक्ट-1884 के तहत ज़मीन खरीदी जायेगी। जबकि वहां पर जिन किसानों ने एजिटेशन किया हुआ है उनका यह कहना है कि आप हमारी ज़मीन लीजिए, वहां के किसानों को यह आपत्ति नहीं है कि वहां पर प्रोजैक्ट न लगे। लेकिन वहां जो ज़मीन ली जा रही है उसका कम-से-कम पहले अधिग्रहण किया जाए। यह आपके घोषणा पत्र में भी है कि किसानों को कम-से-कम फैक्टर-ii के तहत मुआवज़ा देंगे। इसमें एक कमेटी बनाई गई थी जिसका इसमें ज़िक्र नहीं है। इसमें एस0डी0एम0 की अध्यक्षता वाली एक अलग कमेटी का ज़िक्र किया गया है। इसमें एक कमेटी थी जिसके अध्यक्ष (चेयरमैन, हिमुडा) तथा डी0सी0 कांगड़ा और डी0सी0 हमीरपुर मैम्बर थे तथा यह तीन लोगों की कमेटी थी। मगर आज तक इस कमेटी ने किसी की शिकायत नहीं सुनी और न ही इस कमेटी की कोई मीटिंग हुई। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसान की ज़मीन को फैक्टर-ii के तहत एक्वायर करके उनको सही मुआवजा दिलाने का प्रयास करेगी?

14.03.2020/1130/av-ag/1

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में इन्होंने उत्तर देने की भी खुद कोशिश की है। मुझे नहीं मालूम कि आपके पास जो जानकारी है यह किस सूत्र से है तथा यह सही भी है या नहीं; यह विषय अलग तरह का है। लेकिन हमने इस प्रश्न के उत्तर में फैक्चुअल पोजिशन दी है। हमारे पास जो एस0जे0वी0एन0एल0 से सूचना प्राप्त हुई है हम तो उसी के मुताबिक उत्तर दे पायेंगे। माननीय सदस्य ने जो किसानों को डराने-धमकाने वाली बात कही है तो हमारे सामने अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है। मैं यहां पर फैक्चुअल पोजिशन को स्पष्ट कर देता हूं। इस प्रोजैक्ट के तहत जिला कांगड़ा और जिला हमीरपुर की ज़मीन आ रही है। इस प्रोजैक्ट के लिए जिला हमीरपुर के अंतर्गत 189 हैक्टेयर तथा जिला कांगड़ा के तहत 142 हैक्टेयर ज़मीन एक्वायर की जायेगी जो कि कुल मिलाकर 331 हैक्टेयर बनती है। यह प्रोजैक्ट 66 मैगावाट का है तथा इसकी अनुमानित लागत 668 करोड़ रुपये है।

टी सी द्वारा जारी

13.03.2020/1135/TCV/AG-1

प्रश्न संख्या : 2758 क्रमागत

मुख्य मंत्री ... जारी

मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि इस परियोजना में कुल 427 परिवार प्रभावित व 4 परिवार विस्थापित होंगे। इन परिवारों को दी जाने वाली राशि का निर्धारण अभी नहीं हुआ है तथा राशि का नियमानुसार निर्धारण होने के उपरान्त मुआवज़ा प्रदान कर दिया जाएगा। इस प्रोजैक्ट की कहानी बहुत लम्बी है। यह हमारी प्राथमिकता है कि जो लोग विस्थापित होंगे या जिन लोगों की ज़मीन जाएगी उनको जायज़ मुआवज़ा देने में कोई कोताही नहीं की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकार एवं हिमाचल सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में एक मिनी रत्न श्रेणी के शेड्यूल-ए, सी.पी.एस.ई0 के तौर पर एस0जे0वी0एन0 की स्थापना 24 मई, 1988 को हुई थी। एस0जे0वी0एन0लि0 ने विस्तृत सर्वेक्षण एवं जांच के बाद 66 मैगावाट क्षमता की प्रस्तावित डी.पी.आर. तैयार की। इस प्रकिया में धौलासिद्ध मंदिर के पास 50 मीटर ऊंचे डैम का निमार्ण प्रस्तावित है। परियोजना की लागत आई0डी0सी0 तथा एफ0सी0 सहित 4.47 रुपये प्रति यूनिट के लैवेलाइज्ड टैरिफ पर नवम्बर, 2010 में 497.67 करोड़ रुपये आंकी गई। जिसमें भूमि अधिग्रहण के लिए 10.01 करोड़ रुपये का प्रावधान था। डी0पी0आर को ऊर्जा निदेशालय द्वारा 25.06.2011 टैक्नो-इक्नोमिक क्लीयरैंस प्रदान की जिसकी वैधता ऊर्जा निदेशालय द्वारा दिनांक 11.05.2018 से अगस्त, 2020 तक बढ़ाई गई। तत्पश्चात भूमि अधिग्रहण की लागत में बढ़ौतरी होने के कारण परियोजना के अनुमानित लागत मई, 2016 के मूल्य स्तर पर 870.81 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। जिसके बाद दिसम्बर, 2017 के मूल्य स्तर पर डैट इक्विटी रेशो 70:30 के स्थान

13.03.2020/1135/TCV/AG-2

पर 80:20 करने के उपरांत 810.43 करोड़ रुपये लाया गया जिससे इस परियोजना का लैवेलाइज्ड टैरिफ 7.5 रुपये प्रति यूनिट के स्थान पर 6.92 प्रति यूनिट लाया जा सके। एस0जे0वी0एन0लि0 द्वारा इस परियोजना की 810.43 करोड़ रुपये की कुल लागत की निवेशक मंजूरी के लिए पी0आई0वी0 के समक्ष प्रस्ताव प्रेषित किया। विद्युत मंत्रालय द्वारा परियोजना का टैरिफ अव्यावहारिक पाया गया और अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया। परियोजना के लिए अधिकृत की जाने वाली निजी भूमि की लागत सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में सर्कल रेट में संशोधन के कारण काफी हद तक बढ़ गई थी।

श्री आर0के0एस0 द्वारा ... जारी

14.03.2020/1140/RKS/AS-1

प्रश्न संख्या:2758...जारी

मुख्य मंत्री... जारी

इसके बाद नई भूमि अधिग्रहण अधिनियम-2013 लागू होने के उपरांत परियोजना को व्यावहारिक बनाने और निजी भूमि की लागत को कम करने के लिए प्रबंधन ने दिनांक 18.04.2016 को भूमि मालिकों के साथ निजी वार्ता के लिए जाने का फैसला किया। भूमि की लागत को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने उपमंडल स्तर पर नेनोसिएशन कमेटी का गठन दिनांक 09.06.2016 को जारी अधिसूचना द्वारा किया गया। जमीन की कोस्ट बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण यह प्रोजैक्ट वाइबल नहीं पाया गया था। लेकिन भूमि मालिकों के साथ नेगोशिएशन होने के उपरांत भूमि की कीमत 40 करोड़ रुपये और इन रियायतों को प्रदान किए जाने के बाद धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना का लेवलाइज्ड टैरिफ 4.53 रुपये प्रति यूनिट तथा संभावित लागत 667.98 करोड़ रुपये आंकी गई है। नई शर्तों तथा उपरोक्त रियायतों के साथ धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निष्पादन हेतु दिनांक 25.09.2019 को हिमाचल प्रदेश सरकार एवं एस.जे.वी.एन.एल. लिमिटिड के बीच संशोधित एम.ओ.यू. साइन किया गया और उसके हिसाब से हम काम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यह प्रोजैक्ट बनना चाहिए लेकिन जब हम जमीन की कीमतें इस स्तर पर बढ़ाएंगे तो यह व्यावहारिक नहीं होगा। पिछले कल जो बद्दी-नालागढ़ सड़क का प्रश्न किया गया था उसमें भी यही बात है। लैंड एक्विजिशन में 6 करोड़ रुपये जबकि प्रोजैक्ट की कंस्ट्रक्शन कोस्ट लगभग 400 करोड़ रुपये आ रही है। आप वहां के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम इस प्रोजैक्ट को लगाना चाहते हैं और यह चीज प्रदेश हित में है। लैंड एक्विजिशन के लिए सरकार की ओर से नेगोशिएशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। इसमें किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा रही है। नेगोशिएशन में जो व्यावहारिक चीज है उसके मुताबिक इसकी राशि लगभग 40 करोड़ रुपये बनती है और इसे देखते हुए यह प्रोजैक्ट वाइबल बनने की परिस्थिति में है। मैं चाहूंगा कि हम सब लोग इसमें सहयोग दें।

14.03.2020/1140/RKS/AS-2

श्री रमेश चंद ध्वाला(ज्वालामुखी): अध्यक्ष महोदय, यह प्रोजैक्ट निचले क्षेत्र में लगने जा रहा है और इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। । इस प्रोजैक्ट की व्यवहार्यता नहीं बन रही थी। इसके लिए पिछले 22 वर्षों से प्रकिया जारी है और इसलिए मैं संबंधित अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा...(व्यवधान) आप कहते हैं कि सब कुछ बेच दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस क्षेत्र की 99 प्रतिशत भूमि में बंदर रहते हैं। वहां दरिया है ओर वहां पर बंदर रहते हैं। उस भूमि की उपयोगित क्या है? ...(व्यवधान) अगर वह कृषि योग्य भूमि है तो उसका मुआवजा मिलना चाहिए। मार्किट रेट के हिसाब से उस भूमि की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन बैठक में जो नेगोसिएशन हुई है उसके हिसाब से जमीन की अदायगी की जा रही है।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

14.03.2020/1145/बी.एस./ए.एस./-1

प्रश्न संख्याः 2758 क्रमांगत

श्री रमेश चन्द ध्वाला जारी...

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सभी लोगों को अदायगी कर दी गई है? उत्तर में यह लिखा है कि लगभग 427 परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसमें हमारे ज्वालामुखी सब डिविजन की लगभग 99 प्रतिशत हैक्टेयर जमीन जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि, एक तो यह प्रोजैक्ट बहुत मुश्किल से वाइबल हुआ है। अगर हम यहां पर फिर से लोगों को राजनीतिक तौर पर वहां प्रेरित करेंगे तो यह प्रोजैक्ट फिर नहीं लगेगा। जब यह प्रोजैक्ट लगे तो नौकरियों में first preference should be given to the people in lieu of the land they have given. जो लैंड लोगों ने दी हैं उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। दूसरा, जितने भी प्रभातिव

परिवार हैं क्या उन्हें मुआवजा मिल चुका है या मिलेगा? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपनी जमीन नहीं देना चाहता ?

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में यह कहना चाहूंगा कि जो निजी भूमि की बात हो रही है उसमें 67 प्रतिशत भूमि को खरीदा जा चुका है। इसमें 4935 कनाल में से 3292 कनाल खरीदी जा चुकी है। बाकी बची हुई भूमि की क्रय की प्रक्रिया जारी है। अध्यक्ष महोदय, यह सारी भूमि, जिस पर परियोजना के घटकों का निर्माण किया जाना है उसकी क्रय प्रकिया पूरी की जा चुकी है। जो भूमि शेष बची है उस भूमि का प्रयोग जल भराव के लिए होना है। जिसकी आवश्यकता परियोजना के निमार्ण शुरू होने के 54 माह के उरांत होगी। जब इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा उसके बाद जब पानी जाना है, जल भराव होना है उस प्रकिया को बाद में पूरा किया जा सकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि इसको हम जल्दी कर लेंगे।

श्री रमेश चन्द ध्वाला : मैं माननननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि विवाद यह है कि जो शरारती तत्व थे उन्होंने उस एरिया में जमीन खरीद ली है इसलिए अब वे ऐतराज कर रहे हैं।

14.03.2020/1145/बी.एस./ए.एस./-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि जहां भी महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट सरकार का आने वाला होता है वहां रातों-रात जमीन खरीदी और बेची जाती है। कुछ लोग वहां पर जमीन इसलिए खरीदते हैं, उन्हें लगता है कि जब इस प्रोजैक्ट के लिए जमीन की जरुरत होगी तो इसका अधिग्रहण किया जायेगा इसके बदले में उनको एक अच्छी राशि उन्हें मिलेगी। यह एक नहीं अनेक जगह ऐसा होता है। इस प्रोजैक्ट में संभवतः ये हुआ है। जिसके कारण आपत्ति करने वाले, जो धरना देने वाले ज्यादातर वे लोग हैं। आज भी अध्यक्ष महोदय, हम एक नहीं अनेक जगह देखते हैं। जहां भी कोई महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट आता है तो ये होता है मैं इसके बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं।

जहां तक रेट के बारे में मैं जानकारी दूं तो अध्यक्ष महोदय, जो दो फसली, बगीचा फलदार, नहरी जमीन की कीमत का रेट है वह कनाल के हिसाब से 3.30 लाख रुपए के हिसाब से है

श्री डी.टी.द्वारा जारी...

14.03.2020/1150/DT/DC-1

प्रश्न संख्यां 2758... जारी

मुख्य मंत्रीः जारी....

और एक फसली जमीन है उसकी एक लाख 65 हजार के कनाल के हिसाब से है। बंजर कदीम और बंजर गदीद यह 44 हजार कनाल के हिसाब से है। खडेतर जो है 33 हजार रुपये कनाल के हिसाब से है। गैर मुमकिन, नाला दरिया, सपड़ कुहल, घराट इस किस्म की जमीन में 22 हजार पर कनाल के हिसाब से है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ज्वाला जी में 544 कनाल, जयसिंहपुर में 1338 कनाल, नदौन में 307 कनाल, सुजानपुर में 1103 कनाल और कुल मिलाकर 3292 कनाल यह जमीन है। अगर हैक्टेयर के हिसाब से इसको कैलकुलेट करना है तो यह लगभग 126 .41 के लगभग यह बनती है। जैसे मैने बताया कि 67 प्रतिशत प्राइवेट जमीन को फाइनल कर लिया है, उसकी सारी प्रक्रिया आगे बढ़कर यहां तक पहुंची है। अध्यक्ष महोदय, इसके उत्तर की लंबी सूची इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट है और यह प्रोजैक्ट लगना चाहिए और इसे लगाने में आपका सहयोग चाहिए। इस प्रोजैक्ट के काम को विलम्ब करने में जो लोग लगे हैं उन लोगों के साथ चुने हुए प्रतिनिधि बातचीत करें और उस प्रोजैक्ट को आगे बढ़ने की दिशा में हमें सहयोग दें।

14.03.2020/1150/DT/DC-2

प्रश्न संख्या 2759

श्री अरूण कुमार(नगरोट) : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है वह सूचना आधी- अधूरी है। उसमें न तो स्कूलों के नाम दर्शाए गये हैं मेरे आज दो प्रश्न लगे हैं और दोनो ही शिक्षा विभाग के हैं। एक प्रश्न संख्याः 2759 और दूसरा प्रश्न संख्याः 2783 है। मैं चाहता हूं की इसी में ही इन दोनों प्रश्नों का पूर्ण रूप से जबाव मिल जाए। मेरे नगरोटा स्कूल में वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटवास में जो भवन आज से चार -पांच वर्ष पहले बना था उस पूरे भवन में पानी आता है और बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। उसके बारे में भी मैंने शिक्षा विभाग को पूरा प्राक्कलन बना कर भेजा था। ऐसे ही वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल जसाई जहां पर चार कमरों की अति आवश्कता है। क्योंकि वहां पर 138 छात्र पढ़ रहे हैं और यहां हमारे चंगर क्षेत्र का एक अलग गांव है जहां से जो दुसरा स्कूल है वह बडोह में पड़ता है। बडोह वहां से लागभग 12 किलोमीटर दूर पड़ता है तो यहां पर जितनी जमीन है उसके अनुसार दो कमरे नीचे और दो ऊपर बनने की बहुत जरूरत है। वहां पर जो दो कमरे बने हुए हैं वे वह बहुत ही जर्जर हलात में हैं। इस तरह से हमारे वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बॉयज उसका जो पुराना स्कूल है वह वर्षों पुराना स्कूल है। मैं भी उस स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, उस समय का यह स्कूल बना हुआ है और इसके ऊपर सलेटों की छत पड़ी हुई है। अब यह सलेटे जगह-जगह से टूट गई हैं। क्योंकि अब सलेटे मिलती भी नहीं है और छत टूटने के कारण पानी अन्दर आता है जिससे स्कूल की सारी सीलिंग खराब हो चुकि है। यह बहुत बड़ा स्कूल है मेरे विधानसभा क्षेत्र नगरोटा बगवां में है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य इस विषय में आप माननीय मन्त्री महोदय का आवश्वासन चाहते हैं,न। तो कृपया आप समय का ध्यान रखें

श्री अरूण कुमारः जी माननीय महोदय, मैं यह चाहता हू कि माननीय मंत्री महोदय एक कमेटी बनायें और यह कमेटी उस स्कूल में जाकर वस्तुस्थिति का आंकलन करे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्राईमरी स्कूल, पटियार और मलां में बच्चों के लिए शौचालय की

व्यवस्था नहीं है । जो रिपोर्ट नीचे यहां भेजी जाती है वह रिपोर्ट आधी अधूरी होती है। अतः मैं माननीय मन्त्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं। श्री एन.जी.द्वारा जारी..

14-03-2020/1155/डी.सी.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या 2759 जारी.....

श्री अरूण कुमार जारी.....

कि जिन-जिन स्कूलों में बच्चों को कमरों की आवश्यकता है क्योंकि कम्पयूटर आने के बाद स्कूलों के 2-2 कमरे उनमें रूक चुके हैं और बच्चों को बैठने की बहुत दिक्कत होती है। मेरा दूसरा प्रश्न जोकि बड़ोह कॉलेज के बारे में है उसमें मैं बताना चाहता हूं कि उसके भवन निर्माण के लिए 6 करोड़ 92 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है और उसके लिए केवल 34 लाख 75 हज़ार रुपये ही पैसा आया है। लोक निर्माण विभाग के पास जब तक 30 प्रतिशत पैसा जमा न होगा जोकि 2 करोड़ 08 लाख रुपये बनता है तब तक काम शुरू नहीं होगा। यह कॉलेज 26 पंचायतों के लिए है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आशवासन चाहता हूं कि इसका काम कब तक शुरू किया जाएगा?

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, आज प्रश्न काल में असमान्य चीजें हो रही हैं। माननीय सदस्य जी ने एक ही प्रश्न के साथ दोनों प्रश्न पूछ लिए हैं जोकि प्रश्न संख्या-2759 और प्रश्न संख्या-2783 है। माननीय सदस्य ने जिन विद्यालयों के बारे में बात की है मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि कुल 13 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें रिपेयर की आवश्यकता है। लेकिन उनमें प्रयाप्त क्लास रूम हैं जिनमें कक्षाएं चलाई जा रही है। वहां पर दो विद्यालय (रमेहड़ और गिरथोली) ही ऐसे हैं जिसमें 1-1 अतिरिक्त क्लास रूम की आवश्यकता है और **मैं इन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि इस वर्ष उन कक्षों के लिए बजट का प्रावधान करके उनका निर्माण कर देंगे।** इन सभी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए शौचालयों का प्रावधान समुचित है। वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में दो के भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं लेकिन इनमें भी कक्षाएं चालने के लिए प्रयाप्त क्लास रूम हैं। 3 उच्च पाठशालाओं में अतिरिक्त

क्लास रूमज़ की आवश्यकता है और 6 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में शौचालयों की आवश्यकता है।

14-03-2020/1155/डी.सी.-एन.जी./2

इस वर्ष इनके लिए प्रयाप्त बजट का प्रावधान करने का प्रयास करेंगे। ताकि इनमें शौचालय और क्लास रूम भी बन कर तैयार हो जाएं। माननीय सदस्य जी ने जैसा कहा है मैं विभाग को कहूंगा की उप-निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी वहां पर जाए और उस क्षेत्र के जितने विद्यालय जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं उनकी रिपोर्ट सबमिट करें ताकि उसके अनुसार हम बजट का प्रावधान कर सकें। दूसरे प्रश्न में इन्होंने कॉलेज की बात कही है, इनके क्षेत्र में बड़ोह कॉलेज है, वह टेकओवर हुआ था और उसके बाद उसके भवन में अभी प्रयाप्त कमरे हैं लेकिन उसमें विज्ञान कक्ष की अलग से आवश्यकता है। उसके लिए नई जमीन ली गई है जिसे विभाग के नाम कर दिया गया है और उस पर भवन निर्माण होना है। उसके लिए 6 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। हमने विभाग को कहा है कि आवश्यकता अनुसार अलग-अलग ब्लॉक वाइस प्रशासनिक स्वीकृति के लिए प्राक्कलन बनाएं ताकि जितना पैसा हम इन्हें दे उससे भवन निर्माण का काम शुरू हो सके। इस वर्ष के बजट में भवन निर्माण के लिए 90 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है और इससे पूर्व में भी इसके लिए पैसा दिया गया है। दोनों राशियों को मिला कर हम कोशिश करेंगे कि इस वर्ष भवन निर्माण का काम प्रारम्भ कर दिया जाए।

14-03-2020/1155/डी.सी.-एन.जी./3

प्रश्न संख्या-2760

श्री राकेश सिंघा (ठियोग): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमती से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से केवल दो बातें जानना चाहूंगा। पहली बात कि क्या हमारी सरकार the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act 1970 and the Employees Compensation

Act 1923 को मानती है कि नहीं? क्योंकि जो जानकारी दी गई है इसमें वह मृत्यु शामिल नहीं की गई हैं जो मजदूर बिजली बोर्ड के लिए काम करता है not through outsource but through contractor और उसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूं दिनांक 01-12-2014 को FIR No. 189/14 रजिस्टर हुई थी जिसमें श्री रोशन लाल की मृत्यु हुई है। Not a single penny has been given to him और दलित परिवार जिसके पास एक इंच भी जमीन नहीं है।

मुख्य मंत्री, श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी....

14/03/2020/1200/MS/HK/1

प्रश्न संख्याः 2760

मुख्य मंत्रीः माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वैसे तो लिखित में इसका विस्तार से उत्तर दिया हुआ है। अध्यक्ष जी, केजुअल्टी रिलीफ मैन्युअल के तहत 4,00000/-रुपये बिजली विभाग द्वारा किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर दिये जाते हैं। इसके अलावा यदि कोई 60 प्रतिशत से अधिक अपंग हो जाता है तो उसको 20,0000/-रुपये देने का प्रावधान है। बिजली बोर्ड यदि किसी तीसरे व्यक्ति की बिजली का करंट लगने के कारण मृत्यु हो जाती है तो उस सूरत में भी 2,00000/-रुपये तक रिलीफ देता है। जहां तक आपने पर्टिकुलरली एक व्यक्ति रोशन लाल की बात कही है। इस संदर्भ में मुझे यह कहना है कि श्री रोशन लाल को श्री रंजीत कंवर, जो ठेकेदार था, के द्वारा 22 के0वी0एच0टी0 लाइन की दुरुस्ती हेतु लगाया गया था तथा 1 दिसम्बर, 2014 को कार्य करते हुए रोशन लाल की बिजली का करंट लगने से मृत्यु हो गई। बिजली बोर्ड की ओर से फौरी तौर पर उसको 20,000/-रुपये की सहायता दी गई लेकिन बाद में मामला ठियोग में सिविल जज की अदालत में चला गया। अब यह मामला वहां पर चल रहा है। जैसे ही इस मामले को लेकर माननीय न्यायालय से कोई आदेश आता है, उसके बाद आगामी निर्णय इस पर ले सकते हैं। जिसका आपने जिक्र किया है उसको हम एग्जामिन करेंगे कि क्या कर सकते हैं। क्योंकि यह मामला न्यायालय के अधीन है इसलिए न्यायालय का फैसला आने के बाद ही इस पर कुछ कह सकते हैं। अध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रोशन लाल को

2,00000/-रुपये और देंगे, यह भी हमने तय किया है क्योंकि वह बहुत गरीब परिवार से है। जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद आगे की प्रक्रिया करेंगे।

प्रश्नकाल समाप्त

14/03/2020/1200/MS/HK/2

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय कोरोना वायरस कोविड-19 पर एक संक्षिप्त वक्तव्य व सूचना इस माननीय सदन में देंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के संदर्भ में पूरा विश्व चिन्तित है और पूरे विश्व ने बड़े स्तर पर इसमें कुछ निर्णय लिए हैं। यह बीमारी पूरे विश्व में जिस रूप से फैल रही है, उसको देखते हुए WHO ने इसे महामारी घोषित किया है। उसके पश्चात हमारी केन्द्र सरकार ने लगतार भारत में इस बीमारी को फैलने से कैसे रोका जाए, उस दृष्टि से एडवाजरी एक बार नहीं बल्कि अलग-अलग समय में जारी की है और कर भी रहे हैं। मैं यह भी देख रहा था कि हमारे हिमाचल प्रदेश के एडज्वाइनिंग राज्यों की सरकारों ने कुछ एहतिआत के तौर पर कदम उठाए हैं। जैसे उत्तराखण्ड ने स्कूल/कॉलेजिज बन्द किए हैं। पिछले कल पंजाब सरकार ने भी यही निर्णय लिया है और हरियाणा सरकार ने भी एक निर्णय लिया है कि जो दिल्ली के एडज्वाइनिंग एरियाज हैं, उनमें कुछ दिनों तक स्कूल/कॉलेजिज बन्द रखे जाएंगे। अध्यक्ष जी, थोड़ी ऐसी परिस्थिति बनी है जिसके कारण मैंने पहले भी इस माननीय सदन में स्पष्ट किए हैं। वास्तव में आजकल विधान सभा का सत्र चल रहा है और यह विषय बहुत महत्व का है इसलिए इस बीच में मैं सदन में भी हर बात को सांझा करता रहा। अध्यक्ष जी, पिछले दो-तीन दिनों से बहुत सारे बच्चों के माता-पिता की ओर से और कुछ छात्रों की ओर से भी हमें सीधे तौर पर फोन आ रहे हैं यानी इसको लेकर हमें बहुत से ऐसे फोन आ रहे हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए,

जारी एस0एस0 द्वारा----

मुख्य मंत्री क्रमागत :

हालांकि मुझे इस बात का संतोष है कि हिमाचल प्रदेश में वह परिस्थिति नहीं है। अभी तक जितने भी मामले पाए गए उनकी इंवैस्टीगेशन रिपोर्ट के मुताबिक उनमें कोरोना वायरस नहीं आया है। सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यह बात भी सच है कि हमारा पड़ोस का राज्य नेपाल है वहां से हमारा आने-जाने का रास्ता क्योंकि सड़क मार्ग से भी है ऐसी परिस्थिति में वहां एहतियात के तौर पर और **ज्यादा फोकस करके कुछ चीज़ों को करने का हम विचार कर रहे हैं** ताकि कोरोना वायरस फैलने की घटनाएं न हो। मैंने पहले भी इस बात को लेकर एडवाइजरी जारी करने के लिए कह दिया तो वह जारी भी कर दी गई है। जो सोशल गैदरिंग्ज़ हैं और उसके साथ-साथ में विशेष रूप से जो मेले के आयोजन होते हैं इन पर हम एहतियात बरतें और इनको रोकें। केन्द्र से भी इस बात के लिए बड़ा स्पष्ट शब्दों में आग्रह है और आज हमारी माननीय गृह मंत्री जी से बात हुई और उन्होंने भी कहा कि जहां बड़ी गैदरिंग्ज़ होती हैं जैसे पब्लिक मीटिंग्ज़, जन-सभाएं और इसके अतिरिक्त जहां मेले के आयोजन होते हैं या प्रोग्राम्ज़ होते हैं जहां हजारों की संख्या में लोगों का आना-जाना होता है उनको अवॉयड करने के लिए साफ संदेश व आदेश दें। वे सारी चीज़ें हमने पहले भी कर ली हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ चीज़ों को ले करके आज माननीय सदन में एक स्टेटमैंट देना चाह रहा हूंः-

अध्यक्ष महोदय, कोरोना वायरस यानी COVID-19 ने विश्व भर को एक महामारी के रूप में प्रभावित किया है। देश भर में कोरोना वायस से संक्रमित लोगों की संख्या निरंतर रूप से बढ़ रही है एवं दुर्भाग्यवश भारत में इस रोग से प्रभावित दो लोगों की मृत्यु की सूचना भी प्राप्त हुई है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक कुल 593 लोग जो कोरोना प्रभावित देशों से आए हैं और जिन्हें निरंतर निगरानी पर रखा गया है, इनमें से 372 लोगों की सूचना भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से प्राप्त हुई है तथा 221 लोगों ने स्वयं इन प्रभावित देशों से आने की सूचना दी है। इनमें से 7 लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार आदि के लक्षण पाए जाने के उपरांत आई0जी0एम0सी0 शिमला एवं गवर्नमैंट मेडिकल कॉलेज टांडा में

14.03.2020/1205/SS-HK/2

दाखिल किया गया था। इन सभी की रिपोर्ट नकारात्मक पाई जा चुकी है। COVID-19 की स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार पूरी से सजग एवं सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग इस महामारी से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। इसलिए प्रदेशवासियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है अपितु पूर्ण रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार ने सभी प्रकार की सार्वजनिक सभाओं, समारोहों, मेले, त्यौहारों, खेल-कूद प्रतियोगिताओं को स्थगित करने की अधिसूचना जारी की है। कुछ समयावधि के लिए आयोजित होने वाले धार्मिक आयोजनों में जनसाधारण को एकत्र न होने के पर्याप्त दिशा-निर्देश भी जारी किये गए हैं और उन्हें अपनी यात्रा अथवा आयोजन को पुनर्नियोजित करने के लिए कहा जा रहा है। स्थिति की गम्भीरता को देखने हुए वायरस की कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने हेतु प्रदेश में सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, आंगनबाड़ी केन्द्र, क्रच इत्यादि को 31 मार्च, 2020 तक बंद करने के निर्देश जारी किये जा रहे हैं। लेकिन इन शिक्षण संस्थानों में सभी प्रकार की परीक्षाओं की प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहेगी क्योंकि परीक्षाओं को आगे करना उचित नहीं रहेगा। इसी के साथ सभी प्रकार की बैठकें, कार्यशालाएं इत्यादि जोकि अत्यावश्यक न हों एवं प्रदेश के सभी सिनेमा घरों को भी 31 मार्च, 2020 तक बंद किया जा रहा है क्योंकि वहां पर लोगों का ज्यादा आना-जाना होता है। इस कदम को सभी लोग सकारात्मक रूप से लें और डर का माहौल न फैलने दें। आपकी और आपके परिजनों की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार के साथ सहयोग की अपेक्षा करता हूं

जारी श्रीमती के0एस0

14.03.2020/1210/केएस/वाईके/1

मुख्य मंत्री जारी---

अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय विधायकों से, क्योंकि रीसैस से पहले का अंतिम वर्किंग डे है, उसके बाद हमारा हाउस आज एडजॉर्न हो जाएगा फिर हम 23 मार्च, 2020 को मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भारत सरकार की ओर से

डायरैक्शन्ज़/गाइडलाइन्ज़ हैं, उनके मुताबिक हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना है और चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते मेरा आप सभी से भी निवेदन है कि कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस प्रकार की परिस्थिति हिमाचल में अभी तक नहीं है। कोरोना वायरस का कोई भी केस पोज़िटिव नहीं पाया गया है लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर, कई जगह इस बात के लिए आग्रह आ रहे हैं कि हमने तो कार्यक्रम की तैयारी कर दी है, मैं समझता हूं कि अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में जहां भी इस प्रकार के आयोजन अगर पूर्व निर्धारित हैं, लोगों के बीच जाकर, उनको समझाकर रोकने की आवश्यकता रहेगी।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया, इसका हम स्वागत करते हैं लेकिन मुख्य मंत्री जी, बाकी सब चीजें ठीक हैं, मगर 25 मार्च से 2 अप्रैल, 2020 तक चैत्र नवरात्रे हैं। इसमें हम लोगों को कैसे रोक पाएंगे और धार्मिक स्थलों पर हम क्या कदम उठाएंगे उसके लिए we will have to take some special steps. We cannot stop the people because उनकी आस्था होती है। खासकर अष्टमी व नवमी का जो दिन होता है। हम चाहते हैं कि इसमें आप अपने ऑफिसर्ज़ को स्पैशल इंस्ट्रक्शन्ज़ दें । नैना देवी, चिंतपुरनी या अन्य मंदिरों में और छोटे-छोटे मंदिरों में भी बहुत भीड़ होती है, अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगी।

14.03.2020/1210/केएस/वाईके/2

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि अवेयरनेस के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। खासकर जो इस तरह के मेले या त्योहार होते हैं, धार्मिक स्थान होते हैं, नवरात्रों का विशेषतौर पर माननीय सदस्या जी ने ज़िक्र किया, वहां पर बड़ी श्रद्धा के साथ लोग आते हैं। इन आयोजनों को आयोजित करने वाली कमेटी से भी इस बात का आग्रह करेंगें और प्रशासन की ओर से भी हम इस तरह की तैयारी रखेंगे कि वहां इतनी ज्यादा भीड़ न आए। लोग दर्शन करने आएं लेकिन कम मात्रा में आएं, इस तरह सारी चीजों को ले कर कोशिश करेंगे।

श्री होशयार सिंहः अध्यक्ष महोदय, आज मैं हाउस में मास्क पहनकर इसलिए आया हूं कि this is a reality which we should show, सभी को बताना चाहिए कि we should use the mask. Sir, as per the latest report, 85 केसिज़ कोरोना वायरस के हैं और यह अभी 11 बजकर 14 मिनट की रिपोर्ट है कि हिन्दुस्तान में 83 केसिज़ कन्फर्म हो चुके हैं। यह बीमारी दिल्ली व आगरा तक पहुंच गई है and they have closed all the schools, colleges, meetings, public meetings and all, which is a very good step. माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि 31 मार्च तक सभी स्कूल व कॉलेज बंद होंगे। परन्तु एक छोटा सा प्वाइंट था कि doctors are available on all the check points. जो टूरिस्ट बाई एयर हमारी स्टेट में आ रहे हैं, क्या उनकी चैकिंग हो रही है? क्या एयरपोर्ट्स में, चैक प्वाइंट्स पर डॉक्टर्ज़ की टीम अवेलेबल है? जैसे कि आप जानते हैं कि दलाई लामा को मिलने के लिए चाइना से बहुत लोग आते हैं, क्या चाइना से आने वाले सभी लोगों की एयरपोर्ट्स या चैक प्वाइंट्स पर चैकिंग होगी? अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ इसका जवाब चाहिए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं इस संदर्भ में विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि जैसे ही कोरोना वायरस की खबर आई थी, उसके पश्चात हमने पर्टिकुलर हो कर एयरपोर्ट्स पर इन सारी चीजों की तैयारी की है। विशेषतौर पर कांगड़ा का गग्गल एयरपोर्ट, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में दलाई लामा जी से मिलने के लिए विदेश से भी लोग आते हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

14.03.2020/1215/av-yk/1

मुख्य मंत्री---- जारी

वहां इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। वहां एक पोस्ट बनाई गई है तथा बाहर से जितने भी धार्मिक दृष्टि से लोग दलाईलामा जी से मिलने के लिए आ रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिड पूरी सूचना हमारे पास है। वहां आने वाले लोगों में इस बीमारी के सिम्प्टम्ज को भी चैक किया जा रहा है। अभी केंद्र सरकार की ओर से इस तरह के सारे आने-जाने के वीज़ाज रद्द कर दिए गए हैं और मुझे नहीं लगता कि यहां ऐसी परिस्थिति में बाहर से कोई

आयेगा। हमारे लिए चिंता का विषय यह है कि नेपाल में भी यह बीमारी आ चुकी है। वहां से भारत के लिए आने-जाने का साधन बाई रोड भी है। बाई एयर कनेक्टिविटी के तहत मोनिटर करना आसान है मगर बाई रोड चैक रखना कठिन काम है। मगर वाबजूद इसके हमारी तैयारी पूरी है।

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर) : अध्यक्ष महोदय, जिला किन्नौर और स्पिति के एरिया में नेपाली मूल के प्रतिदिन हजारों लैबरर्ज आ रहे हैं। हमारे जिला किन्नौर के राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 पर जो नेपाली लोग आ रहे हैं क्या आप उनकी स्क्रीनिंग करवायेंगे तथा क्या आज की डेट में आपके पास स्क्रीनिंग गन्ज उपलब्ध है?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कह दिया कि ऐहतियात के तौर पर जो भी चीजें करने की है उसको चैक पोस्ट पर करने की कोशिश की जा रही है। हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल बाई रोड से आने-जाने वालों को मोनिटर करना है। मगर उसके बावजूद भी विभाग ने उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है और कुछ प्वाईंट्स ऐसे हैं जहां पर शुरू करने की आवश्यकता रहेगी। मैं यह बताना चाहूंगा कि विभाग की तरफ से पूरी तैयारी है। लेकिन जहां तक आप जिला किन्नौर व स्पिति एरिया के बारे में पूछ रहे हैं तो इस संदर्भ में मैं अभी विभाग से फिर से जानकारी लूंगा क्योंकि अभी हम इसी के बारे में बैठक करने वाले हैं। जिसमें कैबिनेट के लोग व हमारे सारे अधिकारी होंगे। इसके लिए एहतियात के तौर पर जो कुछ भी करने की आवश्यकता होगी; वह किया जायेगा। हालांकि आज की डेट में हमारे पास मास्क और

सेनिटाईज़र की उपलब्धता में कमी नहीं है। मगर उसके बावजूद यदि और चीजों की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए आने वाले समय में कैसे आगे बढ़ना है; उसकी जानकारी हम आपको दे देंगे।

14.03.2020/1215/av-yk/3

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब श्री राकेश पठानिया, सभापति, लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2019-20), समिति का 24वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 12वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री राकेश पठानिया, सभापति : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2019-20), समिति का 24वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 12वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब श्री हीरा लाल, सभापति, सामान्य विकास समिति (वर्ष 2019-20), समिति का 18वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 16वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री हीरा लाल, सभापति : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सामान्य विकास समिति (वर्ष 2019-20), समिति का 18वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 16वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

14.03.2020/1215/av-yk/4

वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा एवं समापन

अध्यक्ष : अब वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा होगी। आज ही चर्चा का समापन माननीय मुख्य मंत्री महोदय के उत्तर से होगा। इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जो आवंटित समय 10-10 मिनट का है उसी में अपनी बात कहें।

टी सी द्वारा जारी

13.03.2020/1220/TCV/AG-1

अध्यक्ष... जारी

क्योंकि आज ही माननीय मुख्य मंत्री जी को चर्चा समाप्त होने के बाद इस सदन में चर्चा का उत्तर भी देना है। श्री मुकेश अग्निहोत्री जी आप क्या कहना चाहते हैं, कहिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली) : अध्यक्ष जी, अभी 3 माननीय सदस्यों ने बोलना है, उनको पर्याप्त समय दिया जाये क्योंकि 10 मिनट बहुत कम हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि सत्तापक्ष से तो मुख्य मंत्री जी का जवाब आना है, आप वहां थोड़ा समय कम कर दें लेकिन हमें प्रोपर समय बोलने के लिए दिया जाये।

अध्यक्ष : मेरा पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों से विशेष रूप से आग्रह है कि वे समय का ध्यान रखें। पिछले कल भी माननीय सदस्यों ने काफी सहयोग दिया था। कई सीनियर माननीय सदस्य भी चर्चा में भाग ले रहें थे परंतु उन्होंने समय की परिधि में ही अपनी बात रखी । अब माननीय सदस्य, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु (नदौन) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट अनुमान यहां सदन में पेश किया है, उस पर विचार रखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में पहले पन्ने पर कहा है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्ज़ा प्राप्त हुए 50 वर्ष हो गये हैं। 50 वर्ष के लम्बे अंतराल के संदर्भ में मुख्य मंत्री द्वारा यह बजट पेश किया गया है। हमने 50 वर्षों में क्या खोया और क्या पाया, आज इस बजट के माध्यम से इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। वर्ष 1971 में जब कांग्रेस पार्टी ने सभी छोटी-मोटी रियासतों को मिलाकर पूर्ण राज्य का दर्ज़ा हासिल किया था तो उस समय हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति थी? हमारी आबादी 34 लाख के करीब थी और जो साक्षरता दर थी, वह केवल 24 प्रतिशत के करीब थी। हिमाचल प्रदेश में स्कूल 4000 के करीब थे, सड़कें 7000 किलोमीटर के लगभग थीं लेकिन धीरे-धीरे इन 50 सालों में हमने विकास की उन बुलंदियों को छुआ जो कांग्रेस पार्टी की नीतियों व कार्यक्रमों द्वारा तय की गई। इसमें

13.03.2020/1220/TCV/AG-2

निश्चित तौर पर कोई दो-राय नहीं होनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश को साक्षरता की दर में पूरे हिन्दुस्तान में जो पहला स्थान मिला है, वह कांग्रेस पार्टी के विचारों व कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों के द्वारा मिला है। इसमें भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जो विकास की बुलंदियों को हमने छुआ है, उसमें हमारे प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री, डॉ0 यशवंत सिंह परमार जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक ऐसी सोच जिसने इस प्रदेश की संस्कृति को बचाए रखा, जिसने इस प्रदेश के अस्तित्व को बचाए रखा। एक ऐसी विचारधारा जिसमें कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के व़जूद को बनाया, हिमाचल प्रदेश को सजाया, हिमाचल प्रदेश की प्रकृति में चार चांद लगाए, वह कांग्रेस पार्टी ही है। यह बार-बार कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। मैं उन सभी मुख्य मंत्रियों को जिन्होंने इस प्रदेश को हिन्दुस्तान का सबसे सुन्दर प्रदेश बनाया, आज इस सदन के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं। परमार जी की सोच थी, उन्होंने लैंड टेंडैंसी एक्ट

लाया और धारा-118 का जो प्रावधान किया गया, उसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के किसान व छोटे कृषकों की ज़मीनें बेचने से बच गई। ये सिर्फ़ परमार साहब की सोच थी। उसके बाद श्री राम लाल ठाकुर जी, श्री शान्ता कुमार जी, श्री वीरभद्र सिंह जी और श्री प्रेम कुमार धूमल जी आये, सभी इस प्रदेश के विकास में कहीं-न-कहीं मिल का पत्थर साबित हुए हैं।

श्री आर0के0एस0 द्वारा ... जारी

14.03.2020/1225/RKS/AG-1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु...जारी

जहां हमने पूरे हिन्दुस्तान में विकास के मामले में अगम्य स्थान बनाया है वहां राजनीति के संदर्भ में भी अगम्य स्थान बनाया है। इसी सभागार और छात्र राजनीति से निकले हमारे कई साथियों ने राष्ट्र में अपना नाम रोशन किया है। यह इस प्रदेश की 50 वर्षों की उपलब्धि है। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के छात्र संगठन से निकलकर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और यह हमारे लिए गर्व की बात है। श्री आनंद शर्मा जी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से निकलकर ऑल इंडिया युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने और केंद्र में भारत सरकार के मंत्री भी रहे। हमारे साथ बैठे आदरणीय राकेश सिंघा जी ने छात्र जीवन में अपनी विचारधार को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया और राष्ट्रीय स्तर पर इनकी नियुक्ति हुई। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रदेश ने बहुत महत्वपूर्ण नेता इस देश को दिए हैं। आज सोच इस बात की होनी चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं? हमने क्या खोया, क्या पाया इस पर विचार किया जाना चाहिए। आज इस सदन में बैठ हुए जो माननीय सदस्य हैं उनमें कुछेक को छोड़कर आजादी के बाद पैदा हुए हैं। शायद श्री धनी राम शांडिल या श्री महेन्द्र सिंह जी आजादी से पहले पैदा हुए हों। लेकिन परिवर्तन आया और माननीय श्री जय राम ठाकुर जी आजादी के बाद पैदा हुए पहले मुख्य मंत्री बने और इसी तरह माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी भी आजादी के बाद

पैदा हुए पहले नेता प्रतिपक्ष बने। इस सदन में बैठे 80 प्रतिशत विधायक आजादी के बाद पैदा हुए हैं। जिस मेहनत से इस प्रदेश के नेताओं, मुख्यमंत्रियों व मंत्रियों ने इस प्रदेश को सिंचा है उसके लिए आज हमें उन्हें याद करना चाहिए और 50वीं वर्षगांठ पर यह उनके लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिस सेवा भाव से उन्होंने इस प्रदेश की राजनीति को आगे बढ़ाया है उस सेवा भाव से आजादी के बाद पैदा हुए नेतृत्व को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम हिमाचल प्रदेश के लोगों पर हजारों करोड़ रुपये का कर्ज़ छोड़कर जा रहे हैं। सन् 1971 में हिमाचल प्रदेश में कोई कर्ज नहीं था। आज हम 56 हजार करोड़ रुपये के कर्ज़ के तले दबे हैं।

14.03.2020/1225/RKS/AG-2

आने वाले 5 वर्षों में 71 लाख की आबादी में प्रति व्यक्ति को एक लाख रुपये का कर्ज चढ़ा होगा। परिस्थितियां कोई भी रही हो लेकिन विकास की कोई सीमा नहीं होती। हिमाचल प्रदेश की जनता बड़ी जागरूक है। यहां का मतदाता बहुत जागरूक है। जब नेतृत्व लोगों की आशा के अनुरूप खरा नहीं उतरे तो यशवंत सिंह परमार से लेकर माननीय प्रेम कुमार धूमल तक कई एसे उदाहरण हैं जिनको जागरूक मतदाता ने धूल चटाई है। हमारा मतदाता राजनीति को कई दृष्टि से देखता है। हमारे बीच धीरे-धीरे ईमानदारी का पतन हो रहा है। मैंन एक सवाल किया था और यह खबर पंजाब केसरी में प्रकाशित हुई है। भ्रष्टाचार के मामलों में दो वर्षों में लगभग 100 एफ.आई.आर. दर्ज़ हुई हैं। हिमाचल की पहचान ईमानदार लोगों के रूप में होती है। एक सोच जो ईमानदारी से इस देश की सेवा करना चाहती थी उस सोच को हमारा नेतृत्व आगे बढ़ा रहा है, लेकिन आपको क्या हो गया है? एक भ्रष्टाचार तो वह है जो दिखाई देता है लेकिन एक भ्रष्टाचार वह है जो दिखाई नहीं देता लेकिन समझ आता है। यस बैंक में घोटाला हुआ।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

14.03.2020/1230/बी.एस./ए.एस./-1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जारी...

हम क्या बैठे हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी एक स्टेटमैंट दे कर चले गए, हमारा क्या दायित्व है, 2 हजार करोड़ रुपए के करीब हिमाचल की गरीब जनता का पैसा येस बैंक में फसा पड़ा है। कॉऑपरेटिव बैंक का 650 करोड़ रुपया उसमें पड़ा है। कांगड़ा कॉऑपरेटिव बैंक का 350 करोड़ रुपया उसमें पड़ा है। स्मार्ट सिटी धर्मशाला का 180 करोड़ रुपए उसमें पड़ा है। इन्फ्रास्ट्रक्चर बोर्ड का 130 करोड़ रुपया उसमें पड़ा है और कितने निगमों/बोर्डों का पैसा उसमें है? मैंने प्रश्न किया है, आने वाले समय में हमें पता चलेगा। क्या यह 2 हजार करोड़ रुपया हमारे विकास कार्यो में काम नहीं आना था? आपके इन दो बैंकों में कितने गरीब मजदूरों, किसानों, महिलाओं के खाते कॉऑपरेटिव बैंक में खुले होंगे? माननीय मुख्य मंत्री जी आए बयान दिया और चले गए। इसमें इन्क्वायरी होनी चाहिए थी। जो भ्रष्टाचार हमें दिखाई नहीं देता कि किस तरह से 650 करोड़ रुपया कांगड़ा कॉऑपरेटिव बैंक का येस बैंक में गया? यह जो बैंक है ये ज्यादा पैसे पर ज्यादा लालच देते हैं। ठीक है कई जगह इन्ट्रस्ट रेट ज्यादा हो सकता है। लेकिन 5 दिन पहले बड़ौदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसी येस बैंक से 250 करोड़ रुपया निकाला, दो महीने पहले इसी येस बैंक से 1300 करोड़ रुपया निकाला। जो हमारा पैसा रखने वाले लोग थे ये वित्त सचिव या अन्य कोई लोग थे या जो स्टॉक मार्किट को चैक करने वाले लोग थे क्या उन्होंने एक वर्ष से यह नहीं देखा कि येस बैंक की स्टॉक मार्किट नीचे जा रही है? इसमें कहीं-न-कहीं न दिखने वाला भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि 650 करोड़ रुपया डूबने के बाद कांगड़ा कॉऑपरेटिव बैंक और हिमाचल प्रदेश कॉऑपरेटिव बैंक कहीं डूबने के कगार पर तो नहीं आ गए हैं? इसकी इन्क्वायरी करवाई जाए। यही नहीं अजीब सा दौर चला है, पैसे घर में रखें तो चोर ले जाते हैं। बैंक में रखें तो चौकीदार ले जाते हैं। गंगा साफ करते-करते कहीं बैंक ही साफ न हो जाए। ठाकुर साहब आपने 7 चुनाव विभिन्न पार्टियों से लड़े हैं और जीते हैं यह श्रेय आपको जाता है। लेकिन जो अदृष्य भ्रष्टाचार है मैं उसकी बात कर रहा हूं।

14.03.2020/1230/बी.एस./ए.एस./-2

जल शक्ति मंत्री : इसमें हमारा या हमारी सरकार का क्या कसूर है।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : मैंने तो आपका कसूर बोला ही नहीं है, कृपया आप बैठ जाइए। आप तो आजादी से पहले के नेता हैं इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। अध्यक्ष महोदय, दो मिनट का समय इन्होंने लिया है इसलिए मुझे यह समय दिया जाए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया आप चेयर को एड्रेस करें।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भ्रष्टाचार दिखाई देता है वह तो हम सब लोगों को नजर आता है टैंडर दे दिए, सप्लाई दे दी, घर में बैठ करके सब कुछ दे दिया। जो भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता में उसकी चर्चा करता हूं। टैंडर बांटना, माइनिंग की लीजें बांटना, यह सब घर बैंठे नजर आते हैं, यह सब कॉमन हैं। मैं आपको उस माइनिंग की तरफ ले जाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में सीमेंट बनता है और हिमाचल प्रदेश में सीमेंट की कीमत, जो भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दे रहा, 410 रुपए है और पंजाब में सीमेंट का रेट 330 रुपए है, हरियाणा में सीमेंट का रेट 350 रुपया है। हिमाचल से मिनरल्ज जाएगा, हिमाचल से माइनिंग के प्रोडक्ट्स जाएंगे

श्री डी.टी.द्वारा जारी...

14.03.20201235/DT/AS/1

श्री सुखविन्द्र सिंह जारी

सारा रॉ-मैटिरियल हमारे प्रदेश से जायेगा, लकिन हिमाचल के लोगों को यह सिमेण्ट उद्योग सबसे ज्यादा मंहगा सिमेण्ट बेच रहें हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक सिमेण्ट के बेग की कितनी कोस्टिंग होती है? कितने में सिमेण्ट बनता है? कितना रॉ-मैटिरियल लगता है और उस मैटिरियल पर कितना टैक्स कम्पनियां देती है? यह भी देखने की बात है की वह कम्पनियां कोस्टिंग पर टैक्स दे रही की बेचने पर टैक्स दे रही है? 410 रूपये का सिमेण्ट

का बेग। हम उनसे माईनिंग की क्या रोयाल्टी ले रहें हैं और किस दाम पर ले रहें हैं? क्या वहां एन0जी0टी0 सोया हुआ है? पूरे के पूरे पहाड़ खोद दिये जाते हैं फिर भी एन0जी0टी0 सोया हुआ है। माईनिंग की रोयाल्टी क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह न दिखने वाला भ्रष्टाचार है। आप इसकी जांच करवाईये कि क्यों सिमेण्ट की कोस्ट इतनी बढ़ रही है। मेरा यह मानना है कि कांग्रेस के समय में एक बार इसकी कोस्टिंग करवाई गई थी और जो सिमेण्ट था,उसमें सारे टैक्सिज़, रोयाल्टी आदि डाल कर जो प्रोडकशन हुई है, उसकी प्रोडकशन लगभग 140 रूपये प्रति बेग पड़ी । ट्रान्सर्पोटेशन के नाम पर इतना बड़ा घोटाला हो जाता है। 140 प्रति बेग की कास्टिंग क्या है? यदि 20-25 रूपया सिमेण्ट पर रख भी लिया जाये तो भी 160-170 रूपये इसकी कोस्ट होनी चाहिए। परन्तु हिमाचल की गरीब जनता को यह बेग 410 रूपये का बेचा जाता है। घर बनाने को आप प्रधान मन्त्री आवास योजना में पैसे देते है, उसमें आधा पैसा तो यह सिमेण्ट उद्योग ले जाता हैं। कई सिमेण्ट उद्योगों की माईनिंग लीज कर्न्फम ही नहीं हुई है। यह चीज देखने की है कि जो नहीं दिखने वाला भ्रष्टाचार है वह इस सरकार में नज़र आ रहा है। यही नहीं जो जी0एस0टी0 के बाद सारे टेक्स एक हो गयें हैं क्या उनसे उपभोगता को इनपुट क्रेडिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, सरकार को इस दिशा में भी सोचना चाहिए। अभी तक कोई इनपुट क्रेडिट उपभोगता को नहीं मिला जो उपभोगता को मिलना चाहिए था। इस प्रकार की सोच से हम आगे नहीं बढ़ सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने पर्यटन के क्षेत्र में अपने इस

14.03.20201235/DT/AS/2

वर्ष के बजट में काफी कुछ कहा है और हम मानते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है। मुख्य मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि उनकी सरकार पर्यटन के क्षेत्र में मण्डी, कांगड़ा, शिमला में हैलीपोड के लिए 1013 करोड़ रूपये का प्रावधान करेगी। और बजट बुक में यह भी कहा गया है कि हम हैलीपोड का निर्माण अनुभव के आधार पर करेंगे। किस तरह का अनुभव हैलीपोड के निर्माण के लिए चाहिए? कांग्रेस सरकार के समय में 6

हैलीपोड स्वीकृत किये गये थे। जिसमें शिमला के संजौली में, एक रामपुर में, एक ज्यूरी में हुआ था जिसको आपने वहां से चम्बा शिफ्ट कर दिया, एक बद्दी में एक मनाली के सासे में, यह 6 हैलीपोड हमारे समय सैंक्शन हुए थे। हमें न मुख्य मन्त्री जी की नीति ठीक लगी और न ही उनकी नियत ही ठीक लगी। अगर नीति या नियत ठीक है तो इसमें दर्शाना चाहिए था कि इस ज़िला के हैडक्वाटर में हम हैलीपोड बनायेंगे, इतना पैसा हमने मण्डी एयरपोटे के लिए रखा है। मण्डी एयरपोर्ट के लिए तो इसलिए रखा है क्योंकि माननीय मुख्य मन्त्री जी फंस गये हैं क्योंकि यह एम0ओ0यू0 साईन कर चुकें हैं और एम0ओ0यू0 में कन्डीशन है, क्योंकि भारत सरकार के बजट मे अगले पांच साल में 100 एयरपोर्ट बनने हैं, उन्होंने एम0ओ0यू0 में यह कन्डीशन लगा दी है कि अगर आप हमें जमीन प्रोवाईड करेंगे तभी हम आपको एयरपोर्ट देंगे। और यह मुख्य मन्त्री जी का सपना है। अच्छा है, मुख्य मन्त्री महोदय अपना सपना पूरा कर रहें हैं। लेकिन हम यह कहना चाहतें हैं कि मुख्य मन्त्री जी को मण्डी ज़िला से उठकर प्रदेश के अन्य ज़िले जैसे कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला, सोलन चम्बा, सिरमौर आदि सभी ज़िलों को देखना चाहिए।

श्री एन0जी0द्वारा जारी

14-03-2020/1240/डी.सी.-एन.जी./1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जारी.....

जब इन जिलों को भी देखेंगे तब जाकर हैलिपोर्ट बनेंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि...(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया वाइंडअप करें।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे 12 मिनट पड़े हैं और 2 मिनट इन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया है।

अध्यक्षः कौन से 12 मिनट हैं, माननीय सदस्य कृपया वाइंडअप करें।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः अध्यक्ष महोदय, इन पांच हैलीपोड को चलाने के बाद हम फैसला करेंगे कि हैलीपोर्ट्स बनेंगे या नहीं। इनकी नीति साफ नहीं है और नियत तो सिर्फ मण्डी एयरपोर्ट में ही फंसी हुई है। पर्यटन की दृष्टि से एक अच्छा काम इन्होंने किया है और जिसमें इन्होंने हिम्मत दिखाई है कि इसके लिए बजट में पैसे का प्रावधान किया है इसके लिए हम इनका धन्यवाद भी करते हैं क्योंकि अच्छी बात है कि पर्यटन के सैक्टर में हम आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी आप धौलासिद्ध के प्रश्न का जवाब दे रहे थे और आपने धौलासिद्ध और लूहरी प्रोजैक्ट, जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि 'हिमाचल ऑन सेल' है, को आपने बेच दिया है। उसके लिए आपने 67 प्रतिशत भूमि ली, अच्छी बात है कि आपने उसमें नेगोसिएशन किया, 3,000 कनाल जगह आपने 21 करोड़ रुपये में ली। आपने वर्ष 2005 की पावर पोलिसी को पूरी तरह से बदल कर एम.ओ.यू. साइन किया। उस पावर पोलिसी में था कि यदि कोई प्रोजैक्ट वाला आएगा तो upfront premium नहीं देंगे। रिसेशन चल रहा है और इंडस्ट्री आ नहीं रही, हमें धुंध के शहर नहीं बनाने हैं। लेकिन आपने धौलासिद्ध और लूहरी प्रोजैक्ट को किस कंडीशन पर लाइफलोंग दे दिया। एन.टी.पी.सी. के साथ आप जिस एम.ओ.यू. की बात कर रहे हैं और जो आपने सरकारी उपक्रमों के साथ समझौते किए हैं, NTPC, NHPC, SJVNL के साथ जो समझौते किए हैं उसमें आपने प्रदेश के हितों को बेच कर रख दिया है। कांग्रेस सरकार के समय जो भी

एग्रीमेंट हुआ उसके अनुसार 40 साल बाद वह बिजली का प्रोजैक्ट वापिस आएगा। आपने इस एग्रीमेंट में कहा कि 40 साल बाद बिजली का प्रोजैक्ट वापिस नहीं आएगा और आप हमको सिर्फ 25 प्रतिशत दे दो। (घण्टी) पहले एस.जे.वी.एन.एल. ने धौलासिद्ध प्रोजैक्ट के लिए क्या कंडीशन लगाई थी।

अध्यक्षः माननीय सदस्य आप बैठ जाएं। मैं समय को लेकर व्यवस्था दे रहा हूं। आप भी इस माननीय सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और इस माननीय सदन में जो वरिष्ठ सदस्य हैं मैं उन सभी से विशेष रूप से अपेक्षा करता हूं कि वे अध्यक्षपीठ को सदन में व्यवस्था बनाएं रखने में साहयता करें। अध्यक्षपीठ को उनसे यह भी आशा रहती है कि वे नियमानुसार आवंटित समय में ही चर्चा पूरी करें ताकि नए सदस्य इस मामले में उनका अनुशरण कर सकें और इस सदन की परमपराएं और गरिमा बनाए रखें। कृपया सभी सदस्य समय व व्यवस्था बनाए रखने में अध्यक्षपीठ को सहयोग दें। माननीय सदस्य एक मिनट में अपनी बात को वाइंडअप करें।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था देना तो अच्छी बात है लेकिन आपको न्याय करना चाहिए। कल श्री बिक्रम जी ने 47 मिनट तक बोला, यदि आप इस कुर्सी पर बैठ कर न्याय करेंगे तो हमारा भी आदर रहेगा। हम आपकी बात को भी सुन रहे हैं लेकिन आप थोड़ा सा तो हमारा ख्याल रखिए, 3 मिनट तो श्री महेन्द्र सिंह जी ने बीच में रोक दिया, हमारी प्रार्थना है आपसे कि थोड़ा तो समय दीजिए। अध्यक्ष महोदय, धौलासिद्ध और लूहरी प्रोजैक्ट में हमारा एम.ओ.यू. एस.जे.वी.एन.एल. के साथ हुआ है उसमें पहले 10 साल में हमें कोई बिजली नहीं मिलेगी, 10 से 25 साल में 4 प्रतिशत बिजली मिलेगी, 25 से 40 साल में 8 प्रतिशत बिजली मिलेगी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय जो आपने सरकारी उपक्रमों के साथ एम0ओ0यू0 किए हैं

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी....

14/03/2020/1245/MS/DC/1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जारी--------

उसमें आप उनको उन प्रोजैक्ट्स को लाइफ लाँग के लिए मत दीजिए। आप उनको 40 साल बाद वापिस लाने का प्रावधान कीजिए। यह बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, आपके दृष्टिपत्र में था कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति लाएंगे। हमारे सरकारी उपक्रमों और विभागों में लगभग 60,000 युवा लगे हुए हैं। क्या आपने सोचा

है कि उनके लिए नीति लाएंगे? इसका मतलब यह है कि जो आपने दृष्टिपत्र में कहा, वह झूठ था। आपने सिर्फ़ वोट बैंक की राजनीति को साधन बनाकर यह बात लिखी थी। हमारा सरकार से अनुरोध है कि जो भी आउटसोर्स में कर्मचारी लगे हैं, उनके लिए कोई-न-कोई कारगर नीति लाई जाए और कैटेगरीवाइज नीति लाई जाए।

आप मिनिमम वेजिज की बात करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि नर्सिंज को भी 8000/-रुपये मिल रहे हैं और ऑपरेटर को भी 8000/-रुपये मिल रहे हैं। इसलिए जो भी आउटसोर्स कर्मचारी लगे हैं, उनके लिए कैटेगरीवाइज नीति लाई जाए, चाहे वह टैक्निकल या नॉन टैक्निकल कोई भी कर्मचारी है। उसकी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए और मिनिमम वेजिज निर्धारित होने चाहिए कि उसको आउटसोर्स के माध्यम से भी इतने ही पैसे मिलेंगे।

हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी दिन-रात इस प्रदेश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। एक कॉन्स्टेबल 20 साल तक एक ही पद पर लगा रहता है। ये पूरे प्रदेश के अंगरक्षक हैं। लेकिन इन्हें डाइट मनी 7/-रुपये मिलती है। इनको आज के हिसाब से 7/-रुपये डाइट मनी क्यों देते हैं? इस डाइट मनी को बढ़ाना चाहिए। पहले उनको एक महीने की एक्स्ट्रा पे भी मिलती थी लेकिन वह पे भी अब उनको नहीं मिलती है। कितने पुलिस अधिकारी/कर्मचारी आज इस विधान सभा की सुरक्षा में लगे हुए हैं? मेरा मुख्य मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि 7/-रुपये वाली डाइट मनी को बढ़ाया जाए। अगर बेचारों ने चाय का एक कप भी पीना हो तो वह भी 10/-रुपये में आता है। इसलिए कम-से-कम एक डाइट मनी को बढ़ाकर 100/-रुपये किया जाए, इससे ज्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं एक चीज और बताता हूं कि जो पुलिस की भर्ती वर्ष 2015 के बाद हुई है, अब ये मत कहना कि उस समय हमारी सरकार थी क्योंकि हम तो इधर बैठ गए हैं। उन बेचारों का अनुबंध पीरियड आठ साल है जबकि आपकी सरकार ने सरकारी विभागों में जो लोग लगे हुए हैं, उनका शुरू में तीन साल का अनुबंध पीरियड रखा है। तो सिर्फ़ पुलिस कर्मचारियों के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? उनका भी तीन साल का अनुबंध पीरियड होना चाहिए।

14/03/2020/1245/MS/DC/2

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपको बोलते हुए 25 मिनट का समय हो गया है इसलिए समाप्त कीजिए।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मैं अच्छी चीजें ही बता रहा हूं। आज ही पंजाब केसरी में एक ख़बर छपी है कि-"माइनिंग टीम ने किया स्टिंग ऑपरेशन-खनन माफिया से पुलिस के नाम पर जाते हैं 700/-रुपये प्रति ट्रक"। अध्यक्ष जी, यह नहीं दिखने वाला भ्रष्टाचार है। मैं उद्योग मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि माइनिंग में आप कह देते हैं कि हमने पैनल्टी बढ़ाकर 5,00000/-रुपये कर दी है। आप एक भी आदमी बता दीजिए जिस पर आपने 5,00000/-रुपये की पैनल्टी लगाई है? क्योंकि जो पैनल्टी का मैक्सिमम रेट है, वह 5,00000/-रुपये है। माइनिंग में मिनिमम पैनल्टी 5100/-रुपये है। फिर चाहे लोडिंग हो या ओवर लोडिंग हो। सब कुछ सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। अब जो 10 चौकियां बना दी हैं, आप इस अख़बार के माध्यम से बता दीजिए क्या उन चौकियों की भी कीमत लगेगी? उसके लिए भी एक विस्तृत योजना के साथ सरकार को यहां आना चाहिए।

अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि यस बैंक में जो हमारे बैंकों द्वारा पैसा जमा करवाया गया है; जो भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता, उस भ्रष्टाचार की आप इन्क्वायरी करवाइये। जो एस0जे0वी0एन0एल0 उपक्रम के साथ अधिकारियों ने समझौता किया है, उसको कम करके 40 साल किया जाए। इसके अलावा पुलिस भर्ती, आउटसोर्स कर्मचारी, (घण्टी) एक और चीज कहना चाहता हूं। एस0एम0सी0 कर्मचारी आपने 3600 लगाए हैं, उनके लिए भी कोई नीति बने क्योंकि वे हमारे प्रदेश के हैं। अध्यक्ष जी, 50 वर्ष बीत गए हैं और अब नई पीढ़ी आई है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मंत्री के रूप में युवा नेतृत्व आपके सामने आया है। युवा नेतृत्व से हम आशा करते हैं और हमें विश्वास है कि युवा नेतृत्व करेंगे। लेकिन क्या आउटसोर्स

कर्मचारी आपके दृष्टिपत्र में नहीं थे? क्या सीमेंट हिमाचल प्रदेश में 410/-रुपये प्रति बैग नहीं बिक रहा है? क्या एस0एम0सी0 के कर्मचारियों के लिए कोई नीति नहीं बनेंगी? ये सब चीजें हमारे अपने लोगों के लिए हैं इसलिए इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी भी यहां बैठे हैं और हमारा अभी शिक्षा मंत्री जी से बात करना जरूरी है।

जारी एस0एस0 द्वारा---

14.03.2020/1250/SS-HK/1

अध्यक्ष : माननीय सदस्य वाइंड अप करें।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : शिक्षा मंत्री जी जब हम और आप कॉलेज में पढ़ते थे तो 15 कॉलेज थे। यह कांग्रेस की देन है कि आज 140 कॉलेज खुले हैं, 15 यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं और टेक्निकल यूनिवर्सिटी खुली है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया वाइंड अप करें।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : जब आप वहां फर्स्ट प्राइज़ लेने जाते हैं तो वह सब कांग्रेस की नीतियों के कारण है। कांग्रेस के कार्यक्रमों के कारण साबित हुआ है। तभी आपको फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। आपकी सरकार तो पहली बार 1998 में बनी थी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ और वह भी श्री अनिल शर्मा जी के पति जी की बदौलत बनी थी और अब आप खुले दिल से आए हैं। हमने कर्ज़ा लिया तो हमने प्रदेश के विकास में लगाया। लेकिन आपने दो साल में 9000 करोड़ रुपया कर्ज़ा ले लिया है और आने वाले सालों में आप हिमाचल के प्रत्येक व्यक्ति पर एक लाख रुपया का कर्ज़ा चढ़ायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।

14.03.2020/1250/SS-HK/2

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री रमेश चंद ध्वाला जी भाग लेंगे।

श्री रमेश चंद ध्वाला (ज्वालामुखी) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री ने 6 मार्च, 2020 को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमान रखे, मैं भी उसके ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। विपक्ष ने तो कहा कि जो कुछ किया है वह उन्होंने किया है। ठीक है आपने भी कुछ किया होगा लेकिन जितने बी0जे0पी0 की सरकार में काम हुए हैं उतने काम अगर आपने किये होते तो आज हिमाचल बुलंदियों पर होता।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज मित्रों को भी खुश करूंगा। खास करके कल मैडम (श्रीमती आशा कुमारी जी) जी नाराज हो गई थीं, अगर ऐसे कोई शब्द मेरे छोटे भाई (श्री नरेन्द्र ठाकुर) ने

बोल दिये होंगे तो हम उसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन आज मैं अपने मित्रों को भी खुश करूंगा। माननीय मुख्य मंत्री की तरफ इशारा करते हुए शेर अर्ज है:-

"आपकी तारीफ में हम भी कुछ बोलना चाहते हैं,
आपकी तारीफ में हम भी कुछ बोलना चाहते हैं;
मगर आपकी तारीफ क्या कर सकते हैं इतनी,
मगर आपकी तारीफ क्या कर सकते हैं इतनी;
काबलियत हमारे अल्फाज़ों में कहां है।"

...(व्यवधान) ऐसी बात नहीं है, मैं पहले ही मंत्री हूं। आपको शायद कोई गलतफहमी है। आपने बहुत कुछ बोला है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह पूर्णतः करमुक्त बजट है तथा इसमें प्रदेश के विकास की तरफ पूरा ध्यान दिया गया है। आप इस बात को माने या न माने। 100 रुपये में से 41.22 रुपये विकास कार्यों पर खर्च करने का प्रावधान है जोकि आज तक इतिहास में सर्वाधिक है। अध्यक्ष महोदय, बजट में खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा फोकस किया है। शिक्षा के क्षेत्र में 8016 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हेतु 2702 करोड़ रुपये तथा आयुर्वेद में 307 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। भिन्न-भिन्न सिंचाई योजनाओं हेतु 1024 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आगे घटती कृषि योग्य भूमि तथा बढ़ती आबादी सम्पूर्ण देश के लिए चिन्ता का विषय है। जहां पहले फसलें सड़क के किनारे लहलहाती थीं आज वहां बड़े-बड़े मॉल बन गए, दुकानें बन गईं और बड़े भव्य मकान बन गए। जारी श्रीमती के0एस0

14.03.2020/1255/केएस/एचके/1

श्री रमेश चंद ध्वाला जारी---

इसलिए ये जो कृषि की ओर बजट में प्रावधान किया गया है, मैं मुख्य मंत्री जी को इस बात की बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि

खुद की बुराई हम कैसे करें, इसका ठेका तो विरोधियों ने ले रखा है,
खुद की तारीफ़ कैसे करें, इसका ठेका हमने लोगों को दे रखा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि यह ठीक है कि आज बेरोज़गारी है, इन्होंने कहा कि 10 लाख बेरोज़गार है। अध्यक्ष जी, मेरे घर से भी 4 बच्चे घर पर ही रहकर अपना काम धंधा करते हैं लेकिन उन्होंने इम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज करवाया हुआ है। आजकल कम्प्यूटर का युग है, बच्चे कोई न कोई काम धंधा तो कर रहे हैं लेकिन जो आप इतनी दुहाई दे रहे हैं कि 10 लाख बेरोज़गार घूम रहे हैं, मैं यह कहना चाहूंगा और मैं अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो लोग गांव को छोड़कर शहर की तरफ़ जा रहे हैं, वे तो शहर में कोई न कोई रिसोर्सिज़ अपना लेते हैं। उनको शाम की या महीने की आमदनी हो जाती है। लेकिन अगर गांव में हम कोई काम-धंधा करते हैं, अगर केसर, हींग व चंदन की खेती की ओर प्रदेश के युवाओं का रुझान होगा तो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हम समिति के माध्यम से टूअर पर गए थे, हमने कर्नाटक और केरल में जा कर देखा, कर्नाटक में इतने अच्छे रिसोर्सिज़ हैं कि वहां पर सफेद व लाल चंदन का तेल भी बिक रहा है। यहां पर भी 10 हजार रुपये किलो चंदन बिक रहा है। हमें वहां बताया गया कि जिस व्यक्ति ने 100 पेड़ चंदन के लगाए हैं, 15 साल के बाद उसको डेढ़ करोड़ आमदनी होगी। तो जो नौकरी में लगेगा, क्या उसकी डेढ़ करोड़ आमदनी हो सकती है? हमारे निचले क्षेत्रों में चंदन और खैर से बहुत ज्यादा आमदनी हो सकती है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, प्राइवेट मैम्बर डे में मैंने डिस्कशन भी मांगी है और मैं तो यह कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश का कर्जा जिला कांगड़ा ही अदा कर देगा लेकिन उसमें ग्रीन फैलिंग पर कोर्ट की इंटरफेरेंस है। श्री राकेश पठानिया जी के एक सेक्शन से 6 करोड़ रुपया आएगा। अभी कटाई चली हुई है, अभी तो एक सेक्शन को ट्रायल बेस पर दिया गया है । हमारे जो अधिकारी हैं, बुरा मत मानना लेकिन अगर कहीं फोरैस्ट की जमीन पर जाते हैं तो फोरैस्ट वाले

14.03.2020/1255/केएस/एचके/2

वहां खड़े नहीं होने देते। खड्ड में जाते हैं तो माइनिंग वाले खड़े नहीं होने देते। अगर कहीं और जगह जाते हैं, तो वहां भी यही हाल है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बिना people participation के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों को अपने साथ मिलाएं, उनको

समझाएं और अगर इतना प्रबन्ध माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने किया है कि पानी खेतों तक जाएगा, तभी सूखे खेतों में कुछ न कुछ पैदा होगा।
श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

14.03.2020/1300/av-yk/1

श्री रमेश चंद ध्वाला----- जारी

पानी खेतों में जायेगा तभी जाकर उन सूखे खेतों में कुछ उगेगा। हम अगर जंगल में जाएं तो फोरैस्ट और माइनिंग वाले सारे तंग करते हैं। मैं यहां पर रिसोर्सिज की बात कर रहा हूं और इस बारे में किसी भी सदस्य ने बात नहीं की है। हमने केरल और कर्नाटक में देखा कि वहां पर लोगों ने कॉफी की बहुत ज्यादा बिजाई की होती है। इसके अतिरिक्त वहां पर नारियल और केले का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। वहां लोग उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो क्या हमारे लोग मेहनत नहीं कर सकते। मगर हमारे लोगों में इस संदर्भ में जागृति नहीं है और इनको जागरूक करने के लिए अगर हम तथा आप कोशिश करेंगे तो हमारा हिमाचल प्रदेश भी समृद्ध व सुदृढ़ होगा। इससे बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा वरना यहां पर रोज़गार के और कोई साधन उपलब्ध नहीं है। वहां टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इन्कम है। हमारा जो पौंग डैम एरिया है वहां बहुत ही फर्टाइल ज़मीन है। लेकिन वहां पर फोरैस्ट वाले नहीं बैठने देते। अगर वहां पर कोई तम्बू लगाकर बैठता है तो उसको वन विभाग वाले उठा देते हैं। इसलिए ऐसी कोई नीति बननी चाहिए और अगर नीति बनेगी तो उससे हमारे बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार मिल सकता है। वहां पर ईको टूरिज्म है तथा लोग वहां एक रात का 10-10 हजार रुपये कमा रहे हैं। ईको टूरिज्म के तहत उन्होंने पहाड़ी कल्चर के स्ट्रक्चर तैयार करके बड़े-बड़े रिज़ोर्ट बनाए हुए हैं। मैंने वहां समुद्र में जाकर 3500 रुपये फोरफिट करवाए क्योंकि मुझे डुबकी लगानी नहीं आई। नरेन्द्र ठाकुर जी तथा दूसरे माननीय सदस्य तो काफी दूर तक गये मगर मैंने सोचा कि मुझे नहीं मरना। मेरे कहने का मतलब यह है कि वे टूरिज्म के अंतर्गत बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। हमारे यहां पर भी ऐसे बहुत सारे रिसोर्सिज हैं। अगर हम पौंग डैम में टूरिज्म

प्वाईंट ऑफ व्यू से बोट चलाना चाहते हैं तो उसके लिए परमिशन नहीं मिलती है। अगर उस प्रकार की परमिशन मिलती है तो उससे हमारे बच्चों को रोज़गार मिल सकता है। इसलिए आप लोग जो यहां पर लड़ाई-झगड़ा करते रहते हैं, मुझे नहीं मालूम आप लोग कहां से ऐसी-ऐसी बातें लाते हैं; ...(व्यवधान) नहीं, अगर तो कोई बात हो फिर तो हम भी आपके साथ है। लेकिन

14.03.2020/1300/av-yk/2

जब राम भगवान और रावण की लड़ाई हो रही थी तो रावण वहां पर मूर्छित हो गये। वहां राम ने लक्ष्मण को कहा कि जाओ और कोई शिक्षा लेकर आओ। लक्ष्मण जी गये और रावण के सिर की तरफ जाकर खड़े हो गये, इस पर रावण ने कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण के वापिस जाने पर जब राम ने पूछा कि क्या शिक्षा लेकर आये तो उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं। इस पर राम भगवान ने पूछा कि आप खड़े कहां थे तो बताया गया कि सिर की तरफ खड़ा था। इस पर राम भगवान ने कहा कि आपको पांव की तरफ खड़े होना चाहिए था। फिर वे खुद गये और रावण ने उनको कहा कि देखो मैं इतना बड़ा योद्धा और विद्वान था तथा मेरे पास सोने की लंका थी। लेकिन आपका अपनों ने साथ दिया और मुझे अपनों ने ही धक्का दिया। अब आपके अपने ही साथ छोड़कर चले जाएं तो इसमें हमारा क्या दोष है। ...(व्यवधान) बाकी सब बढ़िया चला हुआ है। इस सरकार ने जो किया है वह आज दिन तक कभी नहीं हुआ। इस बजट के माध्यम से हर वर्ग को टच किया गया है। हमारा यह दायित्व बनता है और हमारे तथा आपके सहयोग से हिमाचल में एक क्रान्ति आ सकती है।

टी सी द्वारा जारी

13.03.2020/1305/TCV/YK-1

श्री रमेश चंद ध्वाला... जारी

हिमाचल प्रदेश के युवाओं को बाहर जाकर नौकरी ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं हैं। कुल्लू में जो रिवर राफ्टिंग चल रही है, वह हमारे नदौन में भी चल सकती है लेकिन हमारे मित्र इस प्रकार का कोई सुझाव नहीं देते हैं। वे ऐसी-ऐसी बातें खोज कर लाते हैं जिससे यहां सदन में माहौल ही ख़राब हो जाये। यदि हम योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे, हमारे जो अधिकारी हैं, ये 10-15 लाइनें अंग्रेजी की बोल कर चले जाते हैं और उसके बाद मौके पर कुछ नहीं होता है। इसलिए इनके सहयोग व मार्गदर्शन की भी ज़रूरत हैं। हमारे युवाओं का प्रदेश से बाहर जाने का एक ही कारण है कि उनको यहां पर रोज़गार पाने के लिए मोटिवेट नहीं किया जाता है। जब जम्मू-कश्मीर में केसर और हींग हो सकता है तो क्या हमारे निचले इलाकों में चंदन नहीं हो सकता है? मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसके लिए कोई नीति बनाई जाये और इसको लीगेलाइज़ किया जाये। आज भी हमारे इलाके में इसको बेचा जा रहा है और यह 7000 किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है। हमारे क्षेत्र में चंदन का कोई भी बड़ा पेड़ नहीं रहा है। यदि हर कंस्टिच्यूंसी में इसकी नर्सरी लगाई जाये और वन विभाग के अधिकारी वहां जाकर मोटिवेट करें कि यह पेड़ कैसे लगना है तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। हमारे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 500 पेड़ तुनी के लगाये हुए हैं और आज नहीं 20 साल पहले लगाये थे। उसको इनका 5 करोड़ रुपया आज ही दे रहे हैं। क्या जो नौकरी करने बाहर जाएगा उसको 5 करोड़ रुपया मिल जाएगा? यदि युवाओं को मोटिवेट किया जाये तो इस हिमाचल प्रदेश का उत्थान हो सकता है लेकिन टीका-टिप्पणी करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि विरोध, विरोध के लिए ही करना चाहिए लेकिन ठीक बात का भी विरोध करना गलत बात है। आपको गुस्सा किसी और बात का होता है, वह आपकी लीडरशिप है, उसमें हम क्या कह सकते हैं? मैं तो यह कहना चाहूंगा कि 'मुद्दतों से उस पूंछ को पकड़ कर चले हुए हैं, अब तो अंत होने वाला है।' इसलिए उस पूंछ को छोड़ दो और कोई नया नेतृत्व ढूंढें तब जाकर इस पार्टी का भला हो सकता है। मैं एक शेर कहना चाहूंगाः-

13.03.2020/1305/TCV/YK-2

तारीफ़ वही बड़ी जो निकले दुश्मन की जुबां से,
अपने तो दिल रखने के लिए दो लफ़्ज कह देते हैं।

अगर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा तो आप बाहर चले जाएंगे और मैं आपको बाहर नहीं भेजना चाहता हूं।

श्री आर0के0एस0 द्वारा ... जारी

14.03.2020/1310/RKS/AG-1

श्री रमेश चंद ध्वाला... जारी

लफ्ज़ तो मेर पास ऐसे-ऐसे हैं अगर मैं उन लफ्ज़ों को बोलूं तो आप बाहर चले जाएंगे। लेकिन इस विधान सभा की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। 'विधायक निधि 1.10 करोड़ रुपये की गई है'। 'विधायक प्राथमिकता योजना की धनराशि सीमा को 80 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 120 करोड़ रुपये किया गया है'। 'सामाजिक सुरक्षा पैंशन को 750 रुपये से बढ़ाकर 1 हजार रुपये किया गया है'। 'विधायक क्षेत्र विकास निधि को बढ़ाकर 1.75 करोड़ रुपये किया गया है'। 'विधायक ऐच्छिक निधि को 1.10 करोड़ रुपये किया गया है'। 'वृद्धों को पैंशन प्रदान करने हेतु उनकी आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया गया है'। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं से 5,34,000 लोगों को फायदा हुआ है और 50 हजार पात्र लोगों को इसके दायरे में लाया जा रहा है। 'आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 500 रुपये बढ़ाया गया है'। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धों को मुफ्त दवाई वितरण की जाएगी और इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 'इस वित्तीय वर्ष में 20,000 रिक्त पद भरे जाएंगे'। '1800 किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण किया जाएगा'।

अध्यक्षः माननीय सदस्य आपने काफी विस्तार से अपनी बात रखी है, कृपया वाइंड-अप करें।

श्री रमेंश चंद ध्वालाः सर, मैं बहुत महत्वपूण बात कर रहा हूं। 75 पुल व 90 गांवों को सड़क से जोड़ा गया है। 1 लाख घरों को पानी के कनैक्शन्ज दिए जाएंगे। वर्ष 2024 से पहले प्रदेश के सभी घरों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी निवेदन करना चाहूंगा कि चंदन के वृक्षों लिए कोई नीति बनाई जाए ताकि कोई भी व्यक्ति अपना पेड़ सही तरीके से बेच सके। ये पेड़ चोरी-छुपे बिक रहे हैं और इनके दाम भी कम मिल रहे हैं। अतः मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इसके लिए नीति बनाई जाए। पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु रोपवेज और हैलिपैड का निर्माण किया जा रहा है। कांगड़ा, शिमला हवाई अड्डों का विस्तारीकरण किया

14.03.2020/1310/RKS/AG-2

जा रहा है और इसके लिए 1013 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान भी किया गया है। इस वर्ष पुलिस कॉंस्टेबल के 1 हजार पद भरे जाएंगे। अब मैं कहना चाहूंगाः-

गलतियां भी होगी और गलत भी समझा जाएगा,
यह जिंदगी है जनाब यहां तारीफ भी होगी और कोसा भी जाएगा।

मेर मित्र ---(***)--- यहां से चले गए। इन्होंने जो कहा है वह वे प्रश्न में भी कह रहे थे। ये कहते हैं

श्री बी.एस. द्वारा... जार

---(***)---अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

14.03.2020/1315/बी.एस./ए.जी./-1

श्री रमेश चन्द ध्वाला जारी...

Charity begins at home. हमारा अपना दामन कैसा है? इनका मैंने देखा है, इन्होंने भी वहां पर भूमि भरीदी है। वहां पर नैगोसिएशन होने जा रही है। एक बहुत बड़े हमारे मित्र वहां पर हैं। उसने ज्यादा खरीदी है। यह सारी बातें जो इन्होंने की हैं और इन्होंने यहां पर सीमेंट के बारे में कहा, वह हमारी सरकार के समय में महंगा नहीं हुआ है। इसकी बात मैं विस्तार से बताना चाहता हूं,

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अपनी बात बहुत विस्तार से रख चुके हैं। कृपया समाप्त करें।

श्री रमेश चन्द ध्वाला : पंजाब में सीमेंट के साथ मिट्टी को मिलाया जाता है और वहां पर और भी एजेंसियां सीमेंट सप्लाई करती हैं। इसलिए पंजाब में सीमेंट सस्ता है और हिमाचल प्रदेश में महंगा है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो मर्जी कहें परंतु यह बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के लिए, मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए पेश किया है मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चर्चा के दौरान मेरा नाम लिया है इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आदरणीय ध्वाला जी ने आपका नाम नहीं लिया है। आदरणीय सुख राम जी का नाम लिया था।

श्री रमेश चन्द ध्वाला : मैंने लिया है।। can give you solid proof. मैं ठोस सबूत दूंगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं और जिसकी गवाही की बात कर रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए।

14.03.2020/1315/बी.एस./ए.जी./-2

---(***)--- कोई चीज रखने से पहले कागज़ ले होने चाहिए।

श्री रमेश चन्द्र ध्वाला : आपने रिश्तेदार के नाम भी जमीने ले रखी है।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : लो जी, अब रिश्तेदार का नाम आ गया है। अगर ईमानदारी के पैसे से जमीन खरीदना जुर्म है तो इस विधान सभा में बैठे हुए जितने भी व्यक्तियों ने जमीन खरीदी है उन्होंने जुर्म किया है। ध्वाला जी आप तो ठेकेदार है। आप क्या सप्लाई करते थे दुनिया को पता है। ---(***)--- मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं , ये तो सप्लायर थे कितना क्या करते थे हमें सब पता है। मुख्य मंत्री महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ध्वाला साहब ने जो मुझ पर आरोप लगाए हैं ..(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह अनुरोध रहेगा कि इस बात को या तो एक्सपंज किया जाए या यहां पर प्रूफ को ले किया जाए। यदि जमीन गलत तरीके से खरीदी है तब है, जमीन सही तरीके से खरीदी है तो अच्छी बात की है न? आप कृपया इस बात को एक्सपंज करें। अध्यक्ष महोदय, हमारा सवाल यह नहीं है, ध्वाला जी आपके ऊपर तो सप्लाई का केस बना था, जब आप ठेकेदारी करते थे आपके ऊपर केस बना था।

श्री रमेश चन्द ध्वाला : क्या मैंने बेइमानी की थी ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठ जाइए, आपकी बात आ गई है।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : सर, बात आ गई है परंतु किसी की ईमानदारी पर अंगुली उठाना भी गलत बात है। मैंने जमीन खरीदी, एफिडेबिट में जमीन है, पिछले 20 साल से हमारे नाम पर है, 25 साल से है। मेरा भाई, मेरी पत्नी जो अपने दम पर खरीद सकता है वह खरीद सकता है। इसमें क्या दोराय है क्या कोई चोरी से या करप्शन से खरीदी है---(***)--- श्री डी.टी.द्वारा जारी...

---(***)---अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

14.03.2020/1320/DT/AS-1

श्री रमेश चंद ध्वालाः माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों को जब यह पता चला की यहां पर प्रोजेक्ट लगेगा तो कुछ लोगों ने कोड़ियों के भाव वह जमीन भेज दी। ...(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य महोदय, कृपया आप बैठ जाऐं। आप अब मत बोलें मैं इस पर व्यवस्था दे रहा हूं। जो माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी है, इसमें कोई भी असंसदीय शब्द उन्होंने नहीं कहे। आपके ध्यानार्थ मैं लाना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने कहा कि आपने जमीन खरीदी है। कोई गलत तरीके से नहीं खरीदी है। जमीन खरीदी है, कहां खरीदी है, कब खरीदी है, यह उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि यह जमीन गलत तरीके से खरीदी है। इसलिए शब्दों की गहराई में जाना बहुत जरूरी है। यह नहीं कहा है कि गलत तरीके से खरीदी है। ...(व्यवधान) इन्होंने ऐसा नहीं कहा। ...(व्यवधान) गलत तरीके का इसमें कहीं जिक्र ही नहीं आया है। माननीय सदस्य, ...(व्यवधनान) आप बैठ जाईये मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री सुखविन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, आप श्री रमेश ध्वाला जी को प्रोटेक्ट कर रहें हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य ऐसा नहीं हैं, मैं आपको भी प्रोटेक्ट कर रहा हूं। आप कृपया सुनिए। एक तो उन्होंने कही गलत तरीके से जिक्र नहीं किया है। इस मानीनय सदन में हम क्या बोलतें हैं थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। आपने कहा ---(*******)--- ...(व्यवधनान) इन शब्दों को एक्सपंज किया जाता है। ...(व्यवधान)

---(***)---अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गए।

14.03.2020/1320/DT/AS-1

श्री सुखविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने जो मानसिक सन्तुलन वाली बात कही है, वह शब्द मैं वापिस लेता हूं। लेकिन श्री रमेश ध्वाला जी द्वारा भी मेरे बारे में गलत बात कही गई है।

अध्यक्षः कौन सी बात कही है इन्होंने? ...(व्यवधान) गलत तरीके का तो जिक्र ही नहीं हुआ है यहां पर। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य महोदय इन्होंने आपका नाम नहीं लिया यहां पर कहा गया ---(***)---इसलिए नाम को भी कार्रवाई से निकाला जाता है। आपका नाम नहीं लिया है, ---(***)---

अब इस सदन की कार्यवाही दोपहर के भोजन के लिए 2:00 बजे तक स्थगित की जाती है।

---(***)---अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

14-03-2020/1410/डी.सी.-एन.जी./1

माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत अपराह्न 02.10 बजे पुनः आरम्भ हुई।

अध्यक्षः अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी भाग लेंगे।

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमान इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया गया है मैं उस पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका धन्यवाद। पहली बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने थोड़ी ईमानदारी और थोड़ी जिम्मेवारी के साथ इस बात को माना है कि आज जिन बुलन्दियों पर हिमाचल प्रदेश पहुंचा है वह कांग्रेस के कारण हुआ

है। इस बात को आप बाहर भाषणों में नही बोलेंगे परन्तु इस बजट बुक के प्रथम पृष्ठ पर बड़े साफ शब्दों में आपने इस बात को कहा है। लेकिन यहां पर भी आपने थोड़ी कंजूसी की है। जिन महान हस्तियों ने इस प्रदेश को बनाने में अपना सहयोग किया उसमें पंडित जवाहर लाल नेहरू जी, डॉ0 यशवंत सिंह परमार जी, राजा वीरभद्र सिंह जी और उनके बाद ठाकुर राम लाल जी, श्री शांता कुमार जी व श्री प्रेम कुमार धूमल जी, उन सब का नाम यहां पर नाम नहीं लिया गया। काश उनका नाम भी यहां पर लिया जाता तो इस प्रथम पृष्ठ पर थोड़ा वजन अधिक पड़ जाता। फिर भी कोई बात नहीं, आपने इतना तो माना कि आज हिमाचल प्रदेश कई मायनों में पूरे देश में नम्बर-1 है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रति व्यक्ति आय आदि। 50 वर्ष के छोटे से सफ़र में यह बहुत बड़ी कामयाबी है। मुझ से पूर्व मेरे साथियों ने बड़े विस्तार से और बड़े सुन्दर शब्दों में जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश 1948 में कितना था, 30 छोटी-बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश बना, इसके बारे में विस्तार से मेरे साथी बता चुके हैं जिसे मैं दोहराना नहीं चाहता। उस समय हिमाचल में 248 किलोमीटर कुल सड़कें थी और आज 34,000 किलोमीटर सड़के हम बना चुके हैं। उस समय दर्जन भर स्कूल होते थे, कोई कॉलेज भी नहीं था और हिमाचल के बच्चों को कॉलेज के लिए लाहौर जाना पड़ता था लेकिन आज 130 से ज्यादा कॉलेज बने हैं,

14-03-2020/1410/डी.सी.-एन.जी./2

10 हज़ार से ज्यादा प्राथमिक स्कूल हैं, 3 हजार से ज्यादा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, हाई स्कूल और इतने ही मिडल स्कूल बने हैं। आज घर-घर में पानी है। उस समय बिजली केवल शिमला और मण्डी में हुआ करती थी, हिमाचल पूरे भारत में कांग्रेस के समय बिजली के क्षेत्र में नम्बर-1 पर भी रहा है। आज हम बहुत आगे पहुंचे हैं और उस सब के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 50वीं जयन्ती मानने का बहुत अच्छा फैसला लिया है इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। जिसने हिमाचल प्रदेश को बनाया उसमें खासकर श्रीमती इन्दिरा गांधी जी और हमारे डॉ0 यशवंत सिंह परमार

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी....

14/03/2020/1415/MS//1

श्री जगत सिंह नेगी जारी------

उनकी प्रतिमा हमारे विधान सभा के परिसर में यहां लगे ताकि यह उनके लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि हो। जहां तक बजट की बात है, यह इस वर्तमान सरकार की बहुत बड़ी मजबूरी हो गई है। अब कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले दिल्ली वालों का गुणगान गाना बहुत जरूरी हो गया है। जब तक मोदी जी के गुणगान नहीं गाएंगे तब तक आपका कोई कार्यक्रम नहीं चलेगा। जैसे मंदिर में जाकर जब तक सवा रुपये का प्रसाद नहीं चढ़ाते तब तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। ठीक है, आपने मोदी जी का गुणगान किया है। ...(व्यवधान) जब विनोद जी आप बोल रहे थे, मैंने आपको बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं किया। वैसे भी आप किसी दूसरे की सीट पर बैठकर तो बोल ही नहीं सकते। अध्यक्ष जी, आप इसके लिए व्यवस्था दीजिए। इन्होंने मोदी जी का धन्यवाद किया कि वे तीन बार हिमाचल में आए और मोदी जी ने कहा कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है। ऐसा है, जब मोदी जी झारखण्ड में जाते हैं तो वहां भी ऐसा ही बोलते हैं और जब यू0पी0 या दूसरी जगह जाते हैं, तब भी ऐसा ही कहते हैं। पता नहीं किस-किस का कौन-कौन सा घर है। परन्तु हमारा घर तो उन्होंने बर्बाद कर दिया है। वे यहां तीन बार आए और इस गरीब प्रदेश का करोड़ों रुपया बर्बाद करके चले गए। ठीक है, आपने धन्यवाद किया कि इस बजट में 19000 करोड़ रुपये मोदी जी की देन है। हमने भी वित्त आयोग का धन्यवाद किया। लेकिन आप असली कहानी बताते नहीं हैं। आपको जो पेसा केंद्र से आता है, वहां मोदी जी का अटैची में रखा हुआ कोई ख़जाना नहीं है कि हमारे मुख्य मंत्री जी दिल्ली गए और वे वहां से ख़जाना निकालकर इनको दे देते हैं कि हैलिकॉप्टर में डालकर ले जाओ। ऐसे पैसा नहीं मिलता है। उसके लिए नियम बना हुआ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद-280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना होती है और उसे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यह कोई पहला वित्त आयोग नहीं है। इससे पहले 14वां वित्त आयोग था और अब यह 15वां वित्त आयोग है। वित्त आयोग ने देश का पैसा जो रेवेन्यू और कस्टम इत्यादि से आता है तथा जो कन्सोलिडेटिड फण्ड ऑफ इण्डिया होता है, उसको बांटने का एक फॉर्मूला इजाद किया

हुआ है। वह फॉर्मूला कोई हिमाचल या किसी दूसरे राज्य के लिए नहीं है बल्कि वह पूरे भारतवर्ष के लिए है। उस फॉर्मूले के तहत कुछ पैरामीटर्ज दिए हुए हैं और उन पैरामीटर्ज के तहत हमें पैसा मिलता है। अभी ज्यादा समय नहीं है जब दुबारा समय मिलेगा तो मैं वित्त आयोग के बारे यहां विस्तृत रूप से विचार रखूंगा। परन्तु मैं आपकी जानकारी के लिए यहां कहना चाहूंगा कि जो पैरामीटर्ज रखें है, उसमें सबसे बड़ा काम 14वें वित्त आयोग ने किया

14/03/2020/1415/MS//2

है। क्योंकि पहले परिस्थितियों के हिसाब से वित्त आयोग फॉर्मूला इजाद करते हैं और पैसा बांटने का नियम बनाते हैं। पहले राजस्व के डिविजिबल पूल में राज्यों का हिस्सा 32 परसेंट था, उसको बढ़ाकर 14वें वित्त आयोग ने 42 परसेंट कर दिया। जब ऐसा हुआ तो उसका फायदा हिमाचल और पंजाब को भी हुआ है। फिर उसके साथ आगे जो इन्होंने सिफ़ारिशें की हैं; आप जैसे कहते हैं कि हमने पंचायती राज संस्थाओं के लिए अलग से प्रावधान किया है तो ऐसा कुछ नहीं किया है। यह भी 14वें वित्त आयोग ने कहा है कि 2 लाख 88 हजार करोड़ रुपये का अनुदान का प्रावधान किया है। जो इन्होंने पैरामीटर्ज लगाए हैं, उसमें नम्बर-1 पर जो पैरामीटर है, उसमें यह जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में राजस्व घाटे को देखा जाता है। आपका फॉरैस्ट एरिया कितना है और आपकी जनसंख्या कितनी है, ये 4-5 पैरामीटर्ज लगाकर तब हमें पैसा मिलता है। उसके कारण हमें पैसा मिला है। अभी आपने यहां बड़े जोश में कह दिया कि हमें इस बार 19000 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से मोदी जी की मेहरबानी से मिले हैं। यह बिल्कुल गलत बात है। यह पैसा जो हमें मिल रहा है यह मोदी जी के कारण नहीं मिल रहा है बल्कि 14वें वित्त आयोग की जो रिकमेंडेशन्ज हैं उनके कारण मिल रहा है। इसमें भी मैं कहना चाहूंगा, हालांकि मैं गलत हो सकता हूं लेकिन जो आंकड़े आपने यहां प्रस्तुत किए हैं उसमें और जो मेरे पास आंकड़े हैं, उनमें कुछ फ़र्क है। आप 19000 करोड़ रुपये लेकर चले हुए हैं परन्तु मेरे सामने तो यह आंकड़ा 18 हजार कुछ करोड़ रुपये का बनता है। यहां भी मुझे नहीं लगता कि आपके आंकड़े सही हैं।

15वें वित्त आयोग में भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो 42 परसेंट है उसमें से एक परसेंट और कम कर दिया है। अब हमें 41 परसेंट मिलेगा और हम 14-15 राज्य हैं जिनका रेवेन्यु डेफिसिट है। वह एक परसेंट कहां जा रहा है, वह जम्मू-कश्मीर के लिए जा रहा है। जहां आपने धारा-370 को हटाया है, उन लोगों को आप हमारा पैसा देने लगे हैं। आपको उसकी चिन्ता नहीं है। वह बात आपने छिपाई हुई है। सबसे बड़ी बात यह हुई,

जारी एस0एस0 द्वारा------

14.03.2020/1420/SS-HK/1

श्री जगत सिंह नेगी क्रमागत :

कि आप जो 19 हजार करोड़ रुपया दिल्ली से आने की बात कर रहे हैं वह आने वाला नहीं है। अभी दिल्ली का जो हमारा केन्द्र का बजट पास हुआ उसमें हमारे जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने हिमाचल को रेवेन्यू डैफिसिट के जो मु0 11000 करोड़ रुपये मिलने हैं या दूसरी स्टेट को मिलाकर कुल 78 हजार करोड़ रुपये मिलने हैं उसका उन्होंने केवल 14 परसैंट देना माना है। तब हम ओर मारे गए। आपने मु0 11000 करोड़ की प्रोजैक्शन की है जोकि दिल्ली से आना है। उसका 14 परसैंट करके आप 6 हजार करोड़ रुपये पर आ गए। 12500 करोड़ रुपये का जो आपने कर्ज़ लिया हुआ है उसमें और इजाफा हो जायेगा। 6 हजार करोड़ रुपया और आपके सिर चढ़ जायेगा। इसलिए ये जो फाइनेंस की बातें हैं इनको जनता से छुपाकर हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरे साथी, श्री हर्षवर्धन जी ने ठीक कहा कि आपको श्वेत पत्र यहां रखना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पता लग जाए कि हम कहां हैं, किधर जा रहे हैं। इसकी हमें चिन्ता करने की ज़रूरत है। इसलिए आपका फाइनेंस कमीशन को धन्यवाद करना कहां तक सही है। चलो धन्यवाद कर दिया तो कोई बात नहीं। वह केवल हमारी रिक्मेंडेशन पर नहीं हुआ। पूरे हिन्दुस्तान में घूमें, उन्होंने सभी स्टेटों की पॉजिशन देखी। तब उन्होंने यह सिफारिश की है और वह स्पेशल ग्रांट जिसके बारे में आप सोचते हैं वह हमें नहीं मिलने वाली है। 15वें वित्तायोग ने स्पेशल ग्रांट के लिए भी फार्मूला इज़ाद किया हुआ है। जिनको रेवेन्यू डैफिसिट नहीं है, जहां उनको पैसा नहीं मिल रहा है, उन स्टेट्स में हमारा नाम नहीं है। अब तो हम स्पेशल ग्रांट से भी रह गए। हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। मोदी जी हमें झुनझुना देने वाले हैं और दे भी चुके हैं हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए यह मोदी गुणगान करना हमारे प्रदेश हित में नहीं है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि जहां तक इस बजट की बात है यह बजट जिस तरह से बनाया गया है, अभी बहुत तारीफ हुई, कई घंटे इसकी तारीफ में न जाने क्या-क्या बोला गया, शेरो-शायरी हुई परन्तु यह हमारे प्रदेश के लिए एक बोझ है। इतना बड़ा बोझ है कि जिस दिन 2022 में माननीय जय

राम ठाकुर जी की सरकार जायेगी उस दिन आप यह बोझ हमारे ऊपर छोड़कर जाओगे। अब तो मैं कहता हूं कि एक लाख करोड़ रुपये का कर्ज़ा हमारे ऊपर छोड़कर जायेंगे। आपने किया क्या है? यह तो कोई भी कर लेता। सॉफ्टवेयर तैयार कर लेते कि हमारे पास इतना उधार

14.03.2020/1420/SS-HK/2

का है इतना वो है और उसे उसमें डाल देते कि यह फॉरैस्ट डिपार्टमैंट के लिए है, यह फलां डिपार्टमैंट के लिए है तथा उसमें मार्क कर देते कि हमने हवाई अड्डे को 1000 करोड़ रुपया देना है और बाकी को झुनझुना देना है। एक सैकिण्ड में सारा डाटा निकल आना था। आपने तीन घंटे हमें तो परेशान किया ही बल्कि आपके पीछे बैठे मंत्री पांचवें मिनट में ऊब गए। आपकी शेरो-शायरी उनको जगाने में काम नहीं आई। जो उबासियों उन्होंने ली हैं उसे पूरे हिमाचल ने देख लिया है। वे भी मान गए कि इस बजट में है ही कुछ नहीं। ...(व्यवधान) आपने वीडियो देख लेना कि कौन-से मंत्री सोये थे, मैं उनका नाम नहीं लेता। It is in the public domain. मेरे पास नहीं है बल्कि वह पब्लिक डोमेन में है। आप देख लेना कि कौन-कौन सोये हुए थे। फिर अगर मैं मुहावरा कह दूं कि चोर की दाड़ी में तिनका तो फिर हल्ला पड़ जायेगा। इसलिए मैं यह बात नहीं कहता। यह जो बजट है यह ठीक है कि हर गवर्नमैंट डेली वेजर्ज़ के पैसे बढ़ाने के लिए प्रयास करती है। परन्तु डेली वेजर्ज़ को हम आजकल दे क्या रहे हैं? 300 रुपये से नीचे दे रहे हैं, वह कम-से-कम 500 रुपया होना चाहिए था। मिड डे मील वर्कर्ज़ हैं, दूसरे आपके आशा वर्कर्ज़ हैं, डेली वेजर तो हमारे पास कम बचे हैं। पी0डब्ल्यू0डी0 में कोई नया डेली वेजर नहीं है। आपके आई0पी0एच0 में कोई नहीं है और डिपार्टमैंट में हैं नहीं। अब हमारे पास बेचारे आउटसोर्स वाले हैं। वे 60 हजार से ज्यादा हैं। अगर पैसा देना है तो उनको दो। उनके लिए पैसा बढ़ाओ। उनको सम्मानजनक पैसा दो। आप उस तरफ इसलिए आए हैं कि आपने दृष्टि पत्र में लोगों को धोखा दिया। आपने लोगों को गुमराह किया। आपने दृष्टि पत्र के द्वारा वायदा किया था कि हम हिमाचल को स्वर्णिम बनायेंगे। आज आपने हिमाचल को भस्म कर दिया। आज आपका बजट एक पंचायत के प्रधान के बजट से भी नीचे गया हुआ है।

जारी श्रीमती के0एस0

14.03.2020/1425/केएस/एचके/1

श्री जगत सिंह नेगी जारी---

आपने अपनी प्रायोरिटीज़ नहीं चुनी। हिमाचल का जी.डी.पी. एग्रीकल्चर से और बागवानी से बढ़ता है परन्तु आपने बागवानी और कृषि को एक पैसा नहीं दिया। ...(व्यवधान) मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि आपकी प्रायोरिटीज़ कहां है? आपकी प्रायोरिटीज़ गलत जगह हैं। आप हवाई अड्डा कहां बना रहे हैं, मण्डी के अंदर बना रहे हैं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, इनको मिर्ची क्यों लग गई? जब ये बोल रहे थे, हमने एक शब्द नहीं बोला। ...(व्यवधान) एक हजार करोड़ रुपये...(व्यवधान)

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को आप कहें कि नेगी जी को सुनें क्योंकि जब ये बोल रहे थे, हमने सुना। अब इनको क्या परेशानी हो रही है? ...(व्यवधान) सर, खासतौर पर मंत्रियों को। ये जो हमारे बच्छी और मच्छी मंत्री हैं, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जब माननीय उद्योग मंत्री जी बोल रहे थे तो ये 52 बार खड़े हुए। मतलब अपने ख़िलाफ ये एक शब्द भी नहीं सुन पा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से माननीय सदस्य बात कर रहे हैं, ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : जगत सिंह नेगी जी, कृपया आप इस चेयर को एड्रैस करें।

श्री जगत सिंह नेगी : अध्यक्ष महोदय, मैं कैसे बोलूं जब मेरे कानों में इनका इतना शोर आ रहा हैं।। need your protection. सर, आप कोई व्यवस्था करिए। मैं कैसे बोलूंगा अगर आप प्रोटैक्शन नहीं देंगे?

अध्यक्ष : मैं आपको पूरी तरह से सुरक्षा कवच दे रहा हूं परन्तु आप चेयर को एड्रैस करें। आप सीधा चेयर की तरफ देख कर बात करें।

श्री जगत सिंह नेगी : अध्यक्ष महोदय, मैं कैसे करुंगा, कैसे बोलूंगा? यहां अगर मच्छी मार्किट चलेगी तो मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं बोलना छोड़ देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो आपका संरक्षण चाहिए।

14.03.2020/1425/केएस/एचके/2

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा अब समापन की ओर है और बहुत अच्छी चर्चा हुई है। आज के दिन इनकी ख़बर नहीं बन रही है इसलिए ये भूमिका बना रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय नेगी जी, ट्राईबल से सम्बन्धित हैं और बाहर तापमान भी ठंडा है। ऐसी परिस्थिति में भी ट्राईबल एरिया का आदमी ऐसी बात करें, किसी क्षेत्र में डवलपमैंट का अगर कोई प्रोजैक्ट आता है, उसके बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं कि यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मंडी पूरे प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। सर्वे करने के बाद, हमने हिमाचल प्रदेश में कम से कम 7-8 जगह यह सारी एक्सरसाइज़ की और उसके बाद एयरपोर्ट का एक प्रोजैक्ट कहां हो सकता है, इसकी सम्भावना तलाशी। कांगड़ा एयरपोर्ट ऑलरेडी है। शिमला में भी ऑलरेडी है, वह छोटा है लेकिन इसके बड़ा होने की जितनी सम्भावना हो सकती है, हम कर रहे हैं। उसके बाद अगर तीसरी सम्भावना, हमारा जो टूरिस्ट डैस्टिनेशन है, पूरे हिमाचल प्रदेश का केन्द्र स्थान अगर है तो मुझे लगता है कि भौगोलिक दृष्टि से मण्डी ही है और वह टूरिस्ट डैस्टिनेशन को कनैक्ट करता है। टूरिस्ट डैस्टिनेशन को कनैक्ट करने के लिए अगर मण्डी का एयरपोर्ट बनता है तो मण्डी से कुल्लू के लिए सिर्फ एक घण्टे की यात्रा रह जाएगी और सवा घंटे में आप मनाली पहुंचेंगे क्योंकि 7 टनल्ज़ बीच में फोर लेन की बन रही हैं, वह महत्वपूर्ण है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

14.03.2020/1430/av-yk/1

मुख्य मंत्री ------ क्रमागत

हर बात को लेकर के इस प्रकार से टिप्पणी करना; ऊना वाले रेल को जा रहे हैं, हमीरपुर वाले रेल मांग रहे हैं और मण्डी में एयरपोर्ट आ रहा है यानी सब जगह कुछ-न-कुछ हो रहा है। अच्छा है, हम तो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।

14.03.2020/1430/av-yk/2

श्री जगत सिंह नेगी : अध्यक्ष महोदय, मण्डी मैं हवाई अड्डा बने; इस बारे में ऐतराज नहीं किया। मैंने कहा कि आपकी प्राथमिकता कृषि, टूरिज्म, उद्यान आदि क्षेत्रों के लिए होनी चाहिए। मण्डी में बने या कहीं दूसरी जगह बने; मैं तो यह कह रहा हूं कि हमारे पास पैसा कहां है। ...(व्यवधान) मेरा मण्डी के लिए ऐतराज नहीं है, मेरा ऐतराज तो माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा इस बजट में रखी गई प्राथमिकताओं के संदर्भ में है। हमारा प्रदेश आज पूरी तरह से कर्ज़ में डूबा हुआ है और हम कर्ज़ मांग कर अपना घर चला रहे हैं; फिर आप हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं। वहां से हवाई जहाज में कौन जायेगा, हवाई जहाज द्वारा कितने यात्री आयेंगे और उससे हमारा कितना विकास होगा? मुझे याद आ रहा है कि जब हुमायूं की शेरशाह के साथ लड़ाई हुई तो वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद गया। उसको डूबते-डूबते एक बिस्ति ने बचा दिया। बाद में जब हुमायूं दिल्ली के तख्त पर बैठा तो उसने उसको एक दिन का बादशाह बना दिया। फिर उसने चमड़े के सिक्के चला दिए; तो आप चलाइए, हवाई जहाज चलाइए और यहां पर लोग भूखे मर रहे हैं। प्रदेश में 2 लाख के लगभग लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं और आप हवाई जहाज में जाने की बात कर रहे हैं। आज प्रदेश के 2 लाख लोग गरीबी की हालत में है जिनको दो टाइम का खाना नसीब नहीं होता और आप हवाई जहाज की बात कर रहे हैं। आपने 28-29 करोड़ रुपये का उड़नखटोला खरीद लिया है। मारकण्डा जी फोन कर-करके थक जाते हैं कि मेरे फलां मरीज को जनजातीय क्षेत्र से निकालो परंतु उनको हैलीकॉप्टर नहीं मिलता।

उधर हमारे भरमौर के साथी परेशान होते हैं; उनको भी नहीं मिलता इसलिए मैं तो कभी मांगता ही नहीं हूं। ...(व्यवधान) डोडरा-क्वार को तो छोड़ दो, किसी की बात नहीं सुनी जाती। 29 करोड़ रुपये के हैलीकॉप्टर का भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है। मैं यहां पर प्राथमिकताओं की बात कर रहा हूं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मत बनाइए। अगर सरकार के पास पैसा है तो आप मण्डी में 10 हवाई अड्डे बना दीजिए। आप वहां पर कोई जगह मत छोड़िए, वहां आप एक रॉकेट खड़ा करने का स्टेशन बना दीजिए। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि हम हवाई किले बनाने की हालत में नहीं है,

14.03.2020/1430/av-yk/3

पहले प्रदेश की जनता को रोटी, कपड़ा और मकान तो मिले। आप खुद कहते हैं कि प्रदेश में 10,000 से ज्यादा लोगों के पास मकान नहीं है। उनको पहले मकान दीजिए उसके बाद उनको हैलीकॉप्टर में भेजना। ...(व्यवधान) आपके पास नहीं है। इसके अतिरिक्त, मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है क्योंकि आपने अपने दृष्टिपत्र में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में वित्तीय प्रबंधन खराब किया है। आप इसको अच्छा कीजिए, आप बेरोज़गारी खत्म करने का कोई तरीका निकालें। आपने 18 करोड़ रुपये का तम्बू लगाकर हमें एक इंवैस्टर मीट तो बता दी। 18 करोड़ रुपये के तम्बू में बैठने की क्या ज़रूरत थी? आप उस इंवैस्टर मीट को क्रिकेट स्टेडियम में भी करवा सकते थे। बढ़िया हो जाना था, आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं आए। ---(***)--- हमारा क्या हाल होता। आप आपस में ही साथ नहीं दे रहे तो हमारा क्या साथ देंगे। ...(व्यवधान) किसका साथ दे रहे हैं? हमारा तो नहीं दे रहे हैं। सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास; ...(व्यवधान) अगर लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न मिले तो ...(व्यवधान) यह ऐतिहासिक सदन है और यह बिल्कुल गलत है। पार्लियामैंट में सांसदों और विधान सभाओं में विधायकों को बोलने की अभिव्यक्ति सबसे बड़ा अधिकार है। अगर आपको उस पर भी रोक लगानी है तो हमें यहां किसलिए बैठना है। ...(व्यवधान) अंग्रेजों के ज़माने में भी इस तरह की पाबंदी नहीं थी। ...(व्यवधान) आप कैसे रोक रहे हैं? आप लोग

यहां पर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और हमें बोलने से रोकते हैं। आप हमें बोलने से कैसे रोक सकते हैं। ...(व्यवधान)

(पक्ष और विपक्ष; दोनों तरफ से कुछ सदस्य खड़े होकर शोरोगुल करने लगे।)

...(व्यवधान) अगर बोलने की आज़ादी खत्म कर दी जायेगी तो यह देश भी नहीं रहेगा। आप लोग संविधान की हत्या कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

टी सी द्वारा जारी

---(***)---अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गए।

14.03.2020/1435/TCV/YK-1

श्री जगत सिंह नेगी ... जारी

...(व्यवधान) आप क्या सोचते हैं कि हम बाहर चले जाएं। आज हम नहीं जाएंगे। हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं।...(व्यवधान) यह हमारा अधिकार है। ये सच्चाई सुन नहीं सकते हैं, इनको सच्चाई कड़वी लग रही है। सच्चाई से इनको जलन हो रही है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया सभी माननीय सदस्य, बैठ जाएं, प्लीज़ बैठें। प्लीज़ शांत रहिए। मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि श्री अनुराग ठाकुर उस टैंट के बाहर खड़े थे...(व्यवधान) मैंने जो अनुभव किया है, इसलिए इस प्रकार के शब्दों को कार्यवाही से एक्सपंज किया जाता है। ...(व्यवधान) इतनी ऊंची टोन में बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप माननीय सदन में हैं, इसलिए श्री सतपाल सिंह रायजादा जी, इतनी ऊंची टोन में बात करने की ज़रूरत नहीं है। माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी, आप अपनी बात शुरू करें और वाइंड अप करें। ...(व्यवधान) आप सिर्फ़ 5 मिनट में वाइंड अप करें।

श्री जगत सिंह नेगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि क्या आप मेरे बोलने पर सैंसर लगाएंगे? क्या इमरजेंसी डिक्लेयर्ड है, क्या विधान सभा में आप मेरी हर बात पर सैंसर लगाएंगे? आप मेरी अभिव्यक्ति को नहीं छीन सकते हैं, यह मुझे मेरे संविधान से मिली है और उस संविधान को बनाने में कांग्रेस का हाथ रहा है।...(व्यवधान)

14.03.2020/1435/TCV/YK-2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका बहुत-सारा समय इन बातों में ही चला जाता है। आप चेयर को अड्रैस करिए। सभी सम्माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि जब माननीय सदस्य चर्चा में हिस्सा लेते हैं तो बीच में इंट्रप्ट न किया जाये। ऐसे शब्दों का उच्चारण न किया जाये जिनसे माहौल ख़राब हों। इसलिए संयमित भाषा में अपनी बात रखें। माननीय सदस्य, आप बोलिए।

श्री जगत सिंह नेगी : अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन के नियम बने हैं अगर कोई असंसदीय शब्द कहेंगे तो आपको पॉवर है, आप उनको कार्यवाही से एक्सपंज करवा सकते हैं। लेकिन जब कोई असंसदीय शब्द है ही नहीं तो आप मुझे बोलने से कैसे रोक सकते हैं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि जो बजट का आबंटन किया जाता है, उसको ठीक प्रकार से किया जाये और उसको किसी एक क्षेत्र के लिए न डाला जाये। कल माननीय मंत्री जी बोल रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। इस बजट को स्पोर्ट करने के लिए मंत्री जी को भी उतरना पड़ा क्योंकि यह बजट कमज़ोर है। बाकी सदस्यों का वज़न नहीं पड़ा तो मंत्री जी आ गये। मैंने सोचा था मंत्री जी कुछ बड़ी बातें कहेंगे लेकिन ये एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में ही फंस गये। इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की कि किसी भी मंत्री को अपने क्षेत्र का ही विकास नहीं करना चाहिए लेकिन इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है कि मुख्य मंत्री जी ने अपने इलाके के लिए सी0आर0एफ0 के तहत 270

करोड़ रुपये का बजट रखा है। जो टूरिज्म का पैसा आया, वह भी मुख्य मंत्री जी के इलाके के लिए

श्री आर0के0एस0 द्वारा .... जारी ।

14.03.2020/1440/RKS/AG-1

श्री जगत सिंह नेगी...जारी

जो टूरिज्म और सिंचाई के लिए पैसा आया था वह ज्यादातर पैसा माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में लग रहा है। सी.आर.एफ. में पूरे प्रदेश के लिए 475 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं लेकिन उसका दो तीहाई हिस्सा माननीय मुख्य मंत्री जी ले गए हैं। टूरिज्म विभाग के लिए जो 50 करोड़ स्वीकृत हुए थे उसमें से 20 करोड़ रुपये माननीय मुख्य मंत्री जी अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए ले गए। इरिगेशन में जो 6-7 सौ करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे उसमें से 300 करोड़ रुपये आप ले गए। हम लोग पैसे लेने कहां जाएं? दिल्ली में तो मोदी जी के पास पैसा है नहीं। अब मैं पड़ोस में पैसा मांगने जाऊंगा तो आप मुझे देशद्रोही कहेंगे। अब आप मुझे बताइए कि हम कहां जाएं? एक ही जगह विकास करना शर्म की बात है। ...(व्यवधान) पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का बड़ा खौफ है। ...(व्यवधान) आज पूरा विश्व तकलीफ में है। इस वायरस के कारण विश्व की आर्थिकी में फर्क पड़ रहा है। इस वायरस का तो कोई-न-कोई वैक्सिन निकल जाएगी परंतु जो नफरत का वायरस है, जातिवाद का वायरस है, क्षेत्रवाद का वायरस है और हिन्दू-मुस्लमान का जो वायरस आपकी पार्टी ने हिन्दुस्तान में फैलाया है, उसे कैसे खत्म किया जाएगा? यह देश खत्म होने जा रहा है, इस देश की एकता और अंखडता के ऊपर खतरा आ गया है। ...(व्यवधान) जब तक आपकी मानसिकता बदलेगी नहीं यह देश जम्मू-कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक नहीं रह सकता। आप कांग्रेस के लोगों की बात कर रहे थे। हमने वर्ष 1980 के दशक में ब्रेन ड्रेन का नाम सुना था। उस समय के जो आई.आई.टी. और आई.आई.एम. से पास आउट स्टूडैंट होते थे उन्हें अमेरिका और यूरोप की बड़ी-बड़ी

कंपनियां ले जाती थी। आजकल यहां से भी कांग्रेस के नेताओं का भी ब्रेन ड्रेन हो रहा है। माननीय महेन्द्र सिंह जी, माननीय राम लाल मारकंडा जी और श्री अरुण कुमार जी भी कांग्रेस से बी.जे.पी. में गए हैं। बी.जे.पी. वालों के पास अपना कुछ भी नहीं है। बी.जे.पी. में केवल अंधभक्त तैयार होते हैं। उनको हांकने के लिए कांग्रेस के लोग चाहिए। जिस दिन आपके भीतर कांग्रेस की मानसिकता आ जाएगी उस दिन इस देश का कल्याण हो जाएगा। कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने

14.03.2020/1440/RKS/AG-2

बहुत अच्छी बात कही कि हमें मुख्य मंत्री राहत कोष में पैसा डालना चाहिए। आपने इसके लिए 20 करोड़ रुपये बजट प्रावधान किया और कई लोगों ने इसमें अपना योगदान भी दिया। लेकिन यह सारा पैसा आपके निर्वाचन क्षेत्र में ही खर्च हो रहा है। वर्ष 2019 में 3 करोड़ रुपये से ज्याद पैसा आपके निर्वाचनक्षेत्र में खर्च हुआ है। क्या सारे बीमार व गरीब लोग आपके निर्वाचन क्षेत्र में ही रहते हैं? मेरा आपसे निवेदन है कि यह पैसा जनसंख्या के आधार पर सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बांट दिया जाए ताकि लोगों को शिमला आने की जरूरत न पड़े।...(व्यवधान) यहां पर बहुत शेरो-शायरी हुई लेकिन माननीय मंत्री जी यह जान नहीं पाए कि हमारा पेट शेरो-शायरी से नहीं भरेगा और न ही इससे हमारे बेरोजगार युवाओं का फायदा होगा। मैं यह कहना चाहूंगा किः-

लाख हम शेर कहें, लाख हम इवारत लिखें,
बात वह है जो तेरे दिल में जगह पाती है।

माननीय मुख्य मंत्री जी आप ऐसी बात कीजिए ताकि लोग आपके दिल में जगह पाएं।

---(***)---

अध्यक्षः माननीय जल शक्ति मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

जल शक्ति मंत्रीः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी ने नाम लेकर कहा है कि कांग्रेस का प्रोडक्ट इस तरफ आया है। एक मर्तबा मैं विधान सभा में कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहा हूं और

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

---(***)---अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

14.03.2020/1445/बी.एस./ए.एस./-1

जल शक्ति मंत्री जारी...

मेरे जीवन का वह पांच साल का कार्यकाल जब तक मैं जीवित हूं तब तक जो घाव मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर मुझे मिले हैं उन्हें नहीं भूल सकता। मेरा ही विधान सभा चुनाव क्षेत्र हो कांग्रेस पार्टी का मैं विधायक हूं और कांग्रेस पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अन्दर हो और माननीय अध्यक्ष जी, जब अपने ही क्षेत्र में जनसभा हो, जनसभा में कांग्रेस का मुख्य मंत्री अपनी पार्टी के विधायक को बोलने से रोके फिर पुलिस का एक अतिरिक्त एस.पी बुलाकर, सिविल ड्रैस में वहां पुलिस के कमांडो रखे गए थे। मुझे स्टेज से उठा करके 8 फुट नीचे फैंका गया। वहां लातें मारी गई, वहां पर गाड़िएं खड़ी थी, धर्मपुर, मण्डप से पुलिस स्टेशन, सरकाघाट केवल मात्र 15 मिलोमीटर दूरी पर था। मुझे वहां नहीं ले गए परंतु जोगिन्द्रनगर ले करके गए। जोगिन्द्रनगर में रात को एक डी.एस.पी. साहब आए और कहने लगे कि आपकी जमान होगी। मैंने पूछा कि वह कौन सा कोर्ट रात को खुल गया? उन्होंने बताया कि ए.डी.एम. साहब का कोर्ट मण्डी में खुला है। मैने उस दिन भी कहा कि यहां भी ए.डी.एम., एच. ए.एस. अधिकारी है, यहां भी एस.डी.एम. बैठता है। उन्होंने कहा

कि हमारी मजबूरी है और हमें आपको ले जाना पड़ेगा। रात को एक बजे मण्डी जेल में डाला गया।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय मंत्री जी, यह आपकी फाइनल रिकार्डिंग है। क्योंकि बहुत बार इस बात को आप कह चुके हैं।

जल शक्ति मंत्री : मण्डी जेल में डालने के बाद मैंने सोचा कि आधे घण्डे के बाद मुझे लगा कि ये ए.डी.एम.के कोर्ट में ले जा रहे होंगे। जब ए.डी.एम. के कार्यालय से सुन्दर नगर की तरफ गाड़ियां चलने शुरू हुई तो मैंने चालक को पकड़ कर पूछा कि आप कहीं रापुर नहर में फैंकने तो नहीं ले जा रहे हैं? ड्रइवर और जो डी.एस.पी. था उन्होंने कहा कि सर, हमें आदेश हैं कि जब तक प्रदेश का मुख्य मंत्री धर्मपुर विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अन्दर है तब तक आपको धर्मपुर विधान सभा चुनाव क्षेत्र से बाहर रखना है और बाद में मुझे गोहर की जेल में डाला गया। मुझे 24 घण्टे में तीन जेलों में डाला गया है।

14.03.2020/1445/बी.एस./ए.एस./-2

इस करके जो जलालत कांग्रेस पार्टी के बीच में हो रही है उसी का फल है कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि आपकी पार्टी अब खत्म हो रही है। वह परिणाम देख कर आया, दिल्ली में जो आपका वोट बैंक बढ़ा है, आप वहां पर 4 प्रतिशत पर आ गए हैं। आपसे ज्यादा वोट निर्दलय ले जाते हैं। ...(व्यवधान) इसलिए बुद्धिजीवी आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर अब राजनीति शुरू हो गई है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी बोलना है हम भी फिर राजनीति शुरू कर देंगे।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया सुनिए, मैं व्यवस्था दे रहा हूं कृपया ध्यान से सुनिए। चर्चा के दौरान जब भी किसी मुख्य मंत्री जी का नाम आता है या मंत्रियों का नाम आता है तो उन्हें स्पष्टीकरण देना होता है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर हम यहां किस लिए बैठे हैं।

अध्यक्ष : जब आप कोई बात उठा रहे होते हैं तो माननीय मंत्री जी ने उसका स्पष्टीकरण तो देना ही है। इसलिए जो स्पष्टीकरण आ रहा है उसे हम ध्यान से सुन लें। जब माननीय सदस्य यहां पर कह रहे थे तो माननीय मंत्री जी का नाम लिया गया था।

श्री डी.टी.द्वारा जारी...

14/03/2020/1450/DT/AS1

अध्यक्ष क्रमागत

अब चर्चा में भाग लेंगे श्री मुलख राज जी।

श्री मुलख राजः मानीनय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020-2021 के बजट भाषण की चर्चा में भाग लेने के लिए आपने जो समय दिया मैं उसका धन्यवाद करता हूं। मैं प्रदेश सरकार और श्री जय राम ठाकुर जी को वर्ष 2020-21 के लिए 49,131 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तुत करने की हार्दिक बधाई देता हूं। निःसन्देह यह बजट समाज के सभी वर्गो तक पहुंचने का एक प्रयास है। इस बजट के अधिकतर प्रस्ताव कौशल विकास एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करके युवाओं को एक बेहतर भविष्य उपलब्ध करवाने हेतु सहायक सिद्ध होंगे। किसान की आय को बढ़ाने हेतु बजट मे विशेष प्रावधान किया गया है। सामाजिक क्षेत्र में गरीब तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए व सामाजिक सुरक्षा के दायरे में अभूतपूर्व विकास किया गया है। नये हिमाचल के निर्माण के लिए यह सरकार प्रयासत है और निवेश व रोजगार के नये द्वार इस बजट के माध्यम से खुलेंगे। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार द्वारा 189 जनमंच कार्यक्रम आयोजित करके लगभग 44000 शिकायतों का निवारण सफलतापूर्वक किया गया इसके अतिरिक्त मुख्य मन्त्री सेवा संकल्प के माध्यम से प्रत्येक नागरिक सरकार से जुड़ा है, जिसके लिए माननीय मुख्य मन्त्री महोदय बधाई के पात्र हैं। भविष्य में ज्यादा से ज्यादा जनमंच आयोजित किये जाऐं ताकि लोग सरकार से सीधे जुड़

सकें। सरकार द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत 1990 करोड़ रूपये व अनुसूचित जनजाति उपयोजना के तहत 711 करोड़ रूपये प्रस्तावति किये गये हैं जोकि बहुत ही सराहनीय कदम है। मेरा अनुरोध रहेगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र बैजनाथ, जहां पर काफी संख्या में अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, वहां भी जनजाती उपयोजना के अन्तर्गत धन उपलब्ध करवाने की कृपा करें। सरकार द्वारा 2,76000 परिवारों को गृहणी सुविधा योजना के अन्तर्गत मुफ्त में गैस कनैक्शन दिये गये, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र

14/03/2020/1450/DT/AS1

है। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिए वर्ष 2020-21 में 1024 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है जो की स्वागत योग्य है। लघु सिंचाई योजनाओं को प्रधान मन्त्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत पूरा किया जायेगा । उम्मीद है कि अब हर विधान सभा क्षेत्र में वर्षों से बन्द कुलहें फिर से जल से भरी होंगी। वर्ष 2020-21 से सभी वर्गो के भेड़-बकरी पालकों के लिए उपदान में बकरियां उपलब्ध करवाने की योजना की जो घोषणा की गई है इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र बैजनाथ में सैंकड़ो भेड़-बकरी पालक इस योजना से लाभान्वित होंगे। दूध खरीद मुल्य बढ़ाने से भी किसानों को फायदा होगा। मनरेगा के अन्तर्गत नई योजना "उन्नति" को आरम्भ करने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। इससे गरीब परिवारों को कौशल विकास बढ़ाने हेतु मदद मिलेगी।

श्री एन0जी0द्वारा जार

14-03-2020/1455/ए.एस.-एन.जी./1

श्री मुलख राज जारी.....

अध्यक्ष महोदय, 15वें वित्तायोग की सिफ़रिशों के अनुसार 429 करोड़ रुपये का प्रावधान करने हेतु बहुत-बहुत बधाई देता हूं जिसके कारण पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद् सदस्य भी क्षेत्र के विकास के लिए अपना अहम योगदान प्रदान करेंगे। मिड-डे मील वर्कर्स, वाटर केरियर, राजस्व विभाग के अंशकालीन कर्मचारियों व नम्बरदारों का मानदेय, जल गार्डों आदि का मानदेय बढ़ाने हेतु बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं जिससे प्रदेश का कमजोर वर्ग लाभान्वित होगा। सहारा योजना की राशि 2 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 3 हज़ार रुपये करने से प्रदेश के लाखों बेसहारा लाभान्वित होंगे। प्रदेश के सरकारी आयुर्वेदिक संस्थानों में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रस्ताव करने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूं। पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ने हेतु धर्मशाला में IHM Institute of Hotel Management की स्थापना के लिए आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान में बस अड्डों के निर्माण के लिए 17.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और रख-रखाव के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान करने हेतु माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। उम्मीद है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बैजनाथ में भी नए बस अड्डे का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ होगा। अध्यक्ष महोदय, पठानकोट-चक्की-मण्डी सड़क को फोरलेन करने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए व इसका जो सर्वे हुआ है उसी के अनुसार इसका निर्माण किया जाए। सड़कों से बर्फ को सुनियोजित तरीके से साफ करने के लिए आधुनिक मशीने खरीदने का प्रावधान करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र बैजनाथ में लोक निर्माण विभाग के बीड़ उप-मण्डल में शीघ्र नई मशीनें (जे.सी.बी., टिप्पर आदि) प्रदान की जाएं। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा बीड़ बिलिंग में Pre World Cup Indian National Open Paragliding प्रतियोगिता का आयोजन करने हेतु हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

14-03-2020/1455/ए.एस.-एन.जी./2

अध्यक्ष महोदय, दिहाड़ीदारों को मिलने वाली न्यूनतम दिहाड़ी को 250 रुपये से बढ़ाकर 275 रुपये प्रति दिन किया गया है। सरकारी विभागों व बोर्डों-निगमों के सभी कर्मचारियों की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के बीमा कवर को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने पर हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं इससे प्रदेश के लाखों कर्मचारी लाभान्वित होंगे। मेरे विपक्ष के सभी विधायक कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि प्रदेश में विकास की गंगा निरन्तर आगे बढ़ रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों से जो कुल्हें बंद पड़ी थी और पेयजल की गम्भीर समस्या रहती थी, आज लगभग सभी कुल्हों के काम चले हुए हैं और करोड़ों की सौगात मेरे क्षेत्र में पहुंची है जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय जल शक्ति मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र बैजनाथ में पर्यटन की अपार सम्भानाएं हैं जिसमें एक बीड़ बिलिंग और तत्वाणी प्रमुख है और तत्वाणी के विकास के लिए 40 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। इसके अलावा बीड़ बिलिंग के विकास के लिए भी करोड़ों रुपये की धनाराशि प्राप्त हुई है। उतराला होली मार्ग के निर्माण के लिए फोरैस्ट केस बना दिया गया है। मुझे लगता है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बैजनाथ के विकास की गति तेजी से आगे बढ़ रही है।

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी....

14/03/2020/1500/MS/DC/1

श्री मुलख राज जारी-----

दूसरे, विपक्ष वाले घोटालों की भी बात कर रहे हैं। मैं विपक्ष को यह चेताना चाहता हूं कि ये घोटाले किसकी सरकार के समय हुए? जब यू0पी0ए0 सरकार थी तो एक मंत्री बाहर आता था और दूसरा अंदर जाता था, यह किसकी सरकार में हुआ? जब से मोदी जी इस देश के प्रधान मंत्री बने हैं किसी भी सांसद या मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगा है। यह घोटालों की लिस्ट आपके सामने है(लिस्ट दिखाते हुए)। आई0एम0एफ0 घूस कांड, यूरिया घोटाला, पशु पालन घोटाला, बोफोर्स घोटाला और ट्रांसपोर्ट घोटाला इत्यादि। यदि इस घोटाले की लिस्ट को पढ़ूंगा तो काफी समय लगेगा क्योंकि अध्यक्ष महोदय बार-बार कह

रहे हैं कि समय का अभाव है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो इस बार बजट पेश किया है, इसका मैं भरपूर समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

14/03/2020/1500/MS//2

अध्यक्षः आपने निर्धारित समय में अपनी बात पूरी की है। समय का अभाव नहीं है लेकिन सभी को बोलने के लिए समय निर्धारित किया गया है। मेरा सभी सदस्यों से यही आग्रह है कि समय का ध्यान रखें। अब इस चर्चा में श्री विक्रमादित्य सिंह जी हिस्सा लेंगे।

श्री विक्रमादित्य सिंहः अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने जो वर्ष वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया है, उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

अभी कुछ ही दिन पहले सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हुई थी। हमने उस समय भी यह बात की थी कि सरकार द्वारा जो तथाकथित काम ज़मीनी स्तर पर किए गए हैं, उनके बारे में डिस्पेरिटी हमें देखने को मिली है। आज एक ओर जो सरकार का बजट डॉक्यूमैंट है और दूसरी ओर भाजपा का जो दृष्टिकोण, दृष्टिपत्र है, there is a huge contradiction between these two, whether it is in sphere of government employees, whether you talk about the increase of agriculture hectarage or increase of horticulture hectarage in the State, सिंचाई का जो बढ़ावा है, चाहे उसके बारे में देखें। अभी बहुत से वक्ताओं ने इस बारे में विस्तार से बात की है। इसलिए मैं हर बात की डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश is number one rural state and number two agriculture oriented state. अगर हम प्रदेश के कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो बजट की एलोकेशन हुई है, उसको तथा बाकी राज्यों की बजट एलोकेशन को कम्पेरिजन में देखें तो towards agriculture & in its allied activities, the State has allocated 6.0 percent of its total expenditure and this is lower than the average allocated by the States which stands at 7.1 percent. Similarly, in rural development, Himachal Pradesh has allocated 3.8 percent of its expenditure. This is significantly lower than the average allocation of rural development by the states. Nationally, it stands at

6.2 percent . इन दो लाइनों से मैं समझता हूं कि जो एक सोच और दृष्टिकोण सरकार का है, जो इनकी कथनी और करनी में अंतर है, वह आप लोगों के सामने है। आप कहते हैं कि हम सत्ता में आए। सत्ता में हम जरूर आए, इसमें कोई दो-राय नहीं है। मगर आप सत्ता में दृष्टिकोण के बेसिज पर आए हैं and it is incumbent upon you to fulfill the promises which have been made in your Manifesto. आज हरेक चीज का यह हाल है। हम एक ओर कह रहे हैं कि हमने ख़र्चा कम करना है। हम पी0एस0यूज0 की बात करें।

14/03/2020/1500/MS//3

Hon'ble Prime Minister and his Cabinet, on successive occasions, have spoken about disinvestment of PSUs and Corporations. आज हिमाचल प्रदेश के जो पी0एस0यूज0 हैं,
जारी एस0एस0 द्वारा----

14.03.2020/1505/SS-DC/1

श्री विक्रमादित्य सिंह क्रमागत :

23 में से 13 पी0एस0यूज 3444 करोड़ रुपये के नुकसान में चल रहे हैं। उसमें से एच0पी0 फॉरैस्ट कॉर्पोरेशन 160 करोड़ रुपये के नुकसान में चल रही है। एच0पी0एस0ई0बी0 लि0 1530 करोड़ रुपये के नुकसान पर चल रही है। एच0आर0टी0सी0 130 करोड़ रुपये के नुकसान पर चल रही है। 2260 करोड़ रुपया पिछले एक साल का नुकसान सभी पी0एस0यूज0 का है। It has to be decided by the Government that what is the priority.

निश्चित तौर से जो हमारा इस बार प्रदेश का 49131 करोड़ रुपये का बजट है और जो प्लान आउटले है that is around Rs. 7000 crores, मुझे इस बात की खुशी है कि उसमें से एजुकेशन को 8000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है जोकि सब चीज़ों को मिलाकर सर्वाधिक है। निश्चित तौर पर प्रदेश के अंदर शिक्षा प्रणाली को बढ़ाने की

आवश्यकता है। It is rightly said by the Members of Opposition earlier that you cannot discredit the steps that have been taken by the Congress Governments. अगर आप एक ओर यहां से हायर, प्राईमरी और एलीमैंटरी एजुकेशन के अवॉर्डस लेने दिल्ली जा रहे हैं then you should also recognize the achievements and the steps that have been taken by the previous Congress Governments. चाहे वह कॉलेज खोलने की बात हो, टेक्निकल एजुकेशन के पॉलिटेक्निक खोलने की बात हो, आई0टी0आई0 खोलने की बात हो, government functions in continuity. निश्चित तौर से जो पूर्व सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं it is incumbent on the present Government to recognize and build on those facts and institutions for the times to come. हो सकता है कि अगर कहीं पर एक-आध ऐसा संस्थान खुल गया हो जिसकी आवश्यकता नहीं थी, अगर उसको बंद भी करना पड़े तो निश्चित तौर से in the larger interest of the State that can be thought of. हमको हर चीज़ में राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है कि यह आपने खोला और हमने बंद किया या हमने खोला और आपने बंद किया। The people of the State are looking at us with great expectations. निश्चित तौर से यह चीज़ हमको समझने की आवश्यकता है कि इन कार्यों पर हमको राजनीतिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

14.03.2020/1505/SS-DC/2

अध्यक्ष महोदय, मैं टूरिज्म के बारे में बात करना चाहूंगा। As we know the contribution of tourism sector in Himachal Pradesh is 7 percent of the GDP of the State. और प्रदेश में आज तकरीबन 3700 होटल्ज़ हैं। इस प्रदेश के अंदर 2000 से 2500 के करीब होम स्टे हैं। इसमें I would also like to complement previous BJP Government जिन्होंने प्रदेश के अंदर रूरल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया है। उसको हमें आने वाले समय में आगे ले जाने की आवश्यकता है। अभी स्वदेश दर्शन की बात हो रही है, हिमालयन सर्किट की बात हो रही है जिसके लिए 70 करोड़ रुपये और प्रसाद योजना के लिए 45 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसका हम धन्यवाद और स्वागत भी करते हैं। साथ ही धार्मिक सर्किट, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये की एलोकेशन की गई है, एक राउंड अबाउट लेकर हम वापिस उसी चीज़ पर आ जाते हैं लेकिन हम regional

disparity में विश्वास नहीं करते। I would be the most happiest person if anything happens in the remotest area of Kangra district or in the remotest area of Pangi. हम हिमाचल प्रदेश को एकमत से देखने में विश्वास करते हैं। But the figures speaks the volumes about how the allocation of tourism Department funds whether it is Asian Development Bank or the BRICKS जो इरिगेशन के लिए पैसा आया है, चाहे होर्टिकल्चर के लिए आया है why it is so that the everything is being accumulating only in one region. We must understand as the Head of the State, a person is obligated to look after every region and every district of the State. Especially he is incumbent to look after the remotest areas of the State. मुख्य रूप से टूरिज्म सैक्टर के लिए जो मैंने अभी बात की है यह हमें इस बजट में देखने को मिल नहीं रही है।

जारी श्रीमती के0एस0

14.03.2020/1510/केएस/एचके/1

श्री विक्रमादित्य सिंह जारी---

एयरपोर्ट के बारे में बहुत ज्यादा बात हो गई, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश जी ने स्थिति साफ़ की है and it is something that has been categorically stated by the Airport Authority of India and Government of India कि जहां तक एलोकेशन की बात है, उसमें ज़मीन एक्वायर का पूरा का पूरा पैसा, उसका खर्च जो है that will be borne by the State Government. उसके बारे में अभी तक सरकार द्वारा स्थिति क्लीयर नहीं हो पाई है कि कहां से वह पैसा आएगा? पहले कह रहे थे कि 15वें वित्तायोग से आएगा लेकिन अभी तक स्थिति क्लीयर नहीं हो पाई है। हम सभी को सपने देखने का अधिकार है मगर उन्हें निर्धारित समय पर पूरा करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिस पर अभी तक हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अगर हम tourist inflow की बात करें, वर्ष 2017 में, which was the last year of our Government in the State, 1.91 करोड़ भारतीय पर्यटक प्रदेश के अंदर आए थे जिसमें से साढ़े चार लाख विदेशी पर्यटक थे और वर्ष 2019 में यह संख्या गिरकर 1.68 करोड़ हो गई तथा विदेशी पर्यटक 3 लाख 80 हजार तक सीमित रह गया है। निश्चित तौर पर हमें इस चीज़ को देखने की आवश्यकता है। मुझे याद है, मैंने पिछले बजट में भी यह बात की थी कि the tourism infrastructure in the State should be facilitator. आज हम पी.एस.यूज़ की बात कर रहे हैं कि 3 हजार करोड़ के debt के अंदर हमारे पी.एस.यूज़ हैं। We must differentiate between what the Government should be doing and what should be left to the private entrepreneur in the State. अगर हर चीज़ में सरकारी निवेश होना शुरू हो जाएगा या सरकारी इंटरफेरेंस हर चीज़ में होनी शुरू हो जाएगी तो उसका सरकार को पूरी तरह से नुकसान होना शुरू हो जाता है और जो ये आंकड़े हैं, वे प्रदेश के अंदर इस चीज़ को दिखा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं होर्टिकल्चर की बात करना चाहूंगा। यहां पर बड़े जोर-शोर से सब ट्रॉपिकल की, जो शिवा प्रोजैक्ट है, उसके बारे में बात हो रही थी। निश्चित तौर पर

14.03.2020/1510/केएस/एचके/2

हम उस बात को तब देखेंगे जब उसका पैसा आएगा। अभी तो केवल उसके अनुमानित आंकड़े ही आए हैं कि इसके लिए 1800 करोड़ रुपये अगले वित्तीय वर्ष में आएंगे। It is too early for us to even criticize or congratulate the Government as far as the SHIVA project is concerned. जो होर्टिकल्चर प्रोजैक्ट है! Let me remind this august House that it was conceived by the previous Congress Government under the leadership of Shri Virbhadra Singhji and the then Horticulture Minister, Smt. Vidya Stokesji. 1400 करोड़ रुपये का यह प्रोजैक्ट है, इस पर जितना कार्य प्रदेश के अंदर होना चाहिए था, नहीं हुआ है। मुझे इस बात की खुशी है कि वर्ष

1950-51 में एप्पल प्रोडक्शन जो 792 हैक्टेयर हुआ करती थी, वर्ष 2018-19 में यह 2.32 लाख हैक्टेयर तक पहुंच चुकी है। Apple economy is one of the finest horticulture economies in the country. हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को जो बढ़ावा मिल रहा है, उसमें एप्पल का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। But let me also remind this august House कि जितना सरकार का समर्थन एप्पल इकोनॉमी को प्रदेश में बढ़ाने की ज़रूरत होनी चाहिए थी, हमें देखने को नहीं मिली है। कल श्री नरेन्द्र बरागटा जी कह रहे थे कि सी.ए. स्टोर्ज़ की 2000 टन से 5000 मीट्रिक टन केपेसिटी बढ़ाई गई है, निश्चित तौर पर हम उसका स्वागत करते हैं but seeing the total production of apple in the State which is estimated at 3.3 crore boxes जो पिछले वित्तीय वर्ष में था, उसके अनुमान में हमारे पास प्रदेश के अंदर स्टोरेज केपेसिटी है या नहीं है? आज मार्किट में अरली वैरायटी जो मिडल हिल्ज़ की, हमारे लोअर हिमालयन रेंज की है, शुरूआती तौर पर जो 1800 से 2200 रुपये प्रति बॉक्स जिसका आपको पैसा मिलना शुरू हुआ,

अंग्रेजी श्रीमती अ0व0 की बारी में--

14.03.2020/1515/av-hk/1

श्री विक्रमादित्य सिंह------ क्रमागत

Because of non-availability of storage उसके आधे रेट तक people were forced to sell their produce because of non-availability of CA stores and non-availability of storage. तो इस बारे में देखने की आवश्यकता है कि एच0पी0एम0सी0 के अलावा हमें निजी क्षेत्र में भी सी0ए0 स्टोर लगाने के लिए सब्सिडी मिलनी चाहिए ताकि हमारे ज्यादा-से-ज्यादा उत्पादक तथा कोऑप्रेटिव सोसाइटी से मिलकर हिमाचल प्रदेश में सी0ए0 स्टोर लगवा सके। हम अभी तक एच0पी0एम0सी0 की बात कर रहे थे, तो आज भी हमारे बागवानों का एच0पी0एम0सी0 के पास लगभग 2500 करोड़ रुपये बकाया है जो वह पे नहीं कर पाई है और यह राशि वर्ष 2013 से चली आ रही है। हमें इस बारे में अपना

दृष्टिकोण लगाने की आवश्यकता है। अगर मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश की ओवरऑल परफॉर्मेंस चाहे वह शिक्षा के बारे में है या स्वास्थ्य के बारे में है; it is comparatively better than all other States. इसके अतिरिक्त, अभी प्रदेश सरकार द्वारा नई स्कीम शुरू की गई है वह चाहे आपकी कृषि उत्पाद संरक्षण योजना है या दूसरी योजनाएं हैं; इनके अंतर्गत भी सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों और बागवानों को फायदा देने की कोशिश की जा रही और उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं।

अंत में, मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया वर्तमान बजट ज़मीन स्तर की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य के बिल्कुल विपरीत है। इसमें जो अच्छा कार्य किया है उसका हम स्वागत करते हैं। मगर जो कमियां हैं उन पर भविष्य में और मज़बूती के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

14.03.2020/1515/av-hk/2

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री जिया लाल चर्चा में हिस्सा लेंगे।

श्री जिया लाल (भरमौर) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको आपके जन्म दिन की बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री जिया लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में आपकी अनुमति से माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों के पक्ष में बोलना चाहता हूं। मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इस बजट में प्रदेश के हर वर्ग व हर क्षेत्र का ध्यान रखा है। यह बजट हिमाचल प्रदेश की विकास यात्रा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र का अधिकतम भाग हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हिमाचल प्रदेश का संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र अति दुर्गम एवं पिछड़ा है

जिसके मद्देनज़र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य योजना की 9 प्रतिशत राशि जनजातीय उप योजना के लिए चिन्हित की गई है तथा इसका प्रावधान भी अलग से मांग संख्या 31 के अंतर्गत किया जाता है जिसके कारण प्रदेश के जनजातीय लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में काफी सुधार हो रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मांग संख्या 31 के अंतर्गत कुल 1758 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 700 करोड़ रुपये राज्य योजना, 297.22 करोड़ रुपये केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों तथा 750 करोड़ रुपये गैर योजना में है। जनजातीय उप योजना के अंतर्गत आर्थिक सेवाओं के लिए 516.90 करोड़ रुपये, सामाजिक सेवाओं के लिए 444.14 करोड़ रुपये तथा सामान्य सेवाओं के लिए 47.18 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

टी सी द्वारा जारी

14.03.2020/1520/TCV/YK-1

श्री जिया लाल ... जारी

मैं इस बढ़ौतरी के लिए मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रदेश हित में विभिन्न निर्णय लिए गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने प्रदेश में जितनी भी योजनाएं शुरू की गई हैं, उनकी विस्तारपूर्वक चर्चा की हैं। इनमें देश को पूर्ण राज्य का दर्ज़ा प्राप्त करने के 50वें वर्ष पर 2020-21 को हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाया जाना, प्रदेशभर में आयोजित किए जाने वाले जनमंच कार्यक्रम, विधायक प्रथामिकता योजनाओं के लिए प्रति विधान सभा चुनाव क्षेत्र धनराशि की सीमा 120 करोड़ रुपये करना, विधायक क्षेत्र विकास निधि को 1.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.75 करोड़ रुपये करना तथा विवेक अनुदान राशि 8,00,000 से बढ़ाकर 10,00,000 करना, दूर-दराज़ क्षेत्रों के लिए 10 मोबाइल हैल्थ सैंटर शुरू करना, पांगी घाटी के 1000 घरों में 250 के ऑफ ग्रेड और ऊर्जा सयंत्र स्थापित करना है। मुख्य मंत्री महोदय, आज इस देश को आजाद हुए कम-से-कम 72-73 वर्ष हो गये हैं। किसी भी सरकार ने इससे पहले पांगी

घाटी के बारे में नहीं सोचा। वहां पर सड़कों की बहुत दुर्दशा है। आज भी पांगी घाटी के लोग अंधेरे में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर इसके बारे में किसी मुख्य मंत्री ने सोचा है तो आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने सोचा है, उसके लिए मैं इनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारी जो पांगी घाटी है, वह एक बहुत ही सुन्दर स्थान है और सभी चाहते हैं कि हम पांगी घाटी जाएं लेकिन जब वे सड़कों की दुर्दशा देखते हैं तो वहां जाने से मना कर देते हैं। हमारा जो साच-पास दर्रा है, वहां बड़ी संख्या में यात्री जाना चाहते हैं लेकिन वह रास्ता कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए वे लोग वहां नहीं जाते हैं। वहां पर केन्द्र और प्रदेश सरकार के सहयोग से एक रोपवे बनने जा रहा है जिसके लिए 01 करोड़ रुपया आ गया है। मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी जो सड़क जे0 एंड के0 से होकर जाती है, उसको संसारी नाला बाया किलाड़-उदयपुर-तांदी से बनाया जाये। इसके साथ-साथ 50,000 अतिरिक्त पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देना व विधवा-दिवांगजन की पेंशन राशि को 850 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह करना, जिससे 1,76,000 लोगों को लाभ मिलेगा। दिहाड़ीदार की दिहाड़ी 250 रुपये से बढ़ाकर 275 रुपये

14.03.2020/1520/TCV/YK-2

करना, हिमाचल प्रदेश के विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी परिषद द्वारा करसोग के कुल्थ, पांगी की ठांगी, चम्बा की धातुशिल्प, चम्बा चुक और भरमौर के राजमाह उत्पादों के लिए कम-से-कम 5 जियोग्राफिकल इंडेक्शन पंजीकरण करवाने के बारे में निर्णय लिया गया। ये क्षेत्र मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी जब मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, भरमौर में गये थे तो जो-जो मांगें हमने इनके समक्ष रखी, इन्होंने उनको तुरंत पूरा कर दिया था। इन्होंने एक जल शक्ति का डिवीजन और उसके साथ जल शक्ति का एक सब-डिवीजन मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में दिया है जिसकी बड़े दिनों से डिमांड थी। 100 बैडिड हॉस्पिटल की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की थी जिसका काम शुरू हो गया है। अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश

में 3 एकलव्य स्कूल हैं, किन्नौर में पहले से इस प्रकार का स्कूल था लेकिन भरमौर और पांगी में एकलव्य स्कूल नहीं थे।

श्री आर0के0एस0 द्वारा .. जारी ।

14.03.2020/1525/RKS/AG-1

श्री जिया लाल... जारी

भरमौर और पांगी के बच्चों को के.वी.एस. या नवोदय स्कूल में एडमिशन लेनी पड़ती थी। इन स्कूलों में बहुत कम बच्चों को एडमिशन मिलती थी। मैं माननीय मुख्य मंत्री, माननीय कृषि मंत्री और केंद्र सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज वहां पर क्लासिज भी शुरू हो गई है और इसके लिए बजट का प्रावधान भी कर दिया गया है। जब 8 नवम्बर, 2018 को नोटबंदी हुई तो वह किसी को पूछ कर नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लोगों को यह नहीं बताया गया था कि नोटबंदी हो रही है और आप अपना प्रबंध कर लो। नोटबंदी को हुए काफी समय हो गया है लेकिन इनके पेट में बार-बार मरोड़ क्यों पड़ रहे हैं। जब आपके पास काला धन नहीं था तो आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। जब वर्ष 1971 में नोटबंदी हुई थी तब प्रदेश और केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस समय तो आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। जब नोटबंदी हुई तो मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पुराने नोटों की पेमेंट की गई। इस बात को यहां बैठे वन विभाग के अधिकारी भी सुन रहे होंगे। वह पैसा कहां से आया? जो पैसा जमा था उस पैसे को निकालकर विभाग को दे दिया गया और इस तरह पैसे को एडजस्ट कर लिया गया। इसलिए मैं समझता हूं कि आप लोगों की तकलीफ सच्ची है। जब वर्ष 1971 में नोटबंदी हुई थी तो उस समय जस्टिस बंदासु जी थे लेकिन उस समय आपने कोई विरोध नहीं किया। आजादी से पहले डॉ.भीम राव अम्बेदकर जी ने यह शब्द कहे थे कि हर 10 वर्ष के बाद करंसी को बदला जाना चाहिए। धारा-370 और 35ए आदरणीय मोदी जी की सरकार द्वारा हटाई गई है। इन कामों को करने के लिए हिम्मत चाहिए और यह हिम्मत आप लोगों

में नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह हिम्मत दिखाई है और इसलिए आपके पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं। आप बार-बार कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 9 हजार रुपये कर्ज ले लिया। जो आपने अपने समय में कर्ज लिया था हम उसका ब्याज चुकता करने के लिए कर्ज ले रहे हैं। जब माननीय महेन्द्र सिंह जी आपबीती सुना रहे थे तो आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी। अध्यक्ष जी, मुझे पता है कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे बहुत

14.03.2020/1525/RKS/AG-2

से लोग हैं जो वहां घुटन महसूस कर रहे हैं और वे इधर आना चाहते हैं। माननीय पवन नैय्यर जी अगर आपका पटका पहने रखते तो कभी विधायक नहीं बनते। आपकी पार्टी ने इन्हें दो बार टिकट दिया और दोनों ही बार इनको हरवा भी दिया। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें विधायक भी बना दिया। हमारी बड़ी बहन आशा जी 6 बार चुनाव जीत चुकी है और मुझे लगता है कि आप भी वहां घुटन महसूस कर रही है।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

14.03.2020/1530/बी.एस./ए.जी./-1

श्री जिया लाल जारी...

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी पांच बार चुनाव जीते और मुख्य मंत्री बन गए हैं। ये आपको लाने वाले हैं। मैं मैडम आशा जी से आग्रह करता हूं कि हम बहुत उदार दिल वाले हैं आप भी इस तरफ आ जाओ कुछ-न-कुछ भला होने वाला है। यहां वैसे भी कोई बैठने वाला नहीं है और माननीय विक्रमादित्य जी, मुझे पता है आप भी यहां आने वाले हैं । आदरणीय मुकेश जी भाग्यशाली हैं इनके सब मंत्री हार गए और ये बाल-बाल बच गए हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्री जीः बाल-बाल नही बचे हैं ढंग से बचे हैं।

श्री जिया लाल : नहीं-नहीं बाल बाल ही बचे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में पेश किया। मैं इसका भरपूर समर्थन करता हूं। धन्यवाद

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपने अपने निर्धारित समय में अपनी पूरी बात रखी है इसके लिए आपका धन्यवाद। अब इस चर्चा में अंतिम वक्ता माननीय सदस्य श्री रविन्द्र कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

14.03.2020/1530/बी.एस./ए.जी./-2

श्री रविन्द्र कुमार (जयसिंहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपनी बात आपके जन्म दिवस की आपको बधाई देते हुए रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका धन्यवाद।

श्री रविन्द्र कुमार : इस प्रदेश के यशसस्वी लोक प्रिय मुख्य मंत्री द्वारा 06 मार्च, 2020 को प्रस्तुत किए गए 2020-21 के बजट अनुमान के पक्ष में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत आभार। माननीय मुख्य मंत्री जी का यह तीसरा बजट है और इन तीनों ही बजट्स का यदि हम मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे कि तीनों ही बजट गरीब, किसान, मजदूर, बागवान और उपेक्षित वर्ग को समर्पित हैं। मैंने माननीय मुख्य मंत्री महोदय को एक बार जिला मण्डी में जनसभा में सुना था, एक हर शख्सियत के व्यक्तित्व की एक विकास यात्रा होती है और यात्रा के दौरान जो-जो दुश्वारियों हम सहन करते हैं। उनकी झलक उस शख्सियत की कार्य शैली में मिलती हैं। सुकून और सुखद बात यह है कि यह जो तीनों बजट आए हैं सब-के-सब गरीबी उन्मूलन पर आधारित हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पहला ही निर्णय मुख्य मंत्री बनते ही इनका हुआ वह था वृद्धावस्था की आयु सीमा जो 80 वर्ष की थी उसे कम करना। यह सम्मान कितना बड़ा होता है। यदि अभावों में ज़िदगी गुजर-बसर हुइ है तो कमोबेश बचपन हमारा भी अभावों में बीता है। अध्यक्ष जी, मैं जब नौकरी किया करता था और जिस दिन तनख्वाह मिलती थी, एक सौ रुपया जब अपनी बुजुर्ग दादी के हाथ में रखते थे तो उस सौ रुपए को वह माथे से लगाती थी और एक पुराने रूमाल से बांध कर अपने सिराहने के नीचे रख देती थी। वह जो सुकून और सम्मान की अनुभूमि उनके चेहने पर दिखती थी आज जब उस अनुभूमि को याद करता हूं, तो आज भी गला रूंध आता है और आंखे नम होती है। हजारों लोगों के आशीर्वाद

जो माननीय मुख्यमंत्री इस योजना के अन्तर्गत कमाया है वह ताउम्र इनके साथ रहेगा और कभी विफल नहीं जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, कई कल्याणकारी योजनाएं सरकार ले करके आई शायद हर योजना का मैं यहां पर जिक्र करने लगूं तो इतना न समय है और नहीं आप मुझे वक्त दे पाएंगे।

डी.टी. द्वारा जारी

14.03.2020/1535/DT/AG-1

रविन्द्र कुमारः जारी...

लेकिन एक बात तो गर्व के साथ कह सकते हैं कि जब हम बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं कि मेरा राज्य, मेरे हिमाचल में सौ प्रतिशत इलैक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है। हम दावे के साथ लोगों के साथ यह बात कर सकते हैं कि मेरा प्रदेश अब सौ प्रतिशत एल.पी.जी. युक्त है। हर घर में हर गृहिणी के पास एल.पी.जी.का कनैक्शन हैं। इसके दाता कोई और नहीं बल्कि माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी हैं। प्रतिपक्ष की ओर से दो- तीन बातों का बहुत विरोध होता है। एक मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हैल्प लाईन और दूसरा जनमंच का। या तो ये दोनों ही स्कीमें बिल्कुल खराब है या ये बहुत ही अच्छी हैं। खराब इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि जो 189जनमंच हुए हैं उनमें 47, 848 शिकायतें मिली और लगभग 44,000 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। इस तरह सेवा संकल्प हैल्प लाईन में फरवरी, 2020 तक जिसमें 37,990 शिकायतें मिली और लगभग सभी शिकायतों का सन्तोषजनक निवारण हुआ। इन योजनाओं का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह विपक्ष की विचारधारा वाले लोगों के दिलों में भी घर कर रही है। आपको अपना आधार खिसकता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा मेरा संदेह है। इन्वैस्टर मीट पर बहुत कुछ कहा गया है। कल हलांकि इसका उत्तर माननीय उद्योग मन्त्री बिक्रम सिंह ठाकुर जी ने दिया है। एक बच्चा पैदा होने में कम से कम 9 महीने का समय लगता है। 7-8 नवम्बर को यह इन्वेस्टर मीट होती है और चार महीने के बाद ग्राउंड ब्रेकिंग जिसे मैं अपने शब्दो में व्यक्त करूं तो गोद भराई की एक रस्म हुई और उधर से इतना तोहमते हैं और यह चाहते हैं यह बच्चा 9 महीने से पहले -पहले ही बाहर आ जाए। कल माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक

मुहावरा इस्तेमाल किया और मुझे लगा कि शायद ये इस पर वाकआउट हो जाए। माहभारत में एक करेक्टर पूतना दाई है। मेरे शब्दों पर मत जाना इसके भाव पर जाना। अगर मेरे शब्द चुभन करेंगे तो इसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांगता हूं। उस पूतना दाई की तरह एक विकास के नाम से जो बच्चा पैदा होगा, लगभग 97,700 करोड़ रुपये के एम.ओ.यू साइन हुए और 13,656 सामझौते हुए । यह बच्चा स्वस्थ पैदा न हो, जैसे शिक्षा मंत्री जी ने बात रखी कि किसी की दाढ़ी में तिनका, मैं किसी का नाम नहीं लूगा। यह हम पाठयक्रम में पढ़ते रहे हैं, और इम्तिहान में कई बार ये चीजें पूछी जाती रही है। उधर से भी एक तुकबंदी हुई। वह पार्लियामैंट्री है या नहीं वह आपको तय करना है।

14.03.2020/1535/DT/AG-2

आप करे तो रास लिला, हम करे तो डैस-डैस ढीला। कोई भी माननीय सदस्य यहां से इसकी व्याख्या कर सकता है। इन शब्दों का क्या अभिप्राय था? लकोक्ती और मुहावरों में आप वाकआउट करते हैं

श्री एन.जी.द्वारा जारी...

14-03-2020/1540/ए.एस.-एन.जी./1

श्री रविन्द्र कुमार जारी.....

और गाने पर...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने पंचायत के चौकीदार से लेकर समस्त विधायकों-मंत्रियों तक को इस बजट में कुछ-न-कुछ दिया है। उदाहरण के लिए नाबार्ड में हमारी किट्टी 105 करोड़ रुपये की थी जिसे बढ़ा कर 120 करोड़ रुपये कर दिया गया है, विधायक क्षेत्रिय विकास निधि को 1 करोड़ 50 लाख रुपये से बढ़ा कर 1 करोड़ 75 लाख रुपये कर दिया गया, एच्छिक निधि को 8 लाख रुपये से बढ़ा कर 10 लाख रुपये कर दिया गया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इसके लिए मन की गहराई से धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप इस पद पर आसीन होने से पूर्व प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आयुष्मान भारत योजना का वृहद रूप आपने हिमाचल

प्रदेश में हिम केयर योजना बना कर दिया। मैं इसके लिए एक उदाहरण देना चाहता हूं, जैसा सभी जानते हैं कि हमने भी गरीबी में बचपन काटा है, मेरा एक दोस्त अपने साथी को लेकर एक दिन मेरे घर आता है, मेरे दोस्त को सुबह-सुबह पीने की आदत है, दोनों लड़खड़ा कर मेरे घर आते हैं। आते ही उसने मुझे कहा कि भाई साहब यह मेरे मामा ससुर हैं और इनको कुछ पैसे दे दो। मुझे लगा कि खुद भी पिया है और मामा ससुर ने भी पी हुई होगी और मुझ से पैसे ले कर दोनों शराब में फूंक देंगे। मैंने उनसे कहा कि यदि यह बीमार हैं तो मैं इनका इलाज करवा दूंगा। उन दिनों में चुनाव हो चुके थे और रिज़ल्ट का इन्तेज़ार था। अध्यक्ष महोदय, मैंने उसे कहा कि मैं वीरवार को अपने बेटे के इलाज के लिए टांडा मैडिकल कॉलेज जा रहा हूं और आप मेरे साथ चलना, मैं आपका इलाज करवाऊंगा। वह वीरवार को आ गया और मेरे साथ टांडा मैडिकल कॉलेज गया। जब उसे डॉक्टर को दिखाया तो उसकी शूगर 450 फास्टिंग में थी और डॉक्टर हैरान थे कि यह जिंदा कैसे है। उसका इलाज चला और 2-3 माह के अंदर वह ठीक हो गया। वह टेलरिंग का काम करता था और

14-03-2020/1540/ए.एस.-एन.जी./2

जिस दिन वह मेरे घर आया था उस दिन उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी या कम हो चुकी थी इस कारण वह पैर पटक-पटक कर चल रहा था इसलिए उस समय मुझे ऐसा लगा कि यह भी नशे में होगा। मैंने अपने ईष्ट को याद किया और उनसे माफी मांगी। उसका इलाज 4-5 माह तक चलता रहा और जब वह काम पर दोबारा जाने लग गया तो उसके पैर में ठोकर लगी, पांव में जख्म हो गया, जख्म गैंगरीन में बदल गया और अंततः उसके पैर को काटना पड़ा। हम सब अपनी-अपनी दुनियादारी में व्यस्त हैं और मैंने एक माह तक उसको न फोन किया और न ही उसने मुझ से कभी पैसे मांगे, एक दिन मुझे सुबह-सुबह फोन आता है कि आज आप लम्बा गांव आ रहे हैं या नहीं। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ, उसने कहा कि श्री केवल कृष्ण जिसका आप इलाज कराते थे उसकी मृत्यु टांडा मैडिकल कॉलेज के फर्श के ऊपर ही हो गई है क्योंकि उसकी एडमिशन नहीं हो पाई थी। अध्यक्ष

महोदय, यह राजनीति का मंदिर है और इस पर खड़े होकर मैं एक बात कहूंगा कि उस समय मुझे ऐसा लगा कि मेरे खाते में जो पैसे हैं वह सब निकाल कर किसी चौराहे में जाकर जला देने चाहिए क्योंकि यह पैसा किसी गरीब के काम नहीं आ सका। जब लोकसभा के चुनाव थे उस समय आपका ही इलाका खरमैंकड़ (खैरा के पास) वहां पर एक बुजुर्ग श्री जगत राम जी हैं, मैं उनके पड़ोस में था तो मुझे किसी ने बताया कि श्री जगत राम जी के 2-3 ऑपरेशनज़ हो चुके हैं क्योंकि वह बहुत गम्भीर बीमार थे और आप उनका आशीर्वाद लेकर आओ। मैं उनके वहां गया और एक छोटा सा घर जिसके बाहर कुर्सी पर श्री जगत राम जी बैठे हुए हैं। उनके पास जाकर मैंने उनके पांव छूए और उनसे पूछा कि आप बहुत बीमार थे और अब कैसे हैं? उन्होंने कहा कि अब मैं ठीक हो गया हूं। मैंने उनसे कहा कि यदि आपके पास आपकी बीमारी के कोई बिल हैं तो वे दे देना, मैं मुख्य मंत्री जी से आपको मुख्य मंत्री राहत कोष से पैसा वापिस करवा दूंगा

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी...

14/03/2020/1545/MS/AS1

श्री रविन्द्र कुमार जारी--------

उस बुजुर्ग ने कहा कि नहीं मेरे पास बिल नहीं है। उसने कहा कि मेरे पास कार्ड था और उसने अध्यक्ष जी आपका नाम लिया। वह शायद मुख्य मंत्री जी को नहीं जानता था। उसने कहा कि जो परमार जी ने कार्ड बनाया है, वहां से पैसे कटे हैं। मेरा अपना कोई पैसा उपचार पर नहीं लगा है। यह फ़र्क है।

अध्यक्ष जी, विपक्ष की तरफ से प्रश्न आया कि 125 करोड़ रुपये का एक घोटाला हो गया है। आपको पता है कि 53 करोड़ रुपये आयुष्मान भारत में और 63 करोड़ रुपये हिम केयर में सरकार का ख़र्चा है। इस तरह से 1 करोड़ 16 लाख रुपये इन दोनों योजनाओं पर प्रदेश सरकार ने ख़र्चा है। गरीब के पास अगर सरकार ने मुफ्त में दवाई पहुंचाने का काम किया है तो 125 करोड़ रुपये क्या, मैं तो कहता हूं कि अगर 1025 करोड़ रुपये भी मुख्य मंत्री जी आपको देना पड़े तो आप देने में बिल्कुल भी गुरेज़ न करना। यह मेरा आपसे आग्रह है। इसी तरह से मुख्य मंत्री जी ने सहारा योजना के अंतर्गत 2000/-रुपये से

3000/-रुपये की राशि प्रतिमाह बेसहारा लोगों को देने की कोशिश की है। उनकी दुआयें और उनका आशीर्वाद भी मुख्य मंत्री जी को प्राप्त होगा, यह मेरी मान्यता है।

माननीय अध्यक्ष जी, सामने से एक बन्धु ने थोड़ी सी इकॉनोमी के बारे में भी बात की। मैं बाई प्रोफेशन एक्स-बैंकर हूं। मैं बहुत लम्बी-चौड़ी बात नहीं करूंगा। इस वर्ल्ड में कोई भी ग्रोइंग इकॉनोमी बता दो जहां के बजट में फिसकल रेवेन्यु डेफिसिट न हो? एक भी इकॉनोमी बता दो। ...(व्यवधान)दिल्ली की बात छोड़ दो। दिल्ली में कितना डेफिसिट है, उसकी बात नहीं करेंगे। ...(व्यवधान)दिल्ली का जो बजट है, उसको आप ध्यान से पढ़ें। ...(व्यवधान) मैं कहने वाला था कि एक लिमिट है। कृपा करके मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपको क्या लगता है कि इस तरफ जो लोग बैठे हुए हैं और उस तरफ जो बैठे हैं, ...(व्यवधान)

Shri Harshwardhan Chauhan: Sir, deficit has a limit.

Shri Ravinder Kumar: Sir, what is that limit? जब आप लोग 47000/-करोड़ रुपये छोड़कर गए, तब आपको लिमिट याद नहीं थी? आज यहां पर एक माननीय सदस्य जिनका लगता है कि शिवा के नाम से तीसरा नेत्र खुल गया है, यहां पर तरह-तरह की योजनाएं बताने की कोशिश कर रहे थे। जब वे यहां बैठा करते थे तब वे योजनाएं

14/03/2020/1545/MS//2

क्यों नहीं बताते थे? आज ही उनको क्यों सारी योजनाएं याद आ रही थीं? यह सोचने का विषय है।

अध्यक्ष जी,यहां कुछ-कुछ बातें कोरोना वायरस के ऊपर भी हो रही हैं, जिसके बारे में मुख्य मंत्री जी ने वक्तव्य भी दिया है।...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। इन्होंने कोरोना वायरस की बात की है। उधर से एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि अढ़ाई साल इनके हो गए हैं, अब अढ़ाई साल के बाद हम वहां होंगे। अध्यक्ष जी, सी फोर कोरोना और सी फोर एक और वायरस है जो लगभग 72 वर्षों से इस देश को लगा हुआ है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आशीष बुटेल जी कृपया सुन लें।

श्री रविन्द्र कुमारः ...(व्यवधान) और डैश-डैश.. वे समझ गए हैं, जहां मैंने बात करनी थी। वह बात उन तक पहुंच गई है। कहते हैं कि जब 30 डिग्री सेल्सियस टैम्प्रेचर हो जाएगा तो यह वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा। वर्ष 2024 में यह जो सी फोर दूसरा वायरस है, यह विलुप्ति की कगार पर है और विलुप्त हो जाएगा। यह तय है। अध्यक्ष जी, वैसे मेरा बजट पर बोलने के लिए पिछले कल नम्बर था लेकिन आपने आज मुझे समय दे दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय हिमाचल।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपने निर्धारित समय में अपनी बात रखी है। आज इस माननीय सदन में काफी शेरो-शायरी हुई है। मैं बैठे-बैठे सोच रहा था कि यहां कहा गया कि माननीय मुख्य मंत्री जी आप ऐसी बात कीजिए ताकि लोग आपके दिल में जगह पायें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी ने कहा है,

जारी एस0एस0 द्वारा-----

14.03.2020/1550/SS-DC/1

माननीय अध्यक्ष क्रमागत :

---(***)--- जरा मेरी बात सुनिये। यह जगत सिंह नेगी जी ने कहा। अब ये तवायफों के पैसों की खनक में तवायफ कौन है? माननीय सदस्य यह आपने बोला है। बोलने से पहले थोड़ा-सा सोच लेना चाहिए। आप बड़े सीनियर मेम्बर हैं। ...(व्यवधान) बात सुनिये। और उसमें उनके पैसों की खनक देखकर रुकने वाले कौन हैं? ये आप हैं या कौन हैं? इसलिए माननीय जगत सिंह नेगी जी आपने अपनी चर्चा में शेर के माध्यम से किसी को तवायफ कहा है तो किसी को तवायफ के यहां पैसों की खनक देखकर वहां रुकने की बात कही है। यह अशोभनीय तथा अश्लील व्यंग्य है। यह व्यंग्य इस माननीय सदन में किया गया है ...(व्यवधान) क्या आप (श्री मुकेश अग्निहोत्री जी से) इसको ठीक मानते हैं? आप कहिये। क्या आप ये कोठे और सब शब्द ठीक मान रहे हैं? यह व्यंग्य अश्लील है और सदन के दोनों पक्षों की ओर इंगित हो रहा है। आप इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं लेकिन इसका दोनों तरफ इशारा जा रहा है। ...(व्यवधान) आपकी तरफ ज्यादा जा रहा है। अतः यदि माननीय सदन की अनुमति हो तो इस शेर को कार्यवाही से निकाल दिया जाए? ठीक है। मुकेश जी आपका धन्यवाद।

अब बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2020-21 पर हुई सामान्य चर्चा का उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी देंगे। परन्तु इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस चर्चा में सत्तापक्ष के 30 सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रतिपक्ष के 18 सदस्यों, सी0पी0आई0(एम0) के एक सदस्य और अन्य एक सदस्य ने चर्चा में हिस्सा लिया। इस प्रकार कुल 50 सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया है। चारों दिनों में कुल 15 घंटे 30 मिनट तक यह चर्चा चली। अब चर्चा को समाप्ति की ओर बढ़ाते हुए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस माननीय सदन में चर्चा का उत्तर दें।

14.03.2020/1550/SS-DC/2

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको जन्म दिन की हार्दिक बधाई।

अध्यक्ष : धन्यवाद। आपको यहां पर पूरा बैठना है और माननीय मुख्य मंत्री के उत्तर को सुनना है। यह मेरी आपसे करबद्ध विनती है। आपको बाहर नहीं जाना है। आप यह जन्मदिन का उपहार मत देना कि सदन से बाहर चले जाएं। अब माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 मार्च, 2020 को इस माननीय सदन में मुझे तीसरी बार बजट प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस माननीय सदन की उच्च परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए इस बजट पर हुई चर्चा में इस सदन के 50 सदस्यों ने भाग लिया। जैसा आपने बताया, इसमें 30 भारतीय जनता पार्टी के, 18 कांग्रेस पार्टी के, एक सी0पी0आई0(एम0) के और एक स्वतंत्र सदस्य ने भाग लिया। इस प्रकार कुल मिलाकर 50 सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। अध्यक्ष महोदय, वैसे भी अब की बार हमारा संयोग है कि गोल्डन जुबली ईयर चल रहा है।

जारी श्रीमती के0एस0

14.03.2020/1555/केएस/डीसी/1

मुख्य मंत्री जारी---

इस माननीय सदन के 50 सदस्यों ने इस बजट पर अपनी बात कहते हुए योगदान दिया, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आज यह भी संयोग है कि अध्यक्ष महोदय, आज आपका जन्मदिन है, मुझे मालूम नहीं कि आपकी कितनी उम्र हुई होगी, पूछना भी नहीं चाहिए लेकिन आपके चेहरे की लाली से लगता है कि आपकी उम्र ज्यादा नहीं हुई, आप अभी बालक ही हैं । मैं आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आप लम्बी आयु के साथ इस प्रदेश की, समाज की सेवा करें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने इस चर्चा की शुरूआत की। कई तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल हुआ। बजट डायरैक्शनलैस है। फाइनैंशियल मिसमैनेजमेंट है, लोन ले लिए, ज्यादा ले लिए। एक्सटर्नली एडिड प्रोजैकट्स का ज़िक्र किया, हमारी विभिन्न योजनाओं पर जो प्रदेश की जनता ने स्वीकार की, दिल में जिन योजनाओं को बसाया, उन पर टिप्पणी की गई कि ये योजनाएं प्रदेश के हित में नहीं हैं। बहुत सारी बातों का ज़िक्र हुआ। मैं इस सिलसिले में सिर्फ़ यही कहना चाहता हूं किः-

साहिल के सकूं से किसे इन्कार है लेकिन तुफ़ान से लड़ने का मज़ा ही कुछ और है।

अध्यक्ष महोदय, इससे पहले महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी चर्चा हुई, उसमें भी बहुत से सदस्यों ने भाग लिया और उस समय भी बहुत सारी बातें सुनने को मिली। सुझाव के रूप में भी बातें आई और उसमें कमियां ढूंढने की भी कोशिश हुई। जब हम बजट प्रस्तुत करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी कोशिश होती है कि प्रदेश के हर वर्ग के लिए हम काम करें। जब हर वर्ग की बात करते हैं तो हमारी जो आर्थिक परिस्थिति है, उसमें जो किया जा सकता है, वह करने की कोशिश की जाती है, वह चाहे हमने बजट प्रस्तुत किया, चाहे हमसे पहले किस

और ने बजट प्रस्तुत किया हो। बार-बार इस बात को कहना कि कुछ नहीं हुआ और प्रदेश ऋण के बोझ तले दब गया, यह ठीक नहीं है। यह बात सच है कि ऋण हमारे सामने एक

परिस्थिति है, जिसको हमें खुले मन से स्वीकार करना पड़ेगा। मैं उन सारी बातों पर आगे आऊंगा लेकिन जिन योजनाओं की शुरूआत हमने हिमाचल प्रदेश में जनहित में की है, हमने उनको एक मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की है। इससे पहले कि मैं बजट के बारे में आगे कहूं मैं यह कह सकता हूं कि जिन योजनाओं के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा करने की कोशिश की है, उन योजनाओं को लोगों के बीच में पहुंचाने में हमने जो अपनी ओर से प्रयास किया है, प्रदेश की जनता ने उसको सहज रूप से स्वीकार किया है। मैं कह सकता हूं कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में 2.76 लाख गैस कनैक्शन्ज़ गांव में, घर में, घर की रसोई में पहुंचाना,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

14.03.2020/1600/av-yk/1

मुख्य मंत्री------ क्रमागत

आज़ादी के बाद 70 वर्षों में से जो 50 साल सत्ता में रहे वे इस सोच को अपने दिमाग तक पहुंचा ही नहीं सके। उनके लिए यह विषय सोचने का था ही नहीं, हम स्वादिष्ट भोजन की कल्पना तो करते हैं मगर हमारी माताओं-बहनों के फेफड़ों, आंखों व शरीर पर धुएं के कारण कितना नुकसान होता है; यह उनके सोचने का विषय ही नहीं बन पाया। यह निर्णय बिल्कुल हटकर लिया गया है तथा इस निर्णय की शुरुआत हमने की है। इसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित किए गया और उस लक्ष्य को पूरा करके 2.76 लाख घरों में गैस का चूल्हा पहुंचाया। मैं यहां पर इस बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप हर बात में यह बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला, यह प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है कि कुछ हुआ है। हम किसानों के बारे में बात करते हैं और हमने मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना शुरू की है। हम इस बात से सहमत है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जहां 90-95 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं और गांव में रहने वाला व्यक्ति किसान होता है। वह जंगली जानवरों के कारण इतना परेशान है कि ज़मीन छोड़कर काम-धंधे के लिए

शहर की तरफ निकल पड़ा है क्योंकि जंगली जानवरों के कारण वह ज़मीन जोतने की परिस्थिति में नहीं है। हमने छोटी-सी शुरुआत की है, मगर हमने शुरुआत की है। ...(व्यवधान) आज मुझे इस बात की खुशी है कि एक साल के कार्यकाल में हमने लगभग डेढ़ हजार किसानों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने की कोशिश की है। हम यहां पर बेरोज़गारी का ज़िक्र करते हैं। मैं अभी आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता। यहां पर अलग-अलग तरह के आंकड़े दिए जाते हैं; कोई 10 बोलता है, कोई 12 बोलता है और कई तो 15 भी कहने लग गये हैं। हम इस बात से सहमत है, मगर यह विषय केवल हमारे प्रदेश से संबंधित नहीं है, यह विषय देश और दुनिया से संबंधित भी है और ऐसी परिस्थिति में हमें स्व-रोज़गार की ओर बढ़ना पड़ेगा। इसलिए हमने प्रदेश में मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना की शुरुआत की है। हमने इस दिशा में एक छोटा-सा प्रयत्न किया है और प्रदेश के नौज़वान इसको स्वीकार करने लगे हैं। हमने इसके लिए लगभग 28 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है और बड़ी

14.03.2020/1600/av-yk/2

संख्या में प्रदेश के बेरोज़गार नौज़वान अपना काम-धंधे शुरू करने में कामयाब हुए हैं। यहां पर कौशल विकास भत्ता के बारे में भी बातें कही गई इसलिए मैं उसका भी थोड़ा-सा ज़िक्र करना चाहता हूं। मैं यहां पर उन-उन बातों का ज़िक्र कर रहा हूं जिनको हमने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में करने की कोशिश की और जो किया है। उसके अंतर्गत 65,522 अभ्यर्थियों तथा बेरोज़गारी भत्ता योजना के अंतर्गत 45,323 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया। यहां पर कुछ सदस्य बोल रहे थे कि बेरोज़गारी भत्ता खत्म कर दिया। ...(व्यवधान) आप तो हर जगह शामिल है। अध्यक्ष महोदय, आपके पास स्वास्थ्य विभाग था। हमने हिमाचल प्रदेश में हिम केयर योजना की शुरुआत की और आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि इस योजना का प्रदेश की जनता ने काफी फायदा उठाया है। यह एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में एक प्रयास हुआ है, एक गरीब आदमी जिसको पहले ऐसा लगता था कि बीमार हो गये तो चीख-पुकार के बीच ज़िंदगी खत्म हो जायेगी, उपचार करवाने की

गुंजाइश नहीं होगी क्योंकि उपचार के लिए पास पैसा नहीं है। हमने हिम केयर योजना के माध्यम से 68,222 लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान की है तथा उसके अंतर्गत 63 करोड़ रुपये खर्च किए गए। अब यह आंकड़ा लगभग 65 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। अगर हम कंपेरिजन की बात करें तो आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने या उपचार हेतु जो पैसा खर्च किया जाता था वह लगभग 18 से 20 करोड़ रुपये होता था।

टी सी द्वारा जारी

14.03.2020/1605/TCV/HK-1

मुख्य मंत्री... जारी

जो किसी के इलाज़ के लिए खर्च किया जाता था। हमने 37 करोड़ रुपये तो 2 वर्षों में 'मुख्य मंत्री राहत कोष' के माध्यम से ही खर्च किए हैं। अगर हम 'आयुष्मान भारत', 'हिम केयर' और 'मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता कोष' तीनों को मिलाएं तो जहां आप एक साल में 18 करोड़ रुपये खर्च करते थे, हमने 125 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। ये राशि हमने ऐसे लाचार, बेबस आदमी पर खर्च की है जो अपने इलाज़ के लिए पैसा मुहैया नहीं कर पाता था और अपनी ज़मीन व घर बेच देता था। हमने उस आदमी की मदद करने की कोशिश की है। 'सहारा योजना' का आंकड़ा अलग से है, मैं उसका ज़िक्र नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसमें बहुत-सारा व़क्त लग जाएगा। आप कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है इसलिए मैं इन कामों का ज़िक्र कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, 5,74000 लोगों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है और जिसमें वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत 70 वर्ष तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने के बाद 1,50,000 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। ये नई एडिशन हुई हैं। आप कहते हैं कि जनमंच का ज़िक्र मत करो। हमने काम किया है जिससे आप परेशान होते हैं। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिससे सामने वालों की परेशानी बनी रहनी चाहिए। हम तो इस कार्यक्रम को जनहित में चला रहे हैं और लोगों को इसका लाभ हो रहा है। हमने पूरे

हिमाचल प्रदेश में 189 जनमंच के आयोजन किए हैं, जब से इस कार्यक्रम को शुरू किया है। इसमें 47,848 शिकायतें व मांगे प्राप्त हुई जिनमें से 43,548 का निपटारा हो गया है लेकिन यहां कहा जा रहा था कि ये प्रायोजित कार्यक्रम है। प्री-जनमंच का मतलब क्या होता है? इसमें जिसने अपनी शिकायत दर्ज़ करनी होती है उसको कहा जाता है कि आप अपनी शिकायत दर्ज़ करिए। वह अपनी शिकायत ऑन-लाइन, लिखित रूप में, पंचायत में पंचायत सेक्रेटरी या बी0डी0ओ0 के ऑफिस में दर्ज़ कर सकता है। उसके बाद उसकी जांच की जाती है कि प्री-जनमंच में जो शिकायत दर्ज़ की

14.03.2020/1605/TCV/HK-2

गई थी, उसका समाधान क्यों नहीं हुआ है? यदि समस्या का समाधान जनमंच होने से पहले ही करना है तो पहले भी हो जाता है लेकिन अगर उसकी समस्या का समाधान जनमंच से पहले नहीं होता है तो वह जनमंच कार्यक्रम में माइक पर आकर अपनी समस्या का ज़िक्र करता है और मंत्री और अधिकारी वहां पर उसका समाधान ढूंढ़ते हैं। प्री-जनमंच के लिए जो क्लस्टर बनता है, वह 8-10 पंचायतों का बनाता है और जहां जनमंच होता है, उसी एरिया के अधिकारी और कर्मचारी उसमें होते हैं। जनमंच का कार्यक्रम रविवार को होता है। ...(व्यवधान) आप अधिकारियों की चिंता कर रहे हैं, उन्होंने स्वेच्छा से कहा है कि हम जनता की सेवा के लिए हैं और एक रविवार क्या हम 2 रविवार छोड़ने के लिए भी तैयार हैं।

श्री आर0के0एस0 द्वारा .. जारी

14.03.2020/1610/RKS/hk-1

मुख्य मंत्री... जारी

हमने हैल्पलाइन की शुरूआत की है। इस हैल्पलाइन को शुरू किए हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है लेकिन इस हैल्पलाइन के माध्यम से अब तक 37,990 शिकायतों का निवारण किया जा चुका है। जो बजट वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तुत किया गया है उसमें 25 नये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा किः-

तुम यहां धरती पर लकीरें खींचते हो,
हम वहां पर अपने लिए नये आसमान ढूंढते हैं,
तुम यहां धरती पर पिंजरे बनाते हैं,
हम अपने पंखों में नई उड़ान ढूंढते हैं।

पूर्ण राजत्व का स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है और इस स्वर्ण जयंती वर्ष में हमने कई नए इनिशिएटिव्स लिए हैं। संतोष का विषय यह है कि हिमाचल प्रदेश में हर आदमी के पास अपना घर है। उसका घर टूटा हो सकता है परंतु हिमाचल प्रदेश में कोई भी व्यक्ति फुटपाथ पर नहीं सोता। हमारी कमिटमैंट है 'घर हो तो अच्छा हो'। जब किसी का घर अच्छी कंडिशन में न हो तो उसे रहने लायक कैसे बनाया जाए, उस दृष्टि से एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। हमने इसके लिए स्वर्ण जयंती योजना की शुरूआत की है ओर इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों को 5,100 घर दिए गए हैं। 3 वर्षों में सभी पात्र गरीब अनुसूचित जाति परिवारों के लिए मकान उपलब्ध करवाये जाएंगे। मुख्य मंत्री आवास योजना में अगले वर्ष 3100 नये घर बनाए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं उनके लिए 20,000 रुपये अतिरिक्त उपदान दिया जाएगा। जो 5000 हजार घर बनाए गए थे उनमें इजाफा करके अबकी बार 10,000 घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये चीजें धरातल में आना शुरू हो गई हैं और आप कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्सपैंशन हुआ है परंतु हमें क्वालिटी एजुकेशन पर फोक्स करने की आवश्यकता है और इसके लिए हमने नये इनिशिएटिव्स लिए हैं। प्रारंभिक, उच्च माध्यमिक स्कलों व कॉलेजों के लिए स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय, स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय और Excellence in Colleges योजना की शुरूआत की है जिसके लिए 54 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान भी किया गया है। योजना का लक्ष्य स्कूल और

कॉलेजों के लिए बेहतर क्लास रूम, पानी की व्यवस्था स्मार्ट क्लास रूम, खेल और जिम मुहैया करवाना है। हमने अध्यापकों की उचित संख्या को भी सुनिश्चित किया है। 'स्वर्ण जयंती सुपर 100', के अंतर्गत 10 वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक लेने वाले 100 विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए 1 लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की है। कनैक्टिविटी के संदर्भ में मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

14.03.2020/1615/बी.एस./वाई.के./-1

मुख्य मंत्री जारी...

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद कनैक्टिविटी की बात आती है, अध्यक्ष महोदय, इस पर मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि 69 नैशनल हाइवेज जो इंप्रीसिपल सैंक्शन है और आज मैं इस बात का खुलासा ही कर देता हूं, बहुत जल्दी उन में से 25 नेशनल हाइवे पर इंप्रींसिपल से प्रींसिपल स्वीकृति आने के बाद लैंड एक्वीजिशन का काम शुरू हो जाएगा, 55 की डी.पी.आर्ज. हमने बना दी है और 20-25 की फस्ट फेज में शुरूआत हिमाचल प्रदेश में होने वाली है। विपक्ष वाले पहले बोलते थे कि कुछ नहीं हो रहा है, जब हो रहा है तो कहते हैं कि शुरू कब होगा। चिंता मत करिए, सब होगा। अध्यक्ष महोदय, हमने उसमें आगे बढ़ कर बात कही, हमने कहा कि हम 5 हेलिपोर्ट बनाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि यह तो हवाई सेवाओं के लिए है। हमने कहा कि हमारे हिमाचल प्रदेश में लगभग 38-39 पंचायतें सड़क के बिना बची हैं उन्हें जल्दी-से-जल्दी कनैक्टिविटी देंगे, यह हमारा टारगेट है । अध्यक्ष महोदय, हमने आगे एयरपोर्ट की बात कही है। आज दुनिया कहां-से-कहां पहुंच गई आप उसके बावजूद यही कहना चाहते हैं कि नहीं आगे नहीं। हमने कहा कि नया कुछ सोचना और करना है तो स्वाभाविक रूप से हमें बाई एयर कनैक्टिविटी कैसे इम्प्रूव हो सकती है, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। हमने उसके लिए 1013 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उसके बावजूद

भी फिर बोलते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, आपके बजट में कुछ नहीं है। मैं सुक्खु जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने कहा कि यह काम अच्छा है और यह होना चाहिए।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : माननीय मुख्य मंत्री महोदय, कृपया यह बता दें कि यह कहां पर बनाया जाएगा?

मुख्य मंत्री : वह हम आपको बता देंगे, इसकी सूची दे देंगे। इस बार अध्यक्ष महोदय, हमने और बढ़ करके कार्य किए हैं। हमने कहा कि जो पोष्टिक आहार है इस पर हमें और अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। हमने स्वर्ण जयंती पोषाहार योजना हिमाचल प्रदेश में

शुरू की और उसी तरह से बागवानों के लिए, किसानों के लिए और पशुपालकों के लिए, जो फार्मर प्रोड्यूशर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से 20 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया है। हींग, केसर जैसी चीजों के लिए और भी अन्य जैसे हेलनैट के लिए हमने कहा, प्राकृतिक खेती के सिलसिले में कहा, ये नए कुछ इंसिएटिव हमने लिए हैं और इन्हें और मजबूत करने की बात की है। आने वाले समय में अध्यक्ष महोदय, हम हिमाचल प्रदेश में काम करके आगे बढ़ने की मंशा रखते हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक मंदी के बारे में भी जरा कुछ बोलिए।

मुख्य मंत्री : मैं एक बात कहता हूं कि हिमाचल दुनिया से अलग नहीं है। दुनिया की इकोनोमी की जो परिस्थिति इस वक्त बनी है, जो हालात दुनिया के बने हैं। पहले एक सी. था और उसके बाद एक और सी. जुड़ गया जिसके कारण इकोनोमी तहस-नहस हुई है और यह सच्ची बात है। कोरोना के कारण बहुत नुकसान हुआ है। उसमें एक सी. वायरस तो खत्म हो गया अब दूसरा जैसे-जैसे डॉक्टरों का मानना है कि तापमान बढ़ेगा वैसे उसमें सुधार होगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें ही आगे आना चाह रहा हूं। आप चाह रहे हैं कि इन

योजनाओं का ज्यादा जिक्र न किया जाए तो मैं थोड़ा छोड़ देता हूं। मैं देख रहा हूं कि विपक्ष की ओर से कुछ बातें हो रही है। भगवान शांति बनाए रखे।

श्री डी.टी.द्वारा जारी...

14.03.2020/1620/डी.टी./ए.जी./-1

मुख्य मंत्री जारी...

हमारे कुछ इंसिएटिव्ज हैं जिनका बजट में जिक्र हुआ है। मैं इन्हें अपने पास रख लेता हूं और आने वाले समय में इनका जिक्र करने की कोशिश करूंगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार की जो उपलब्धियां हैं अभी उसका जिक्र हो रहा है इसके बाद अगले विषय का जिक्र होगा।

मुख्य मंत्री : मैं अभी भूमिका बांध रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि इस बजट में कुछ नहीं है। इसलिए मैंने बहुत सारी चीजों को भी बोलने के लिए छोड़ दिया है। अध्यक्ष महोदय, जो यहां पर ऋणों की बात की गई और विपक्ष के नेता जी ने बहुत बोला आदरणीय ठाकुर राम लाल जी ने बोला और आदरणीय सिंघा जी ने बहुत बोला। मैं कहीं और था परंतु भाषण सुना खूब जोर से बोल रहे थे। आप भी सच्चे हैं, मुश्किल यह है कि आप अकेले है इसलिए जोर से बोलना पड़ता है। इन्होंने अपनी बात कही है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019-20 के दौरान अनुपूरक अनुदान मांगों के माध्यम से लगभग 7 हजार करोड़ रुपए की अनुदान मांगों का अनुमोदन किया गया। उसके अतिरिक्त जो ऋण है उससे जुटाए गए। इसमें झुपाने वाली बात नहीं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि हमारी सरकार को 47,906 करोड़ रुपए का कर्जा मिला है। यानी कि आपका दिया हुआ बहुत कुछ है। भगवान की कृपा इस प्रदेश पर इस देश पर आपकी इतनी मेहरबानी हुई कि 48 हजार करोड़ रुपए का ऋण हमें विरासत में मिला है। मैं इस माननीय सदन को इस बात से अवगत करवाना चाहूंगा कि 2018-19 में भारत सरकार से अनुमति होने के बावजूद ही बाजर से 1,617 करोड़ रुपए के ऋण हमने नहीं उठाए है। यह हमारी वित्तीय कर्जों को लगाम लगाने और

वित्तीय प्रबंधन के प्रसास का प्रतीक है। यह बात आपको समझनी चाहिए। आप एक घंटा बोले हैं और हमने आपको ध्यान से सुना है। जो आपकी शंका रहेगी उसका भी हम बाद में जवाब देंगे। केन्द्र की वर्तमान सरकार भी ऋण भार को कम करने बारे सजग रही और भारत सरकार की जी.एस.डी.जी. रेशो को मार्च, 2014 में 52 प्रतिशत थी। मार्च, 2019 में घट कर 48

14.03.2020/1620/डी.टी./ए.जी./-2

प्रतिशत रह गई। इस प्रकार से केन्द्र सरकार और हमारी सरकार दोनों ही सूझ-बूझ से कर्जा उठा रही हैं तथा कुशल वित्तीय पबंधन की ओर हमने कमद उठाए हैं। अध्यक्ष महोदय, हम यह भी कहना चाहते हैं कि निर्धारित सीमा के भीतर ही ले रहे हैं और वर्तमान सरकार द्वारा कार्यभार संभालने के बाद प्रथम दो वित्तीय वर्षों में 31 मार्च, 2020 तक 6,442 करोड़ रुपए के ऋण वापिस किए जाने वांछित हैं। कृपया सुनिए, इसलिए अध्यक्ष महोदय, अगर मैं इसके कंपेरिजन में जाऊं तो पूर्व भाजपा सरकार ने वर्ष 2007-12 पांच साल के कार्यकाल में, जब आदरणीय धूमल जी मुख्य मुख्य मंत्री थे उस वक्त 7,465 करोड़ रुपए ऋण पांच वर्ष में लिया गया था और पूर्व सरकार जिसमें आप शामिल थे, इसमें सी. शामिल था। उसमें 2013-2018 तक 19,195 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया। हमें कहा जा रहा है कि आपने ऋण लिए। आपने तो तीन गुणा ज्यादा ऋण पांच वर्ष में लिए हैं।

श्री एन.जी.द्वारा जारी...

14-03-2020/1625/ए.जी.-एन.जी./1

मुख्य मंत्री जारी.....

...(व्यवधान) 3 गुणा, थ्री टाइम ज्यादा।...(व्यवधान) मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने इस बात का भी जिक्र किया कि इस बार सप्लीमेंटरी बहुत ज्यादा हैं। देखा जाए तो वास्तव में वर्तमान वित्त वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा कुल 3,293 करोड़ की सप्लीमेंटरी है क्योंकि 3,443 करोड़ रुपये तो

ways & means एडवांस थे और जिससे कर्जा नहीं बढ़ता। अध्यक्ष महोदय, 6,793 करोड़ रुपये के आंकड़ों की जो बात की गई है वह मिस-लीडिंग है।...(व्यवधान) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का हमें स्वागत करना चाहिए। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में 519 करोड़ रुपये, National calamity contingency fund 454 करोड़ रुपये, स्वां नदी प्रोजैक्ट 178 करोड़ रुपये इसके अलावा सी.एस.एस. में भी केन्द्रीय सहायता के रुप में जो राशि 2019-20 में मिली है वह भी सप्लीमेंटरी मे ली गई है। अध्यक्ष महोदय, इसके मुकाबले में आपकी सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2014-15 में 7,753 करोड़ रुपये की सप्लीमेंटरी डिमांड रही है। हमारे आंकड़ो का आपके आंकड़ों से हमें मिलान करना पड़ रहा क्योंकि आप गलत सूचना बोल रहे थे। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020-21 के लिए हमने 49 हजार 131 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है और इस पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने प्रश्न उठाए थे कि वित्तीय संसाधन कहां से जुटाएंगे और पैसा कहां से आएगा। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि आपको यह चिंतन करना छोड़ देना चाहिए, प्रदेश की जनता ने वर्ष 2022 तक हमें यह जिम्मेवारी दी है तो यह चिंतन हमने करना है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-2018 में केन्द्र सरकार से 26,258 करोड़ रुपये अनुदान प्राप्त हुआ था और वित्तीय वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 में 30,524 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ था।...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह नेगीः यह तो हमारा हक है।...(व्यवधान)

मुख्य मंत्रीः तो आप लोग अपना हक क्यों नहीं ले पाए।...(व्यवधान)

अध्यक्षः नेगी जी नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए हैं तो आप भी बैठ जाइए।...(व्यवधान)

मुख्य मंत्रीः यहां वित्त आयोग का भी जिक्र आ रहा था।

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी....

14/03/2020/1630/MS//1

मुख्य मंत्रीः वर्ष 2019-20 के दौरान 11 मार्च, 2020 तक, ...(व्यवधान) मुझे पढ़कर बोलने की आदत नहीं है, मैं सच्ची बात बता रहा हूं। लेकिन ये आंकड़े हैं इसलिए पढ़कर बोलने पड़ेंगे। आप कृपा करके सुन लीजिए। वर्ष 2019-20 के दौरान 11 मार्च, 2020 तक इन मद्दों के अंतर्गत 30524/-करोड़ रुपये भारत सरकार से प्राप्त हो चुके हैं तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मार्च माह के अंत तक और अधिक राशि प्राप्त होने की संभावना है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि हमारी सरकार ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इनको देख लीजिए। सबसे बड़ी गलत बात यही है कि ये लोग सुनते नहीं हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, कृपया बैठिए। बैठिए। माननीय सदस्यगण, मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर दे रहे हैं।

मुख्य मंत्रीः ...(व्यवधान) मैं आगे बता रहा हूं।

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, बैठिए। मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर दे रहे हैं। बैठिए, यह व्यवस्था है।

(कांग्रेस विधायक दल के सदस्यगण अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

मुख्य मंत्रीः ...(व्यवधान) मैं वही आपको बता रहा हूं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, ...(व्यवधान) जो आपको सूट किया, वह आपने बोला है। जो आपने बोला है, उसका जवाब तो सुन लीजिए, ।

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, कृपा करके बैठ जाइए।

(कांग्रेस विधायक दल ने नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन किया)

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, हमारे मित्र असली रस्म पर आ गये हैं। यह इनकी नियमित रस्म बन गई है यानी यह इनका हररोज़ का काम बन गया है। अध्यक्ष जी, अभी तो मैंने शुरूआत की थी। अभी तो हम आने वाले समय के आंकड़ों का जिक्र करने वाले थे और अभी तो यह तीसरा ही बजट है। आज से पहले जितने भी बजट इस माननीय सदन में प्रस्तुत हुए हैं, उन पर चर्चा करने के बाद मुख्य मंत्री के माध्यम से उत्तर दिए जाते रहे। हमने देखा है कि पूरे बजट की डिस्कशन और फिर उसका रिप्लाई मुख्य मंत्री की ओर से सब सुनते थे। यह ठीक है कि रिप्लाई आने के बाद कुछ क्वायरीज होती थीं, फिर उसके बाद बाहर जाने की बात होती

14/03/2020/1630/MS//2

थी। लेकिन इनको 15 मिनट बैठना यहां मुश्किल हो जाता है क्योंकि जब असली बातें निकलने लगीं तो इनको यहां बैठना मुश्किल लग रहा था। इसलिए अध्यक्ष जी, आज जो इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति है इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो इनके सिवाय कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। यही लोग जिम्मेवार हैं। आप कल्पना कीजिए वर्ष 2007 से लेकर 2012 तक की सरकार रहती है तो 7000 के लगभग जो लोन लिया जाता है, ये इस आंकड़े को 20,000 पर पहुंचा देते हैं यानी तीन गुणा कर देते हैं। इस तरह से प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या होनी है, इसकी कल्पना कर सकते हैं।

अध्यक्ष जी, मैं जिक्र कर रहा था कि 15वें वित्त आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए वर्ष 2020-21 में 19309/-करोड़ रुपये अनुदान के रूप में प्रदान किए गए जबकि 14वें वित्त आयोग की अवधि के लिए यह राशि प्रति वर्ष 14407/-करोड़ रुपये औसत थी तथा 13वें वित्त आयोग की समयावधि में यह राशि 4338/-करोड़ रुपये औसत थी,

जारी एस0एस0 द्वारा----

14.03.2020/1635/SS-AS/1

मुख्य मंत्री क्रमागत :

और हमको 2020-21 में जाकर 19309 करोड़ रुपया अनुदान मिला है। 13वें वित्तायोग में अगर हम कहें तो प्रतिवर्ष औसत अनुदान हिमाचल प्रदेश को 4338 करोड़ रुपया मिला था। 14वें वित्तायोग में 14407 करोड़ रुपये मिला। 15वें वित्तायोग का क्योंकि अभी तक फाइनेंस कमीशन का पांच साल का कम्प्लीट अवार्ड आना बाकी है लेकिन मात्र एक वर्ष के लिए 19309 करोड़ रुपया हमको मिला है। इसके लिए मैं केन्द्र सरकार और फाइनेंस कमीशन का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 15वें वित्तायोग में 2020-21 के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लिए 429 करोड़ रुपये, शहरी निकायों के लिए 207 करोड़ रुपये तथा एस0डी0आर0एफ0 के लिए 409 करोड़ रुपये के बढ़े हुए प्रावधान करने के लिए केन्द्र सरकार और फाइनेंस कमीशन का आभार व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा यहां पर बहुत ज्यादा एक्सटर्नली एडिड प्रोजैक्ट पर बोला गया। मैं उसके सिलसिले में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैंने बीच में स्टेटमैंट दी थी और पिछले कल हमारे वन मंत्री ने भी स्टेटमैंट दी है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बात को समझना चाहिए कि जब भी हम एक्सटर्नली एडिड प्रोजैक्ट के लिए यहां पर प्रस्ताव भेजते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। उसको अनेकों औपचारिकताओं के दौर में से गुजरना पड़ता है। उसमें समय लगता है। आमतौर पर दो या ढ़ाई या तीन साल उसकी सैंक्शन के लिए लगते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमने प्रोजैक्ट भेजे थे उनमें से अधिकांश प्रोजैक्ट हमारे उस स्टेज पर पहुंचे हैं और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि पांच-छः महीने के अंदर-अंदर कुछ प्रोजैक्टों में पैसा आयेगा और हम ज़मीनी स्तर पर उसमें काम करने की परिस्थिति में होंगे। इसके लिए हमने कुछ स्टेटमैंट्स यहां पर देनी थीं, उसके सिलसिले में हमने बात कह दी।

14.03.2020/1635/SS-AS/2

अध्यक्ष महोदय, यहां ए0डी0बी0 प्रोजैक्ट के सिलसिले में जो बात कही गई है उसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। होर्टिकल्चर डवलपमैंट प्रोजैक्ट के अंदर वर्ष 2016-17, 2017-18 के दौरान केवल 23.48 करोड़ रुपये व्यय किये गए थे जबकि इस परियोजना के कार्यान्वयन को गति प्रदान करते हुए हमारी सरकार द्वारा इस व्यय को वर्तमान में 120.55 करोड़ रुपये के स्तर तक लाया गया है तथा मार्च, 2020 तक इस व्यय को 150 करोड़ रुपये तक लाया जायेगा। इसी परियोजना की संवीक्षा के लिए जनवरी तथा फरवरी, 2020 में विश्व बैंक रिव्यू मिशन की रिपोर्ट के आधार पर विश्व बैंक के भारत के कंट्री डायरेक्टर द्वारा प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की गई है तथा परियोजना के कार्य की गति पर संतोष जताया गया है। ए0डी0बी0 से पोषित पर्यटन क्षेत्र में चलाई जाने वाली परियोजना के प्रथम ट्रेंच (Tranche) के अंतर्गत सभी कार्यों को पूर्ण कर ट्रेंच को बंद कर दिया गया है। द्वितीय ट्रेंच समयावधि 30 जून, 2020 है और द्वितीय ट्रेंच के सभी कार्य समयावधि में पूर्ण होने की सम्भावना है। इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए 2018 में भारत सरकार द्वारा 233.22 मिलियन अमरीकी डॉलर की लागत से पर्यटन क्षेत्र की एक और परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में 30 सब-प्रोजैक्टों की अप्रेज़ल रिपोर्ट ए0डी0बी0 को भेज दी गई है जिसका निरीक्षण ए0डी0बी0

द्वारा किया जा रहा है। ए0डी0बी0 की स्वीकृति मिलते ही प्रदेश सरकार द्वारा फैक्ट्स फाइंडिंग मिशन भेजने के लिए आग्रह किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं सारे विश्व की इकोनॉमी के बारे में कहना चाहता था कि वैश्विक स्तर पर मंदी तथा राष्ट्रीय स्तर पर विकास 5 प्रतिशत होने के फलस्वरूप देश में आर्थिक विकास दर 5.6 प्रतिशत होने का अनुमान है।

जारी श्रीमती के0एस0

14.03.2020/1640/केएस/डीसी/1

मुख्य मंत्री जारी---

क्योंकि यह एक ग्लोबल लैवल का इशू है जिससे स्वाभाविक रूप से भारत भी प्रभावित हुआ है और हिमाचल प्रदेश भी प्रभावित हुआ है। वर्ष 2014-15 के दौरान केन्द्र सरकार ने आमूल-चूल परिवर्तन किए हैं। इस परिवर्तन में विशेषता है बुनियादी ढांचे में सुधार और समावेशी विकास। अर्थव्यवस्था के मूल स्तम्भ मज़बूत हैं और इनसे आर्थिक स्थिति सुनिश्चित हुई है। मुद्रास्फीति नियंत्रण में है। बैंको को पिछले दशकों के संचयित ऋणों से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया है और उनका पुर्नपूंजीकरण किया गया है। जी.एस.टी. सुधार हमारे देश के लिए ऐतिहासिक रहा है।

अध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी. के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में हमने इसको गीयर अप किया है, हम इसको मोनिटर कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन में भी इन्क्रीज़ हुआ है और जी.एस.टी. कलैक्शन में भी हम आगे बढ़े हैं, यह मुझे कहना है।

अध्यक्ष महोदय, यहां हवाई अड्डों की कनैक्टिविटी का ज़िक्र किया गया। उस सिलसिले में मैंने अपनी बात कह दी है। कनैक्टिविटी के बारे में जो प्रमुख रूप से यहां पर बात हो रही थी, उस सिलसिले में मुझे कहना है कि हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोड़ की कनैक्टिविटी में बेहतर काम करने की कोशिश की है और उसमें गति बढ़ी है। इस वर्ष

2019-20 में सरकार द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-2 प्रोजैक्ट लांच किया गया तथा प्रोजैक्ट तैयार करके कुल 964.25 करोड़ रुपये की 113 परियोजनाएं स्वीकृत की गई। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वर्ष 01.01.2013 में जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में आई थी, से 31.12.2017 तक पांच वर्षों में 2938.70 करोड़ रुपये की 967 परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत हुई थीं। यह मैं वर्ष 2013 से 2017 तक पांच साल का ब्यौरा दे रहा हूं। जबकि 01.01.2018 से 11.03.2020 तक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज़-1 के अंतर्गत दो वर्षों में हमने 1908 करोड़ रुपये की 646 योजनाएं स्वीकृत की हैं। यानि की पांच साल में हमारा यह आंकड़ा इनसे 3-4 गुना ज्यादा होगा। अगर हम

14.03.2020/1640/केएस/डीसी/2

नाबार्ड की बात करें तो वर्ष 2019-20 में 464.83 करोड़ रुपये की 115 परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त की गई जिसमें 102 सड़कें व 13 पुल सम्मिलित थे। इनके समय के वर्ष 2013 से 2017 तक पांच साल के कार्यकाल में 1442 करोड़ रुपये की 399 योजनाएं स्वीकृत की गई थीं और ऐवरेज प्रतिवर्ष 288 योजनाएं उसमें रही थीं। जहां इन्होंने 1442 करोड़ रुपये पांच वर्षों में स्वीकृत किए वहां हमारा दो वर्षों के कार्यकाल में 836 करोड़ रुपये मूल्य की 210 परियोजनाएं हमने स्वीकृत की हैं। मैं इस बात का इसलिए ज़िक्र कर रहा हूं कि अगर हम तुलना करें, तो इनके मुकाबले हम बहुत पैसा केंद्र से लाने में सफल हुए हैं। वर्ष 2013 से 2017 तक सैंट्रल रोड़ फंड के अंतर्गत 440.60 करोड़ रुपये की 89 परियोजनाएं स्वीकृत हुईं और हमारे दो वर्ष के इस कार्यकाल में इनके पांच वर्ष में 440 करोड़ रुपये और हमारे दो वर्ष के कार्यकाल में 747 करोड़ रुपये की स्वीकृति इसमें हिमाचल प्रदेश को मिली है। उसके बावजूद भी ये लोग कहते रहते हैं कि केन्द्र से क्या मिला? तो और क्या मिलना है, क्या मिल सकता है? केंद्र हमारी मदद कर रहा है, आदरणीय प्रधान मंत्री जी हमको विकास में सहयोग दे रहे हैं, यही मुझे लगता है कि पर्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के मेरे मित्र क्षेत्रवाद की बात कहते हैं, ये सदन से बाहर चले गए,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

14.03.2020/1645/av-yk/1

मुख्य मंत्री ------ क्रमागत

हमारे कुछ मित्र यहां पर कागज़ उठाकर कह रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2013 से वर्ष 2017 के बीच में एक हरोली विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये से अधिक बजट खर्च किया गया। बाकियों में कई जगह 10 करोड़ रुपये, कई जगह 15 करोड़ रुपये और एक विधान सभा क्षेत्र में इतनी ज्यादा राशि खर्च की गई। यहां पर अभी विक्रमादित्य जी भी नहीं है। वे कह रहे थे ...(व्यवधान) वह आंकड़ा अलग है और मैं कभी उनके सामने उन सारी चीजों का ज़िक्र करूंगा। शिमला ग्रामीण चुनाव क्षेत्र में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की एक-एक स्कीम पर 105 करोड़ रुपये की सैंक्शन होती है और बाकी चीजें अलग हैं। ऐसी परिस्थिति में वे लोग क्षेत्रवाद की बात करते हैं। ठीक है, मैं उन सारी बातों पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन हरेक विधान सभा क्षेत्र में काम हो रहे हैं। हमारे मित्रों ने यहां पर ग्लोबल इंवैस्टर मीट का ज़िक्र भी किया और कहा कि इतने करोड़ रुपये का तम्बू लगा दिया। यहां पर पिछले कल माननीय उद्योग मंत्री जी ने जवाब दिया है कि पंडोगा में इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ज़मीन को समतल करने में ही 110 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। यहां वे कह रहे थे कि उसके लिए 150 करोड़ रुपये तो मैं दिल्ली से लाया। हमने जब कागज़ देखे तो पता चला कि उस ज़मीन पर इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने के लिए मात्र 21 करोड़ रुपये की राशि मोडिफाईड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम के अंतर्गत आई है तथा बाकी की सारी राशि प्रदेश सरकार की खर्च की गई। धर्मशाला में आयोजित ग्लोबल इंवैस्टर मीट में तो प्रधान मंत्री के अलावा 36 देशों के डेलिगेट्स और पूरे देश के इंवैस्टर्ज आए थे तथा वहां

एक दिन का नहीं बल्कि तीन दिन का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के लिए हमें केंद्र से सहयोग के रूप में 12 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई और उसमें राज्य सरकार के केवल 8 से 10 करोड़ रुपये खर्च हुए। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि पूरे देश भर में अगर कहीं सबसे कम खर्चे में कोई ग्लोबल इंवैस्टर मीट हुई है तो वह हिमाचल प्रदेश में हुई है। हमने केवल ग्लोबल इंवैस्टर मीट का आयोजन ही नहीं किया बल्कि उसके संदर्भ में ज़मीन पर भी काम किया है। हमने उसमें डेढ़ महीने के

14.03.2020/1645/av-yk/2

कार्यकाल में 13,600 करोड़ रुपये की ग्राउंड ब्रेकिंग की है। हम इन सारी बातों का जवाब उनके सामने देना चाहते थे। लेकिन वे लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं अब इन सारी बातों पर ज्यादा नहीं जाना चाहता।

यहां पर बेरोज़गारी के बारे में भी कहा गया कि रोज़गार के संसाधन कैसे विकसित करेंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में पूरे हिमाचल प्रदेश के गवर्नमैंट सैक्टर, बोर्ड व कॉर्पोरेशन में कुल मिलाकर करीब 29,000 लोगों को रोज़गार दिया। हमने मात्र दो साल के कार्यकाल में लगभग 17,707 लोगों को रोज़गार दिया। हमने इस साल के बजट में 20,000 और लोगों को रोज़गार देने की घोषणा की है। जितना रोज़गार इनकी पार्टी ने 5 साल के कार्यकाल में दिया हम उसका मुकाबला 2 वर्षों में करने की परिस्थिति में आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे मित्र और भी कई बातें कह कर चले गये। अगर हम पेंशन की बात करें तो पंजाब में सोशल सिक्योरिटी पेंशन 750 रुपये मिलती है और हिमाचल प्रदेश में 1,500 रुपये बुजुर्गों के लिए तथा दिव्यांगों और विधवा पेंशन जो पहले 850 रुपये मिलती थी उसको बढ़ाकर हमने 1000 रुपये किया है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार का शासन है और हम उनसे बहुत आगे हैं। यहां पर रिसोर्स जेनरेशन की बात हो रही थी कि आपके पास संसाधन कहां से आयेंगे। अगर हम एक्साइज पॉलिसी की बात करें तो इन्होंने उस वक्त एक बीव्रेज कॉर्पोरेशन बना दी थी।

टी सी द्वारा जारी

14.03.2020/1650/TCV/HK-1

मुख्य मंत्री... जारी

उसकी पॉलिसी के कारण प्रदेश को लगभग 200 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ। हमने जो पॉलिसियां बनाई अगर हम उनकी बात करें तो वर्ष 2015-16 में जब इनकी सरकार थी तो एक्साइज 1131 करोड़ रुपये का आया। वर्ष 2016-17 में 1307 करोड़ रुपये, 2017 में 1311 करोड़ रुपये और जब 2018-19 में हमारी सरकार आई तो 1311 करोड़ रुपये से हम सीघा 2425 करोड़ रुपये में पहुंचे। वर्ष 2019-20 का जो हमारा लक्ष्य है वह 1625 करोड़ रुपये का है और मुझे पूरा भरोसा है हम इसके करीब पहुंचेंगे। हमने वर्ष 2020-21 का लक्ष्य 1840 करोड़ रुपये का रखा है, उस लक्ष्य को भी हम हासिल करेंगे। हम रिसोर्स जेनरेशन की दृष्टि से लगातार एक्साइज में अच्छी पारदर्शी योजना लाने का प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, 'विधायक क्षेत्र विकास निधि' में हमने 3 साल में 75 लाख रुपये का इजाफ़ा किया है, इस बार भी 25 लाख रुपये इंक्रीज़ किए हैं और पिछली बार भी 25 लाख रुपये इंक्रीज किए थे। माननीय विधायकों की नाबार्ड की योजनाओं के लिए सीलिंग 80 करोड़ रुपये की थी, हमने 3 सालों में उसको 120 करोड़ रुपये तक पहुंचाया है। इस तरह से हम चुने हुए विधायकों के प्रति भी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। पहले जहां ऐच्छिक निधि 6 लाख रुपये मिलती थी, उसको हमने बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया है। सबसे गरीब आदमी मज़दूर होता है। जब हम सरकार में आये तो मज़दूरों को 210 रुपये दिहाड़ी मिलती थी, उसको हमने 225 रुपये किया। दूसरी साल में उसमें 25 रुपये की बढ़ौतरी करके उसको 250 रुपये किया और इस बार 275 रुपये किया है। जो आदमी सुबह उठकर मज़दूरी करता है और मज़दूरी करने के बाद अपने परिवार का पालन-पोषण करता है, इन 3 सालों में हमने उसकी एक महीने की आय में 2000 रुपये की बढ़ौतरी की है और साल में 24000 रुपये की बढ़ौतरी की है। जब दिहाड़ी बढ़ती है तो

14.03.2020/1650/TCV/HK-2

स्वाभाविक रूप में आउटसोर्स के कर्मचारी की आय में भी बढ़ौतरी होती है। अध्यक्ष महोदय, बजट में हमने जो नये इनिशिएटिव लिए हैं, मैं उनका पुनः ज़िक्र करने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। माननीय सदस्यों ने यहां बड़े विस्तार से अपनी बातें कही हैं, कुछ अच्छे सुझाव भी दिए हैं, हम आने वाले समय में उन पर भी विचार करेंगे।

श्री आर0के0एस0 द्वारा... जारी

14.03.2020/1655/RKS/एच.के.-1

मुख्य मंत्री... जारी

यह ठीक है कि कुछ विषयों पर हमें चिंता करने की आवश्यकता है और इसके लिए हमारा सामूहिक चिंतन होना चाहिए। ड्रग्स की बढ़ती प्रवृत्ति को राकने के लिए हमें और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। वर्ष 2019-20 में हत्या के 70 अभियोग, वर्ष 2017 में 99 और वर्ष 2018 में 99 से कम अभियोग दर्ज हुए हैं। वर्ष 2018 में महिलाओं से छेड़छाड़ के 515 अभियोग पंजीकृत हुए जोकि वर्ष 2019 में घटकर 498 रह गए। वर्ष 2018 में चोरी से संबंधित 708 मामले दर्ज हुए जिनकी संख्या वर्ष 2019 में घटकर 477 हो गई। वर्ष 2018 में सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित 3118 मामले दर्ज हुए जिनकी संख्या वर्ष 2019 में घटकर 2897 हो गई। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2019 में बलात्कार से संबंधित 358 मामले दर्ज हुए थे। इसका मतलब यह नहीं समझा जा सकता कि प्रदेश में बलात्कारों की संख्या बढ़ी है। वास्तविकता में बलात्कारों की रिपोर्टिंग में वृद्धि हुई है। इन पंजीकृत अभियोगों में से अधिकतम ऐसे अभियोग हैं जोकि मर्जी से शादी करने की नीयत से घर से भागी हुई नाबालिग होने की अवस्था में कानून के अनुसार बलात्कार की धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। जो हमने नये इनिशिएटिव्स लिए हैं उनमें हमने मीडिया, सोशल मीडिया और आम लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखा

है। जो हमारी सरकार की मूल भावना है, अति पिछड़ा वर्ग है, जिस सैक्टर में काम करने की आवश्यकता है, गरीब है, गांव में रहने वाला आदमी है, बेसहारा आदमी, उम्र दराज आदमी, अनुसूचित जाति और सभी वर्गो के के लिए हमने कई योजनाओं की शुरूआत की है। इस बजट में जो हमने नये इनिशिएटिव्स लिए हैं उनके लिए सोशल मीडिया, इलैक्ट्रोनिक मीडिया, आम जन-मानस, कर्मचारी वर्ग, किसान-बागवान सभी ने अभिनंदन किया है। सीमित साधनों में जो किया जा सकता है उसे करने की हमने पूरी कोशिश की है। इस बजट में जितनी भी योजनाएं हैं ये सभी योजनाएं जनहित में है, समाज के हर वर्ग के लिए है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

14.03.2020/1655/RKS/एच.के.-2

अध्यक्षः इससे पूर्व की मैं आज सदन की बैठक स्थगित करूं, सदन की विभागीय स्थायी समितियों से अपेक्षा है कि वे सत्र के स्थगन के दौरान अनुदान मांगों का बारिकी से अध्ययन करने के बाद अपने-अपने प्रतिवेदन 23 मार्च, 2020 को जब सदन की बैठक पुनः प्रारंभ होगी, प्रस्तुत करेंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि समितियों के सभापति एवं सभी सदस्य गहन रुचि लेकर इस कार्य को सम्पन्न करेंगे और अपनी महत्वपूर्ण संस्तुतियां सरकार को देंगे

अब इस माननीय सदन की बैठक सोमवार 23 मार्च, 2020 के 02:00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-17004 **यशपाल शर्मा**
दिनांकः14 मार्च, 2020 **सचिव**